विषय-वस्तु की सारणी

रक्षा मंत्रालय के विभाग एवं संगठन.....02

रक्षा विभाग.....03

समारोह, सम्मान एवं पुरस्कार.....07

राष्ट्रीय कैडेट कोर.....11

सीमा सड़क संगठन.....21

भारतीय तटरक्षक बल.....25

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं.....38

रक्षा विभाग के अन्य संगठन.....43

विदेशों के साथ रक्षा सहयोग.....52

सरलीकरण, विकेंद्रीकरण तथा कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में पहलें.....73

रक्षा उत्पादन विभाग.....88

सैन्य कार्य विभाग.....118

भारतीय सेना.....119

भारतीय नौसेना.....147

भारतीय वायु सेना.....168

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग.....182

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण विभाग.....197

महिला सशक्तीकरण एवं कल्याण.....210

रक्षा मंत्रालय के अधीन विभाग और संगठन

स्वतंत्रता के बाद, रक्षा मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के प्रभार में बनाया गया था और प्रत्येक सेना को अपने स्वयं के कमांडर-इन-चीफ के अधीन रखा गया था। 1955 में, कमांडर-इन-चीफ का नाम बदलकर थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष कर दिया गया। नवंबर 1962 में, रक्षा उपकरणों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी।

नवंबर, 1965 में , रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाओं की नियोजन और निष्पादन के लिए रक्षा आपूर्ति विभाग बनाया गया था। इन दोनों विभागों को बाद में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। 2004 में, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया। 1980 में, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग बनाया गया था। 2004 में, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। 2019 में, संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुविधाजनक बनाने और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सैन्य मामलों के विभाग नामक एक नया विभाग बनाया गया था।

रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और अतिरिक्त रूप से मंत्रालय में पांच विभागों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है।

मंत्रालय के विभाग

(क) रक्षा सचिव की अध्यक्षता में रक्षा विभाग (डीओडी) रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसद से संबंधित मामलों, विदेशों के साथ रक्षा सहयोग और सभी रक्षा संबंधी गतिविधियों के समन्वय से संबंधित है।

रक्षा विभाग के संगठन

(ख) सैन्य कार्य विभाग (डीएमए) चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की अध्यक्षता में इसके सचिव के रूप में अधिप्राप्ति, प्रशिक्षण और सेवाओं के लिए स्टाफिंग में तालमेल को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यों को देखता है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग और स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन को सुकर बनाना भी इस विभाग का अधिदेश है।

सैन्य कार्य विभाग के संगठन

(ग) **रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी)** सचिव की अध्यक्षता में हैं और यह रक्षा उत्पादन, आयातित स्टोरों, उपकरणों और पुर्जों के स्वदेशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) की विभागीय उत्पादन इकाइयों की योजना और नियंत्रण से संबंधित मामलों को देखता है।

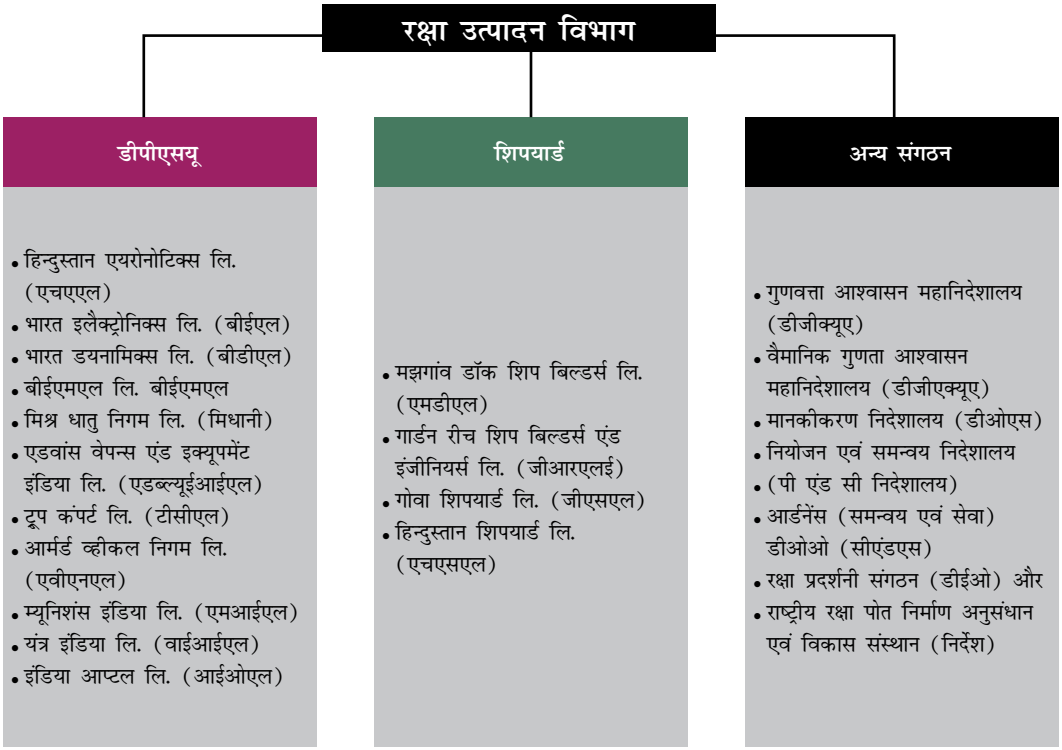

रक्षा उत्पादन विभाग के संगठन

(घ) **रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीआरडीओ)** का नेतृत्व एक सचिव डीडी आरएंडडी और अध्यक्ष, डीआरडीओ द्वारा किया जाता है। इसका कार्य सरकार को सैन्य उपकरणों और संभारिकी के वैज्ञानिक पहलुओं और सेनाओं के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास योजनाओं के निर्माण पर सलाह देना है।

डीआरडीओ में 60 प्रयोगशालाएं / यूनिट शामिल हैं

(ड़) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) के प्रमुख एक सचिव हैं और यह भूतपूर्व सैनिकों के सभी पुनर्वास, कल्याण और पेंशन संबंधी मामलों को देखता है।

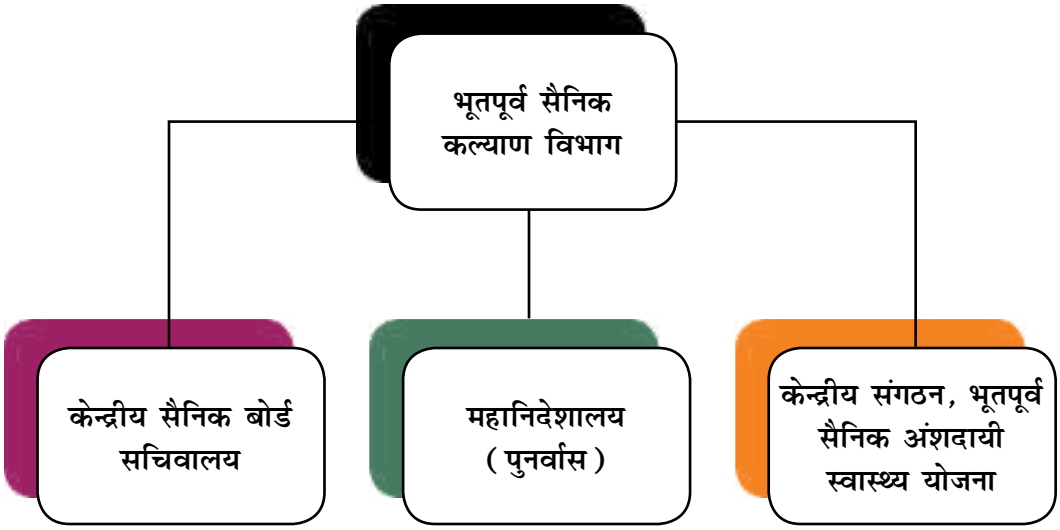

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के संगठन

***

रक्षा विभाग

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE

समारोह, सम्मान और पुरस्कार

गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। 2019-2020 के दौरान आयोजित समारोहों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह

स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत लाल किले में स्कूली बच्चों के गायन समूह द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में देशभक्ति के गीतों के गायन के साथ हुई। तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

इसके बाद, प्रधान मंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ सेना बैंड ने राष्ट्रगान बजाया। इस अवसर पर इक्कीस तोपों की सलामी दी गई। बाद में, दिन के दौरान, राष्ट्रपति ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

वीरता पुरस्कारों की घोषणा स्वतंत्रता दिवस-2019 पर की गई

विजय दिवस

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर समारोह

प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी, 2020 की सुबह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।

गणतंत्र दिवस परेड, 2020

राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील के राष्ट्रपति थे।

49 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेता बच्चों ने सेना की सजी-धजी जीपों में बैठकर परेड में भाग लिया। परेड के अन्य आकर्षणों में राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की झांकी और स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे। परेड में 22 झांकियां और स्कूली बच्चों की 4 झांकियां शामिल थी। परेड का समापन भारतीय वायु सेना के प्रभावशाली फ्लाई पास्ट के साथ हुआ।

गणतंत्र दिवस, 2020 पर वीरता सेवा पुरस्कारों की घोषणा

शौर्य चक्र	• कुल –9 • मरणोपरांत –4
बार टू सेना मेडल (वीरता)	• कुल –4 • मरणोपरांत –0
वायुसेना मेडल (वीरता)	• कुल –116 • मरणोपरांत –9

गणतंत्र दिवस, 2020 पर प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा

परम विशिष्ठ सेवा मेडल	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	अति विशिष्ठ सेवा मेडल
कुल – 28 मरणोपरांत – 0	कुल – 4 मरणोपरांत – 0	कुल – 53 मरणोपरांत – 0

युद्ध सेवा मेडल	बार टू सेना मेडल/ नौसेना मेडल / वायु सेना मेडल
कुल – 10 मरणोपरांत – 0	कुल – 5 मरणोपरांत – 0

सेना मेडल/ नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल (कार्य को समर्पित)	बार टू विशिष्ट सेवा मेडल	विशिष्ट सेवा मेडल
कुल – 57 मरणोपरांत – 1	कुल – 0 मरणोपरांत – 0	कुल – 123 मरणोपरांत – 0

समापन समारोह

'समापन समारोह' एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है, जिसका अभ्यास सैनिकों द्वारा सूर्यास्त के समय युद्ध से हटने के समय किया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में इकट्ठे हुए सैनिकों के प्रस्थान को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का उल्लेख करता यह समारोह 29 जनवरी, 2020 को विजय चौक पर आयोजित किया गया था। इस समारोह में राज्य और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) बैंड के साथ तीनों सेनाओं के बैंड ने भाग लिया। समारोह का समापन राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन और इंडिया गेट को रोशन करने के साथ हुआ।

शहीद दिवस समारोह

राष्ट्रपति ने 30 जनवरी, 2020 को राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्वाह्न 11 बजे दो मिनट का मौन रखा गया।

***

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना एनसीसी अधिनियम, 1948 के अनुसार हुई। एनसीसी राष्ट्र के युवाओं को प्रतिबद्धता की समझ, समर्पण, आत्म-अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है ताकि वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बनें। एनसीसी का आदर्श वाक्य ''एकता और अनुशासन'' है।

30 सितंबर, 2019 को नामांकित कैडेट संख्या का विंग-वार आवंटन

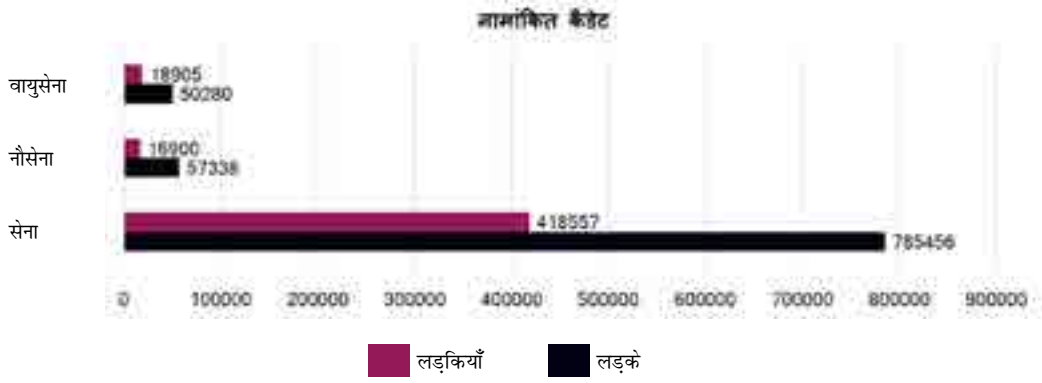

आज की तारीख में एनसीसी में कुल 17644 संस्थान शामिल हैं, जिसमें देश भर के 12401 स्कूल और 5243 कालेज शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त, 2017 को एक एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, 8 एनसीसी आर्मी यूनिट, 2 एनसीसी नेवल यूनिट और 1 एनसीसी एयर यूनिट को चौथे चरण में स्थापित के लिए मंजूरी दी गई है। अभी स्थापना का काम चल रहा है। इससे एनसीसी इकाइयों की संख्या बढ़कर 825 और कैडेटों की संख्या 14,60,000 हो जाएगी।

प्रशिक्षण

संस्थागत प्रशिक्षण

संस्थागत प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम के भाग के रूप में कैडेटों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार करना शामिल है। प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

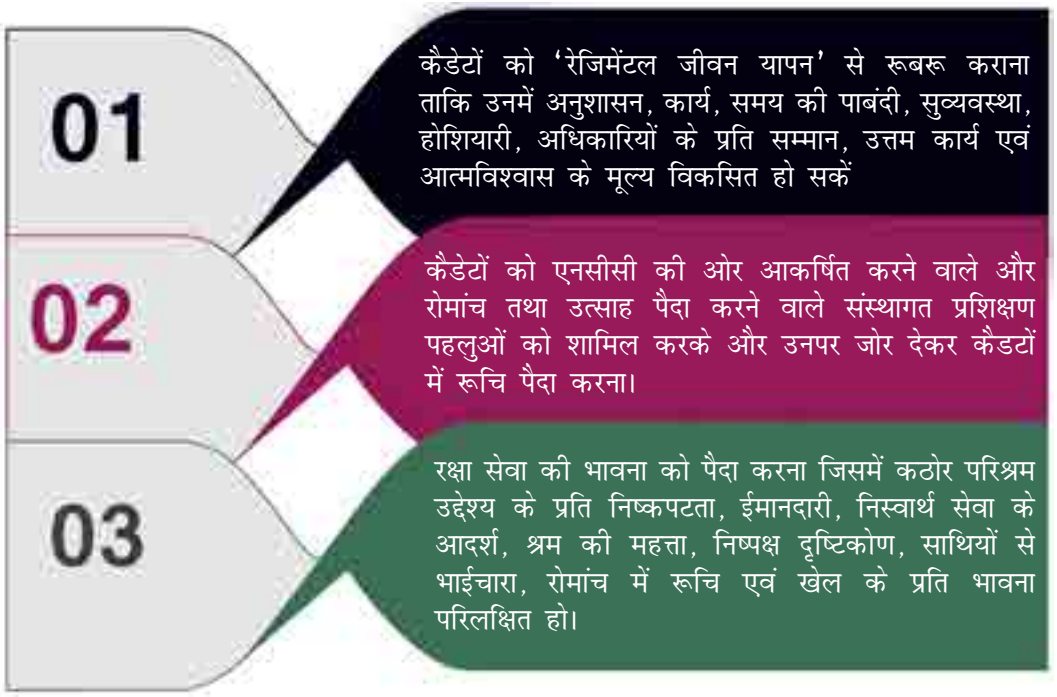

शिविर प्रशिक्षण

कैडेटों को शिविर जीवन के उत्साह से अवगत कराया जाता है, जहां वे संस्थागत प्रशिक्षण में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं। नामांकन की अवधि के दौरान जूनियर डिवीजन/जूनियर विंग (जेडी/जेडब्ल्यू) कैडेटों के लिए कम से कम एक शिविर में भाग लेना और सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग (एसडी/एसडब्ल्यू) कैडेटों के लिए न्यूनतम दो शिविरों में भाग लेना अनिवार्य है।

(क) वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी): 2019 में, देश भर के विभिन्न स्थानों पर 1633 शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों में लगभग 7,32,363 कैडेटों ने भाग लिया।

(ख) केंद्रीय रूप से आयोजित शिविर (सीओसी): सीओसी निम्न प्रकार के होते हैं

केंद्रीय रूप से आयोजित शिविरों के प्रकार

(ग) **गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी):** गणतंत्र दिवस शिविर हर साल 1 जनवरी से 29 जनवरी तक आर्मी परेड ग्राउंड, दिल्ली कैंट में आयोजित किया जाता है। इस शिविर में पूरे भारत से लगभग 2155 कैडेट और मित्र देशों के लगभग 100-120 कैडेट भाग लेते हैं, जिनके साथ एनसीसी का युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम चल रहा है। 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 2 एनसीसी मार्चिंग दल और 2 एनसीसी बैंड भाग लेते हैं।

(घ) **प्रधान मंत्री की रैली:** एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम प्रधान मंत्री की रैली हर साल 28 जनवरी को आयोजित की जाती है। सभी 17 राज्य एनसीसी निदेशालयों की एनसीसी टुकड़ियाँ मार्च पास्ट में भाग लेती हैं।

पीएम रैली 2019

अन्य प्रशिक्षण

(क) उड़ान प्रशिक्षण

(ख) नौकायन विशेष प्रशिक्षण शिविर

(ग) अटैचमेंट प्रशिक्षण

प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण/एसएसबी प्रशिक्षण

प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है:

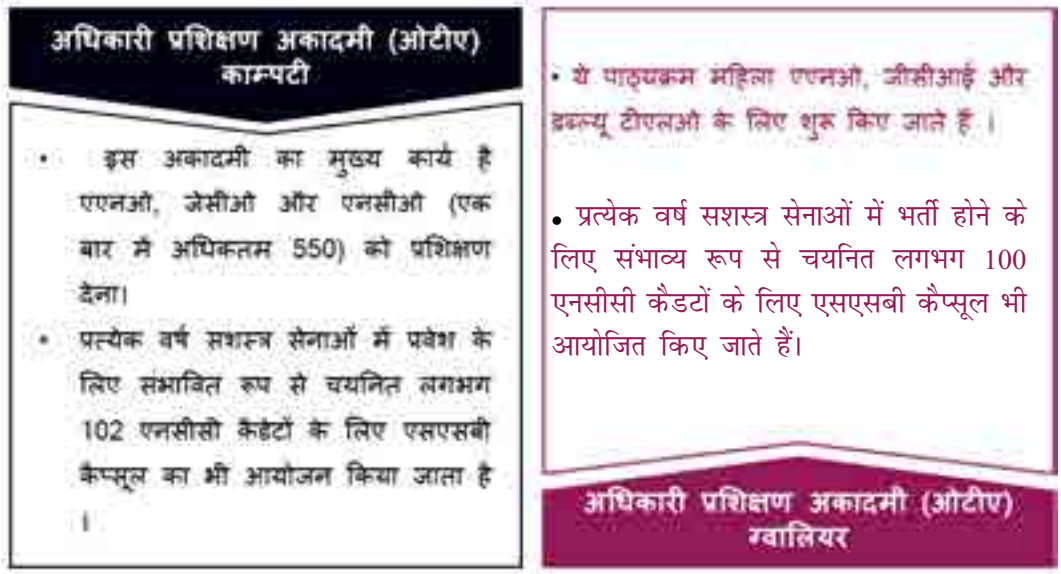

इस वर्ष इन दोनों संस्थानों में क्रमादेशित तरीके से प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षकों की संख्या इस प्रकार है :

(क) एएनओ - 775

(ख) एएनओ के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम - 550

(ग) जेसीओ/एनसीओ के लिए पीआई स्टाफ ओरिएंटेशन - 5000

प्रशिक्षण में सुधार

क. एनसीसी एयर विंग में 110 माइक्रोलाइट विमानों को शामिल किया गया।

ख. विशेष नौकायन कैंपों को 12 स्थान से बढ़ाकर 5 स्थानों तक बढाया गया।

ग. नौसेना द्वारा समुद्र-पारीय परिनियोजन को प्रतिवर्ष 20 कैडेट से बढ़ाकर 30 कैडेट किया गया।

घ. कैडेट रिक्तियों को गणतंत्र दिवस कैंप के लिए 85 से, सेना थल सैनिक कैंप के लिए 151 तक और नेवल नौ सैनिक कैंप कॉ लिए 17 तक बढ़ाया गया।

ड़. सेना से संबंधित प्रशिक्षण को 8000 कैडेट रिक्तियों तक और आईएमए से संबंधित प्रशिक्षण को 130 कैडेट रिक्तियों तक बढ़ाया गया।

च. सितम्बर, 2019 से एक कोर्स में 39 कैडेटों ने ओटीए ज्वाइन किया।

छ. संस्थागत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण संक्षेपण में संशोधन किया गया और एनसीसी में प्रसारित किया गया।

प्रशिक्षण में सुधार

साहसिक और खेल गतिविधियाँ

साहसिक गतिविधियाँ - साहसिक गतिविधियों का उद्देश्य कैडेटों के बीच साहस, खोजपूर्ण जिज्ञासा, ताकत, सहनशक्ति, आत्मविश्वास, टीम भावना, संघ-भाव विकसित करने की भावना पैदा करना है। साहसिक कार्य आधारित गतिविधियाँ कैडेटों को नेतृत्व कौशल सुधारने और उनके चारित्रिक गुणों को बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। संभावित कैडेटों को उच्च स्तर की विशेषज्ञता और प्रवीणता की आवश्यकता वाले अभियानों में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं।

1 पर्वतारोहण अभियान

2 पर्वतारोहण पाठ्यक्रम

3 अखिल भारतीय ट्रेकिंग अभियान

4 कैमल सफारी

5 पैरा बेसिक पाठ्यक्रम

6 पैरा सेलिंग

7 स्लिदरिंग

8 व्हाइट वॉटर राफ्टिंग

9 नौकायन अभियान

10 समुद्री उड़ानें

11 स्कूबा डायविंग

12 अखिल भारतीय नौकायन रेगाटा

क्रियान्वित की गई साहसिक गतिविधियाँ

(क) **पर्वतारोहण अभियान :** इस वर्ष एनसीसी छात्रा कैडेट ने मई- जून, 2019 के दौरान सिक्किम क्षेत्र में माउंट टेनचेनखांग (6010 मीटर) पहले ही चढ़ाई पूरी कर ली है और छात्रों के कैडेट ने सितंबर, 2019 में हिमाचल क्षेत्र में माउंट हनुमान टिब्बा (5982 मीटर) पर चढ़ाई पूरी कर ली।

2019 में सफल पर्वतारोहण अभियान

(ख) **पर्वतारोहण पाठ्यक्रम:** इस वर्ष निम्नलिखित संस्थानों से एनसीसी द्वारा बेसिक, एडवांस, एडवेंचर, निर्देशों की विधि (एमओआई) एवं खोज और बचाव की 426 कैडेट रिक्तियों की सदस्यता ली गई है।

i. अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सम्बद्ध खेल संस्थान, मनाली।

ii. नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (एनआईएम), उत्तरकाशी।

iii. हिमालय पर्वतारोहण संस्थान (एचएमआई), दार्जिलिंग।

iv. जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम (जम्मू-कश्मीर)।

v. राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश

(ग) **नौकायन अभियान :** प्रत्येक एनसीसी निदेशालय 10 से 12 दिनों की अवधि के लिए न्यूनतम एक नौकायन अभियान चलाता है, जिसमें कुल 400 से 500 किलोमीटर की दूरी तय की

जाती है। प्रत्येक निदेशालय के 40 से 60 कैडेट इस आयोजन में भाग लेते हैं। इन अभियानों के दौरान, कैडेट दूरस्थ तटीय गांवों में सामाजिक एजेंडा और स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं। इस वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर पूर्व क्षेत्र निदेशालय के हत्सिन नौकायन अभियान ने लिम्का बुक आफ रिकाडर्स में प्रवेश किया।

एनसीसी के हत्सिन नौकायन अभियान ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है।

खेल

सभी एनसीसी निदेशालयों के एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आयोजित की जाने वाली कुछ प्रमुख खेल गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

प्रमुख खेल गतिविधियाँ

यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (वाईईपी)

वर्तमान में युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम, बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मालदीव, नेपाल, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका और वियतनाम को शामिल करने के लिए दस मित्र देशों के साथ चलाया जा रहा है, ताकि प्रतिभागियों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके और एक-दूसरे के सामाजिक-आर्थिक संबंधों, सांस्कृतिक वास्तविकताओं की सराहना की जा सके और विदेशों में हमारे राष्ट्र की छवि को पेश करने के लिए वे सद्भावना दूत के रूप में कार्य करें। वाईईपी ने 157 भारतीय एनसीसी कैडेटों और 167 विदेशी कैडेटों के आदान-प्रदान सहित दस मित्र देशों के साथ सफलतापूर्वक संचालन किया है।

वाईईपी विवरण

समाज सेवा और सामुदायिक विकास (एसएससीडी) कार्यक्रम

सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियों में फिट इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, जल शक्ति , नशा विरोधी रैली, कैंसर जागरूकता, आपदा राहत, रक्तदान और टीकाकरण,

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ , एड्स जागरूकता, नेत्रहीन की देखभाल, महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता , सड़क सुरक्षा एवं अनुशासन , योग दिवस, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास जागरूकता और इसी तरह के अन्य प्रासंगिक समकालीन सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। एसएससीडी गतिविधियों को अब एनसीसी कैडेटों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

वर्ष के लिए एसएससीडी कार्य योजना के भाग के रूप में, निम्नलिखित दिशानिर्देश भी प्रसारित किए गए हैं :

एसएससीडी कार्य योजना के लिए दिशानिर्देश

भारत सरकार के मिशन

क. शौचालय सहित स्वच्छता और स्वच्छता जागरूकता के साथ महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण के आधार पर एनसीसी कैडेटों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था।

ख 150 वीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान कुल आठ स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किए गए, जिसमें 45 लाख से अधिक कैडेट शामिल हुए और तीन करोड़ नागरिक प्रभावित हुए। अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियों को क्रमादेशित तरीके से आयोजित किया गया है:

i. 3600 गांवों/झुग्गियों और 4300 केंद्रीय पार्कों/प्रतिमाओं की जिम्मेदारी उठाना।

ii. स्कूलों/कॉलेजों, अस्पतालों, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों, समुद्र तटों और जल निकायों में स्वच्छता अभियान।

iii. रैलियों, बैनर प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, डोर-टू-डोर विजिट, लेक्चर/सेमिनार और प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनता को संगठित करने सहित जन स्वच्छता जागरूकता अभियान।

iv. अपनाए गए गांवों/ झुग्गियों में भौतिक सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ओडीएफ और कम्पोस्ट पिट के मुद्दों को संबोधित किया गया ।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधनः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के संचालन पर प्रधान मंत्री के निदेशों के एक भाग के रूप में , एनसीसी ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 सितंबर से 27 अक्टूबर, 2019 तक अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया, जिसमें 9 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों ने मुख्य रूप से 27 अक्टूबर, 2019 तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और इसके वास्तविक निपटान पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्साहपूर्वक विभिन्न जागरूकता और स्वच्छता कार्यक्रमों में भाग लिया। अखिल भारतीय स्वच्छता साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया , जिसका समापन माननीय रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में इंडिया गेट, नई दिल्ली में हुआ। संबंधित इलाकों में नियमित आधार पर जागरूकता के लिए तख्तियों के साथ एनसीसी कैडेटों द्वारा स्थानीय फुट पुलिसिंग करने के लिए कई राज्य निदेशालयों द्वारा 'नो प्लास्टिक यूज' को एक सामाजिक विषय के रूप में भी लिया गया है।

जल शक्ति : एनसीसी ने जल संरक्षण पर एक पहल 'जल शक्ति' को बड़े पैमाने पर आयोजित किया है। संबंधित इलाकों में नियमित आधार पर जागरूकता के लिए तख्तियों के साथ एनसीसी कैडेटों द्वारा स्थानीय फुट पुलिसिंग करने के लिए कई राज्य निदेशालयों द्वारा 'जल शक्ति/जल संरक्षण' को एक सामाजिक विषय के रूप में भी लिया गया है। इन जल संरक्षण कार्यक्रमों में कुल 3,25,780 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया है।

***

सीमा सड़क संगठन

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सशस्त्र बलों की सड़क अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। मई 1960 में दो परियोजनाओं के साथ परिचालन शुरू करते हुए अब यह बढ़कर 18 परियोजनाओं तक पहुंच गया है।

परियोजना विवरण

बीआरओ ने खराब मौसम की हालातों में कठिन, अलग-थलग और दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करने वाली एकमात्र सड़क निर्माण एजेंसी होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है।

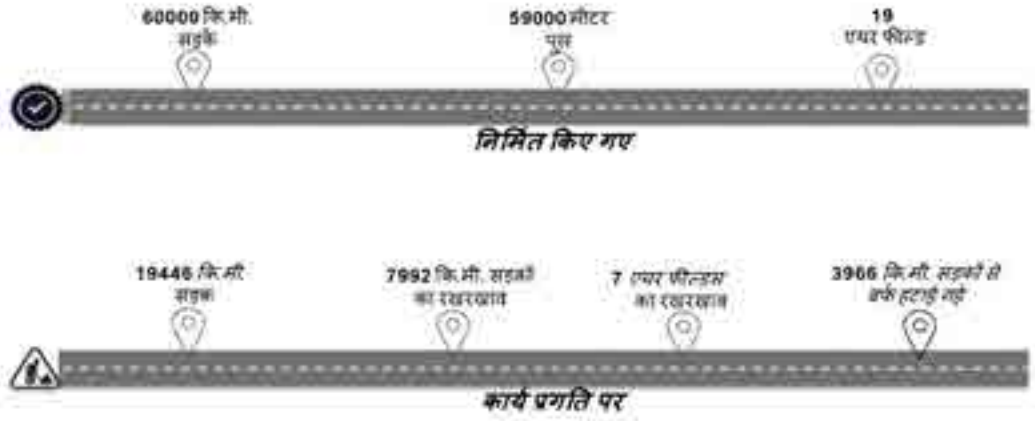

बीआरओ की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. भारत-चीन सीमा सड़को (आईसीबीआर) को पूरा करना

बीआरओ को निर्माण/विकास के लिए 61 सड़कें (3323 किलोमीटर) सौंपी गई हैं। अब तक 36 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पूरी की गई सड़क की लंबाई 2501 किमी (75%) है और 3296 किमी (99%) कनेक्टिविटी हासिल की गई है।

2. बीआरओ में ईपीसी मोड को अपनाना

29 अगस्त, 2017 को रक्षा मंत्रालय द्वारा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट (ईपीसी) मोड के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई थी। तदनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले सभी कार्य ईपीसी मोड के माध्यम से निष्पादित किए जा रहे हैं। ईपीसी मोड के माध्यम से आउटसोर्स किए जाने वाले 43 कार्यों में से डीपीआर तैयार करने के लिए 31 संविदाएँ की गई है।

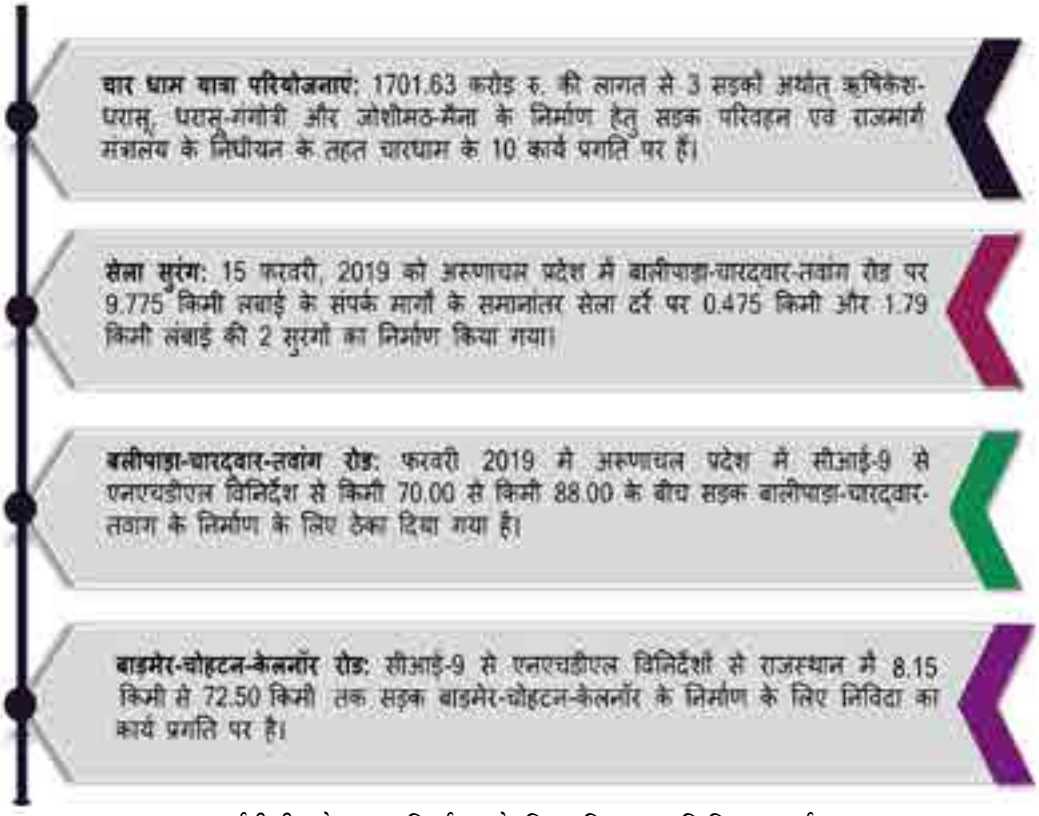

ईपीसी मोड पर निर्माण के लिए दिए गए सिविल कार्य

सेला सुरंग परियोजना

3. ब्रह्मपुत्र में अंडरवाटर टनल

बीआरओ ने ब्रह्मपुत्र नदी के पार सड़क और रेल संपर्क के लिए प्रस्तावित अंडरवाटर टनल के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करना शुरू कर दिया है। व्यवहार्यता और डीपीआर 24 महीनों में पूरा किए जाने की उम्मीद है।

4. सड़क निमू-पदम-दारचा (एनपीडी)

शिंकुनला दर्रे से होकर कारगिल के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्राप्त की गई है। मौजूदा पदम कारगिल रोड को वित्त वर्ष 2019-20 में पदम में एनपीडी रोड से जोड़ा गया है।

5. घाटियाबगड़ रोड - लिपुलेख

79 किलोमीटर लंबी सड़क में से 72 किलोमीटर लंबाई की कनेक्टिविटी हासिल कर ली गई है। सड़क को 2020 में जोड़ने और 2022-23 तक पूरा करने की योजना है। उत्तराखंड के तवाघाट से मानसरोवर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भी यह सड़क महत्वपूर्ण है।

6. पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ और उद्घाटन किया गया

दिसंबर, 2019 तक अलग-अलग विस्तार वाले 3476 मीटर लंबाई के 28 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुलों का विवरण नीचे दिया गया है:

सासरी पुल: 15 नवंबर 2019 को अरूणाचल प्रदेश राज्य में एनएच 13 पर रानाघाट- मेबो -डाम्बक-बोमजीर पर किमी 594.945 कि.मी. पर 200 मीटर लंबा पुल।

कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु: 21 अक्टूबर 2019 को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में डार्बुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (डी-एसडीबीओ) रोड पर 150.40 कि.मी. पर 426 मीटर लंबा ट्रिपल डबल रिइनफोर्सड् एकस्ट्रा वाइड बेलीब्रिज।

***

भारतीय तटरक्षक बल

वर्ष 1977 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक्स भारतीय नौसेना 02 जहाजों और एक्स कस्टम्स 5 पेट्रोल बोट्स के बेड़े के साथ 'तटरक्षक बल' की स्थापना को अनुमोदित किया था।

संसद द्वारा पारित भारतीय तटरक्षक अधिनियम, 1978 द्वारा 18 अगस्त, 1978 को संघ की सशस्त्र सेना के रूप में भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी।

संगठन

भारतीय तटरक्षक बल (डीजीआईसीजी) के महानिदेशक, तटरक्षक संगठन के प्रमुख होते हैं जिनके द्वारा नई दिल्ली स्थित तटरक्षक मुख्यालय (सीजीएचक्यू) से इस संगठन का संपूर्ण नियंत्रण और संचालन किया जाता है।

प्रभावी कमांड और नियंत्रण के लिए भारतीय समुद्रवर्ती क्षेत्र को पांच तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनके मुख्यालय गांधीनगर, मुंबई, चौन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में है।

भारतीय तटरक्षक बल संगठन

भारतीय तटरक्षक बल को प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र में तटीय सुरक्षा, डीप-सी फिशिंग के प्रवर्तन, मानीटरिंग और निगरानी, समुद्रवर्ती अनुसंधान और बचाव कार्य एवं समुद्री ऑयलस्पिल प्रतिक्रिया उपायों की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह तटीय और समुद्री बार्डर के लिए प्रमुख आसूचना एजेंसी भी है।

मौजूदा बल संख्या

मौजूदा बल संख्या

विस्तृत 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' (ईईजेड) निगरानी

भारतीय तटरक्षक जहाज एवं विमानों को तटीय राज्यों की समुद्रवर्ती निगरानी के लिए तैनात किया जाता है। वर्ष 2019 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मालदीव के ईईजेड में पांच बार विस्तारित ईईजेड की तैनाती की गई थी। तीन आईसीजी जहाजों और दो विमानों को मालदीव के ईईजेड में तैनात किया गया था।

तटीय सुरक्षा

तटीय सुरक्षा अभ्यास : भारतीय तटरक्षक बल भारतीय नौसेना (आईएन) के साथ समन्वय करके संपूर्ण तटरेखा क्षेत्र में गश्त एवं निगरानी करता रहा है। वर्ष 2009 से, कुल 196 तटीय सुरक्षा अभ्यास किए गए हैं।

तटीय सुरक्षा आपरेशन्स : तटीय सुरक्षा पर सतत रूप से जोर देने के साथ वर्ष 2009 से, सभी हितधारकों के साथ समन्वय से कुल 419 तटीय सुरक्षा आपरेशन्स किए गए हैं।

सामुदायिक परस्पर संपर्क कार्यक्रम :

वर्ष 2009 से, भारतीय तटरक्षक बल ने सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर मछुआरों को जागरूक करने और आपदा अलर्ट ट्रांसमीटर्स, लाइफब्वायज और लाइफ जैकेट्स आदि जैसे जीवन रक्षक उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए कुल 8240 सामुदायिक परस्पर संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

बोर्डिंग आपरेशन्स :

वर्ष 2009 से, भारतीय तटरक्षक पोतों द्वारा कुल 2,39,724 बोर्डिंग आपरेशन्स किए गए हैं जिसमें से कुल 42,911 बोर्डिंग आपरेशंस वर्ष 2019 में किए गए हैं।

समुद्रवर्ती पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण :

समुद्रवर्ती पुलिस कार्मिकों के प्रोफेशनल कौशल में वृद्धि करने की दृष्टि से भारतीय तटरक्षक बल ने अब तक 4792 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है।

महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

उच्च स्तरीय बैठकें (एचएलएम)

10

उच्च स्तरीय बैठकें

- **आईसीजी द्वारा आयोजित 2**
- **आईसीजी ने 8 एचएलएम में भाग लिया**

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उच्च स्तरीय बैठक

[illegible]	[illegible]	[illegible]
भारतीय तटरक्षक बल कोच्चि	आस्ट्रेलियाई सीमा बल	दिनांक 9 मई, 2019 को द्विपक्षीय सहयोग पर द्वितीय एचएलएम
बांग्लादेश तटरक्षक बल, ढाका	भारतीय तटरक्षक बल	दिनांक 16-17 सितम्बर, 2019 के दौरान दोनों तटरक्षक बलों के बीच समझौता-ज्ञापन के प्रावधानों के तहत पांचवी एचएलएम
जापान तटरक्षक बल टोकियो	भारतीय तटरक्षक बल	दिनांक 21-25 जनवरी, 2019 के दौरान 18वीं एचएलएम
कोरिया तटरक्षक बल इंचियोन	भारतीय तटरक्षक बल	दिनांक 26 मार्च, 2019 के दौरान 10वीं एचएलएम
म्यांमार नौसेना म्यांमार	भारतीय तटरक्षक बल	दिनांक 6-9 मई, 2019 के दौरान म्यांमार एजेंसियों के साथ आईसीजी का द्विपक्षीय सहयोग
भारतीय तटरक्षक बल, नई दिल्ली	श्रीलंका तटरक्षक बल (एसएलसीजी)	दिनांक 20 अगस्त, 2019 के दौरान भारतीय तटरक्षक बल और एसएलसीजी के बीच चौथी एचएलएम
वियतनाम तटरक्षक बल, हनोई	भारतीय तटरक्षक बल	दिनांक 25-27 अप्रैल, 2019 को तीसरी एचएलएम
सिंगापुर	भारतीय तटरक्षक बल	19-22 मार्च, 2019 को आरईसीएएपी सिंगापुर की तेरहवीं शासन परिषद बैठक
श्रीलंका तटरक्षक बल, कोलंबो	भारतीय तटरक्षक बल	दिनांक 7-11 अक्तूबर, 2019 के दौरान एशियन तटरक्षक बल एजेंसियों के प्रमुख की 15वीं बैठक
टोकियो, जापान	भारतीय तटरक्षक बल	द्वितीय तटरक्षक बल वैश्विक बैठक

विदेशी जहाजों का भारत का दौरा

3

विदेशी जहाजों का दौरा

20-23 मार्च, 2019 (पोर्ट ब्लेयर)

- जहाज – सैयद नजरूल, बांग्लादेश तटरक्षक बल
- एमओयू के प्रावधानों के तहत आईसीजी के साथ परस्पर प्रोफेशनल विचार-विमर्श

13-16 मई, 2019 (पोर्ट ब्लेयर)

- जहाज – केएन तंजुंग दातू
- संयुक्त अभ्यास

23-27 अगस्त, 2019 (चैन्नई)

- जहाज – स्ट्राटन, यूनाइटेड स्टेट्स तटरक्षक बल
- प्रोफेशनल पारस्परिक विचार-विमर्श और संयुक्त अभ्यास

विदेशी बन्दरगाहों के लिए आईसीजी पोतों की समुद्रपार तैनाती

भारतीय तटरक्षक जहाजों को विदेशों में समय-समय पर विदेशी तटरक्षक और क्षेत्र में अन्य समुद्री एजेंसियों के साथ संवाद के लिए तैनात किया जा रहा है। जनवरी, 2019 से अब तक कुल 6 आईसीजी पोतों ने 15 देशों का दौरा किया है।

खोज और बचाव (एसएआर) अभियान

समुद्री वातावरण

मुंबई में 7-9 जनवरी, 2019 को आइसीजी द्वारा 7वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास (एनएटीपीओएलआरईएक्स-VII) आयोजित किया गया था। इस अभ्यास के दौरान, 19 देशों के 24 विदेशी प्रतिनिधिमंडल और केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों के 75 प्रतिनिधियों, मुख्य बंदरगाहों, गैर-महत्वपूर्ण बंदरगाहों, तेल शोधन संबंधी एजेंसियों और समुद्र तट पर तेल संस्थापनाओं ने अभ्यास में भाग लिया। जनवरी 7-8, 2019 को एक कार्यशाला और टेबल टॉप अभ्यास का भी आयोजन किया गया था।

''स्वच्छ भारत अभियान'' हेतु सरकार के जारी प्रयासों हेतु, भारतीय तटरक्षक बल ने 21 सितम्बर, 2019 को सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय तटवर्ती क्लीन अप दिवस-2019 (आईसीसी-2019) का आयोजन किया। आईसीसी-2019 में कुल 19,479 स्वयंसेवकों ने भाग लिया जिसके फलस्वरूप 71,220 कि.ग्रा. समुद्री कचरा एकत्र किया गया।

मात्स्यिकीय सुरक्षा

तटरक्षक बल ने जनवरी, 2019 से भारत के समुद्री क्षेत्र (एमजेडआई) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत 108 विदेशी क्रू सहित 21 विदेशी फिशिंग नौकाओं को पकड़ा है।

तटरक्षक बल द्वारा मत्स्य नौकाओं/मछुआरों का देश प्रत्यावर्तन विदेश मंत्रालय, संबंधित देशों में भारतीय उच्च आयोग, राज्य मत्स्य विभागों और जिला प्रशासन के साथ गहन संपर्क द्वारा सीधे समन्वित किया जाता है।

जनवरी, 2019 से देश प्रत्यावर्तन का विवरण इस प्रकार है :

देश प्रत्यावर्तन	जनवरी, 2019 से अब तक	
	नौका	क्रू
श्रीलंका से भारतीय फिशिंग बोट और मछुआरे	38	45
पाकिस्तान से भारतीय फिशिंग बोट और मछुआरे	शून्य	200
भारत से श्रीलंका फिशिंग बोट और मछुआरे	शून्य	50

आसूचना और तस्करीरोधी और नारकॉटिक्स नियंत्रण (एएसएनसी)

आसूचना इनपुट के आधार पर, आईसीजी ने विभिन्न हितधारकों और पड़ोसी देशों के तटरक्षक बलों के समन्वय में वर्ष 2019-20 में 1862.6 किलोग्राम नारकॉटिक्स को सफलतापूर्वक पकड़ा है जिसकी लागत 2160 करोड़ रुपए (खुले बाजार में) है। इसका विवरण इस प्रकार है:

500 करोड़ रुपए की 100 किग्रा हेरोइन	1000 करोड़ रुपए की 196 किग्रा हेरोइन	300 करोड़ रुपए की 1160 किग्रा केटामाइन	185 करोड़ रुपए की 371.6 किग्रा मेथाकॉलन	175 करोड़ रुपए की 35 किग्रा हेरोइन
26 मार्च, 2019	21 मई, 2019	21 सितम्बर, 2019	20 दिसम्बर, 2019	6 जनवरी, 2020
सीजीआरएचक्यू (एनडब्ल्यू)		सीजीआरएचक्यू (एएंडएन)		

आईसीजी द्वारा पकड़े गए अवैध पदार्थ

भारतीय तटरक्षक बल और सिविल प्राधिकरणों के बीच सहयोग

फिशिंग बोट गरीब नवाज ऑफ पिपावाव बंदरगाह को अग्निशमन सहायता : 10 फरवरी, 2019 को फिशिंग बोट 'गरीब नवाज' पर आग लगने की घटना हुई जब यह नौका सेवाई बेत में स्थानीय दरगाह के लिए एक धार्मिक यात्रा के लिए आए 150 स्थानीय ग्रामीणों को उतार कर शियाल बेट द्वीप, पिपावाव लंगरगाह पर खड़ा था।

घटना की सूचना प्राप्त होने पर भारतीय तटरक्षक बल के जहाज पिपावाव को तुरंत सहायता के लिए तैनात किया गया। आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

भारतीय तटरक्षक बल के जहाज द्वारा फिशिंग बोट 'गरीब नवाज' को सहायता

महासागर अनुसंधान पोत (ओआरवी) सागर संपदा (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वामित्व में) को अग्निशमन सहायता : 15 मार्च, 2019 को समुद्रवर्ती बचाव समन्वयक केन्द्र (एमआरसीसी), मुंबई को न्यू मंगलूर के 37 नाटिकल माइल दक्षिण-पश्चिम दूरी पर ऑनबोर्ड अनुसंधान पोत 'ओआरवी सागर संपदा' जिसमें 46 लोग (36 चालक दल और 16 वैज्ञानिक) सवार थे, पर आग लगने के संबंध में उप महाप्रबंधक, एससीआई लिमिटेड से एक ईमेल प्राप्त हुआ।

इस सूचना के प्राप्त होने पर आईसीजी जहाज विक्रम और सुजय जो पेट्रोल पर थे, को तुरंत संकटग्रस्त पोत की सहायता के लिए पथांतर किया गया और ये जहाज 16 मार्च, 2019 को घटना के स्थान पर पहुंचा। पोत पर सवार सभी 46 लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

आईसीजी ने संकटग्रस्त पोत पर अग्निशमन उपकरणों के साथ अग्निशमन दल भेजा और बहुत कम पहुंच के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के तहत अग्नि पर काबू पाया गया। भारतीय तटरक्षक बल के अग्निशमन दल द्वारा पोत के 8 कंपार्टमेंट्स में सफलतापूर्वक काबू पाया गया और तत्पश्चात आईसीजी दलों ने सबमर्सिबल पंपों से पानी को पोत से बाहर निकाला। तत्पश्चात इस पोत ने सुरक्षा की दृष्टि से आईसीजी जहाजों की निगरानी में न्यू मंगलुरू की तरफ प्रस्थान किया और यह पोत 16 मार्च, 2019 को सुरक्षित न्यू मंगलुर पहुंचा।

अग्निशमन अभियान में आईसीजीएस विक्रम एवं सुजय

फायर ऑनबोर्ड 'एमवी एपीएल एलई हावरे' के लिए अग्निशमन सहायता : 9 अगस्त, 2019 को मास्टर ऑफ एमवी एपीएल एलई हावरे द्वारा एमआरसीसी, मुंबई को दूरभाष से फायर ऑनबोर्ड के संबंध में सूचना दी गई। आईसीजी जहाज संग्राम जो गश्त पर था, को तुरंत आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए घटना के स्थान की तरफ रवाना किया गया।

इसी बीच एमवी एपीएल एलई हावरे के समीप ही दूसरे पोत एमवी नोर्ड कोपेनहेगेन को आग की घटना वाले जहाज की दिशा में रवाना किया गया और इस पोत से अनुरोध किया गया कि जब तक आईसीजीएस संग्राम नहीं पहुंचता तब तक एमवी एपीएल एलई हावरे को आवश्यक सहायता पहुंचाई जाए। आईसीजी जहाज संग्राम 9 अगस्त, 2019 को घटना वाले स्थान पर पहुंचा और इस जहाज से

आग पर काबू पाने के लिए एक्सटर्नल अग्निशमन प्रणाली का उपयोग किया गया। तत्पश्चात इस पोत को सुरक्षित कच्छ की खाड़ी में लाया गया और यह पोत 10 अगस्त, 2019 को मुंद्रा लंगरगाह क्षेत्र पर पहुंचा।

विशाखपट्टणम के पास आफशोर आपूर्ति पोत (ओएसवी) तटीय जगुवार पर आग लगने से आईसीजी द्वारा 29 कार्मिकों को बचाना : 12 अगस्त, 2019 को रिमोट आपरेटिंग स्टेशन (आरओएस) विशाखपट्टणम ने आफशोर आपूर्ति पोत ''कोस्टल जगुवार'' (जिसमें चालक दल के 31 सदस्य सवार थे) से धुंआ निकलने की घटना को नोटिस किया, यह पोत विशाखपट्टणम बंदरगाह के तट पर प्रदूषण अनुक्रिया आपरेशंस का कार्य कर रहा था।

इस पोत का चालक दल आग लगने के पश्चात जहाज से कूद गया। आईसीजीएस रानी रशमोनी ने टग 'सिंधु' और एक पोर्ट यूटिलिटी बोट के साथ समन्वय से ओएसवी 'कोस्टल जगुवार' के 29 चालक दल के सदस्यों को बचाया। बचाए गए घायल चालक दल को विशाखपट्टणम बंदरगाह अस्पताल में भर्ती किया गया था। आईसीजीएस समुद्र पहरेदार ने विशाखपट्टणम बंदरगाह ट्रस्ट टग्स 'सिंधु' और 'कोहिनूर' के साथ अग्निशमन की कार्यवाही शुरू की। निरंतर प्रयासों से अग्नि पर नियंत्रण किया गया था।

आईसीजीएस समुद्र पहरेदार ऑनबोर्ड ओएसवी पर अग्निशमन की कार्यवाही करते हुए

बंगाल की खाड़ी में 'फैनी' तूफान के दौरान आईसीजी द्वारा किए गए प्रयास : आईएमडी ने दिनांक 27 अप्रैल, 2019 को 'फैनी' तूफान के आने की सूचना जारी की। मात्स्यिकी प्राधिकारियों को

मौसम संबंधित चेतावनियों के बारे में बताया गया। वीएचएफ पर चेतावनियों को प्रसारित करना और मछुआरों को बंदरगाहों पर वापस लौटने का परामर्श देने के लिए आईसीजी डोर्नियर और जहाजों को तैनात किया गया था। पूर्वी तट पर सभी यूनिटों को एसएआर और आपदा प्रतिक्रिया के लिए तत्काल रूप से तैयार रहने के लिए तैनात किया गया था।

भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चिकित्सा कैम्प

जेक्सन क्रीक से असहाय पुलिस कार्मिकों को सुरक्षित निकालना : दिनांक 2 जुलाई, 2019 को तूफानी मौसम के दौरान जैक्सन क्रीक से गोलाबारूदों के साथ आईसीजीएस विजीत ने 10 पुलिस कार्मिकों को सुरक्षित निकाला।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में आपदा राहत आपरेशन के लिए आईसीजी प्रयास : तटीय राज्यों में बहुत से बहुत अधिक वर्षा की चेतावनी को जारी करने के परिणामस्वरूप भारतीय तटरक्षक बल जिलों और स्टेशनों को दिनांक 4 अगस्त, 2019 को सिविल प्रशासन को सहायता के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया था।

कुल 53 सीजीडीआरटी को जीवन रक्षक/ बचाव गियर्स के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में भेजा गया और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में एसडीएमए/राज्य प्रशासन द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के अनुसार बारी-बारी से तैनात किया गया था। 4418 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

चक्रवाती तूफान 'क्यार' के दौरान पूर्व-सक्रिय उपाय : कम दबाव के क्षेत्र तैयार होने के संबंध में आईएमडी द्वारा चेतावनी जारी होने के उपरांत, भारतीय तटरक्षक बल ने नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए 21 अक्तूबर, 2019 से कई पूर्व सक्रिय उपायों की शुरूआत की थी।

कुल 1678 मात्स्यिकी नौकाओं को आईसीजी रिमोट आपरेटिंग स्टेशंस (आरओएस) द्वारा बंदरगाह पर सुरक्षित लौटने का मार्ग दिखाया गया था। क्षेत्र की जांच, मत्स्य नौकाओं की लोकेशन का पता लगाने और बंदरगाह पर सुरक्षित वापस लौटने के लिए चेतावनी जारी करने के लिए औसतन 10-12 जहाज और डोर्नियस की छोटी उड़ान शुरू की गई थी। आईसीजी यूनिटों द्वारा 44 मछुआरों को बचाया गया।

चक्रवाती तूफान 'महा' के दौरान पूर्व सक्रिय उपाय : कम दबाव के क्षेत्र तैयार होने के संबंध में आईएमडी द्वारा चेतावनी जारी करने के उपरांत आईसीजी ने मछुआरों को बचाने के लिए 28 अक्तूबर, 2019 से कई पूर्व सक्रिय उपाय शुरू किए।

कुल 20 राहत कैंप आयोजित किए गए थे और 759 लोगों को निचले क्षेत्रों से क्षेत्र प्रशासन द्वारा राहत कैंपों में सुरक्षित लाया गया था। चेतावनी जारी करने, क्षेत्रीय निगरानी करने, फंसे हुए मत्स्य नौकाओं की लोकेशन और सहायता के लिए औसतन 6-8 जहाज और 2-3 डोर्नियर की दैनिक आधार पर तैनाती की गई थी।

चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' के लिए आईसीजी प्रयास : कम दबाव के क्षेत्र तैयार होने के संबंध में मछुआरों की रक्षा के लिए आई सी जी द्वारा चेतावनी जारी करने के परिणाम स्वरूप 5 नवम्बर, 2019 से कई पूर्व सक्रिय उपाय किए गए थे।

148 मछुआरों के साथ 18 मत्स्य नौकाओं को बंदरगाह पर सुरक्षित लौटने के लिए समुद्र में और रिमोट आपरेटिंग स्टेशन (आरओएस) तक आईसीजी यूनिटों द्वारा मार्गदर्शित किया गया था। 60 सिविलियन लेबर एक्स-एमईएस को तटरक्षक बल रिहायसी क्षेत्र, पारादीप में शेल्टर प्रदान की गई थी। चेतावनी जारी करने, फंसे हुए मत्स्य नौकाओं की लोकेशन पता करने और उन्हें सुरक्षित शेल्टर तक सहायता

करने के लिए दैनिक आधार पर औसतन 10-12 जहाजों को तैनात किया गया है और 2-3 डोर्नियर्स की छोटी उड़ान शुरू की गई है।

हितधारकों के साथ बैठक

नमखाना, पश्चिम बंगाल में सीआईपी

***

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं (एएफएमएस)

एएफएमएस, रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को समर्पित, भरोसेमंद और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। फील्ड में तैनात अर्ध-सैन्य संगठनों के कर्मियों और देश के अशांत और सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत अन्य केंद्रीय पुलिस/खुफिया संगठनों और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स (जीआरईएफ) इकाइयों को भी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देश के भीतर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा देखभाल भी प्रदान की जाती है। प्राकृतिक आपदाओं, आपदाओं के दौरान और संक्रियात्मक क्षेत्रों में, यह नागरिक आबादी की भी सेवा करता है।

प्रत्येक चिकित्सा सेवा एक महानिदेशक चिकित्सा सेवा (डीजीएमएस) जो कि लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष के पद के अधीन है। महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (डीजीएएफएमएस), जो सेवा के प्रमुख हैं, रक्षा मंत्रालय के चिकित्सा सलाहकार और चिकित्सा सेवा सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। 132 सशस्त्र सेना अस्पताल हैं। एएमसी, एडीसी, एमएनएस और एमएनसी (एनटी) के प्राधिकृत अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है।

एएफएमएस में प्राधिकृत अधिकारियों की संख्या

टेलीमेडीसिन

वर्तमान में, समुद्र में जीवन और/या अंग को खतरे में डालने वाली चिकित्सा आपात स्थिति, जिसके लिए विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता होती है, को या तो खाली कर दिया जाता है, या जहाज निकटतम बंदरगाह में प्रवेश करके मिशन को छोड़ देता है। कभी-कभी मौसम, वायुयान/नौकाओं की कमी या हताहत होने के कारण निकासी भी असंभव हो जाती है। टेलीमेडिसिन बोर्ड परिचालन प्लेटफार्मों और दूरस्थ तटीय स्थानों पर उपयोग के लिए दूरस्थ स्वास्थ्य देखभाल और निगरानी प्रदान करेगा।

टेलीमेडिसिन अनुबंध पर 22 अप्रैल, 2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद 2021 की शुरुआत तक 107 जहाजों/पनडुब्बियों और दूरस्थ स्थानों पर टेलीमेडिसिन उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

(क) टेलीमेडिसिन (टियर-I) रक्षा बायोइंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रयोगशाला (डीईबीईएल) के साथ आगे की पृथक पोस्टों को रेजिमेंटल सहायता पोस्ट (आरएपी) जोड़ने के लिए रेडियो आधारित टेलीमेडिसिन की योजना बनाई गई है। टेलीमेडिसिन उपकरण अर्थात् पोर्टेबल फिजियोलॉजिकल वाइटल पैरा मॉनिटर (पीपीवीपीएम) के संचालन पर प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

(ख) टेलीमेडिसिन (टियर-II) एचक्यूआईडीएस (एमईडी) आर्मी इंट्रानेट का उपयोग करके उत्तरी कमान में 10 आरएपी से 150 जीएच को जोड़ने वाले दूरस्थ क्षेत्र में टेलीमेडिसिन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डीईबीईएल के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें 150 जीएच पर विशेषज्ञों के साथ इन्फैंट्री बटालियनों में तैनात कर्मियों की वास्तविक समय वीडियो इंटरफेसिंग शामिल थी। इसमें पल्स, बीपी, तापमान, श्वसन दर, रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति (एसपीओ 2) ईसीजी और डिजिटल स्टेथोस्कोप, डर्मा-स्कोप और एयरो-स्कोप से डेटा जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा मापदंडों का वास्तविक परीक्षण भी शामिल है।

(ग) टेलीमेडिसिन (टियर -III) : डीईसीयू, इसरो, अहमदाबाद ने एचक्यू आईडीएस (मेडिकल) के सहयोग से सशस्त्र सेना चिकित्सा इकाइयों को सैटेलाइट संचार के माध्यम से 20 टेलीमेडिसिन नोड प्रदान किए हैं। वर्तमान में सभी नोड कार्यात्मक हैं और सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करते हैं। अतिरिक्त 83 नोड्स के लिए प्राप्त अनुरोध निदेशक डीईसीयू आईएसआरओ को भेजा गया था, जिसमें से 53 अतिरिक्त टेलीमेडिसिन नोड्स को मंजूरी दे दी गई है। सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए अतिरिक्त 53 टेलीमेडिसिन नोड्स की स्थापना के लिए खरीद आदेश दिया गया है। टेलीमेडिसिन नोड्स का सारांश निम्नानुसार है:-

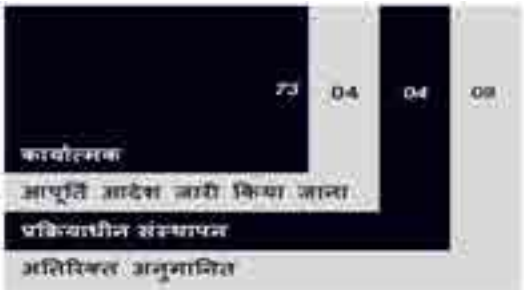

टेलीमेडिसिन नोड्स का सारांश

2019 में प्रगति

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

(क) चिकित्सा शिविर : सेना चिकित्सा कोर, ऑपरेशन सद्भावना के तत्वावधान में जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के दूरदराज के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सा आउटरीच अभियान चलाती है। इसके अलावा, निम्नलिखित अतिरिक्त मल्टी स्पेशिलिटी चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए:

उत्तरी कमान में चिकित्सा कैम्प	दिव्यांग सैनिकों के लिए पहल	सरली में चिकित्सा शिविर का आयोजन	आपरेशन हिमराहत
अविकसित सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्राहकों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए 19 जनवरी, 2019 को जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के ब्लाक गुल में एक बहु-विशिष्ट चिकित्सा-शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 4652 सिविलियनों का उपचार किया गया।	असम के चिक्यू 51 उप क्षेत्र के तत्वाधान में एक दिव्यांग सैनिक सम्मेलन सह रैली का आयोजन किया गया। दिव्यांग पूर्व सैनिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए शिविर स्थल पर कृत्रिम अंग उप केन्द्र का विस्तारित रूप स्थापित किया गया था।	'आपरेशन समरीटन' परियोजना के तहत 23 फरवरी, 2019 को सरली में 456 फील्ड अस्पताल द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 126 चिकित्सा और 29 दंत रोगियों की जांच की गई और 34 प्रयोगशाला परीक्षण किए गए।	28 दिसम्बर, 2018 को भारी अप्रत्याशित बर्फबारी की वजह से नाथुला (सिक्किम) जाने वाले 2900 पर्यटक फंस गए थे। 'आपरेशन हिमराहत' के भाग के रूप में 317 फील्ड अस्पताल की मेडीकल टीमों ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और जीवन रक्षक उपचार प्रदान किया।

अतिरिक्त मल्टी स्पेशियालिटी चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए

(ख) : वर्ष 2018 के लिए **सशस्त्र बलों के सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल** के लिए रक्षा मंत्री ट्राफी माननीय रक्षा मंत्री द्वारा कमान अस्पताल वायु सेना बैंगलोर (सीएचएएफबी) को प्रदान की गई।

सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पतालों के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी

अनुसंधान गतिविधियाँ

नई एएफएमआरसी परियोजनाएं : फरवरी, 2019 में पुणे में आयोजित एएफएमआरसी की 57वीं बैठक के दौरान 129 नई एएफएमआरसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। नई और पहले से चल रही दोनों परियोजनाओं को कुल 8,35,00,000/- रुपये की अनुसंधान निधि का आवंटन किया गया।

पूर्ण एएफएमआरसी परियोजनाएं : 1 अक्टूबर, 2018 से 30 सितम्बर, 2019 की अवधि के दौरान 76 एएफएमआरसी परियोजनाएं पूरी की गई ।

समझौता ज्ञापन : एएफएमएस ने एम्स, नई दिल्ली पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया।

अनुसंधान गतिविधियों का विवरण

पहल

(क) **आईएनएचएस अश्विनी में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना 'बी' का कार्यान्वयन:** आईएनएचएस अश्विनी में मनोरोग सुविधा की जनशक्ति में वृद्धि के लिए सहायता अनुदान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) की योजना 'बी' (जनशक्ति विकास योजना) के तहत स्वीकृत किया गया है।। एम फिल मनोरोग सामाजिक कार्य में शैक्षणिक पाठ्यक्रम 2019 में शुरू किया गया है और अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एम फिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग और एमडी साइकियाट्री में दो अतिरिक्त सीटें) अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए संबंधित संस्थानों / नियामक निकायों से अनुमोदन के अग्रिम चरणों में हैं।

(ख) **ईसीएचएस ग्राहकों के लिए बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) का उद्घाटन :** पीएमबीजेपी और पीएम की पहल ''सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने'' के लिए बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में एक जन-औषधि केंद्र (जेएके) खोलने हेतु चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (सेना) द्वारा एक पहल की गई थी।

(ग) पैलिएटिव केयर सेंटर, बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में आयुष क्लिनिक का उद्घाटन: रक्षा राज्यमंत्री ने 21 अक्टूबर, 2019 को तीनों सेनाओं के डीजीएएफएमएस और डीजीएमएस की उपस्थिति में पैलिएटिव केयर सेंटर, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आयुष क्लिनिक का उद्घाटन किया।

***

रक्षा विभाग के अन्य संगठन

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय (डीजीडीई)

डीजीडीई, नई दिल्ली के पास 62 छावनियों में रक्षा भूमि के प्रबंधन और नागरिक प्रशासन से संबंधित मामलों में सलाहकार और कार्यकारी कार्य हैं। यह वर्तमान में जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और जयपुर में छह प्रधान निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है। प्रधान निदेशालय बदले में कई फील्ड कार्यालयों, यानी 38 रक्षा संपदा कार्यालयों, 3 सहायक रक्षा संपदा कार्यालयों और 62 छावनी बोर्डों का पर्यवेक्षण करते हैं। इन फील्ड कार्यालयों को देश भर में रक्षा भूमि और छावनी बोर्डों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है।

कुल रक्षा भूमि होल्डिंग

महानिदेशालय ने रक्षा भूमि पर नियंत्रण और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और सभी रक्षा भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन किया है। सभी रक्षा सम्पदा अधिकारियों और छावनी बोर्डों के अधीन क्षेत्रों के संबंध में जीएलआर और एमएलआर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी संग्रहित करने के लिए डीजीडीई द्वारा रक्षा भूमि सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

डीईओ और छावनी बोर्डों में क्रमशः लगभग 98.95% और 100% सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू हो गया है।

डीजीडीई को भूमि लेखापरीक्षा करने का कार्य भी सौंपा गया है। सभी डीईओ सर्किलों का भूमि लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है और कुशल भूमि प्रबंधन के लिए सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। वर्ष 2019-20 के लिए 14 डीईओ अंचलों के भूमि लेखापरीक्षा का तीसरा चक्र प्रक्रियाधीन है।

छावनियों में संस्थान, अस्पताल और औषधालय

'स्मार्ट सिटी' बनाने के लिए सरकार की पहल के अनुरूप, स्मार्ट छावनी पहलों को लागू करने के लिए पायलट चरण में 7 (सात) छावनियों की पहचान की गई है।

स्मार्ट छावनी पहल के लिए चिन्हित छावनियाँ

रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए)

वर्ष के दौरान आईडीएसए द्वारा द्विपक्षीय वार्ता/बातचीत, त्रिपक्षीय संवाद, राउंडटेबल/पुस्तक चर्चा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस)

सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस) युद्धनीतिक और संक्रियात्मक स्तर पर तीनों सेवाओं को इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करती है। एमईएस सेना मुख्यालय में इंजीनियर-इन-चीफ के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है, जो कार्य संबंधी मुद्दों के सभी पहलुओं पर रक्षा मंत्रालय और तीनों सेना प्रमुखों के सलाहकार हैं। यह सशस्त्र बलों को रियर लाइन इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करता है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पूरे देश में आवासीय और कार्यालय भवनों, अस्पतालों, सड़कों और रनवे, डॉक और बंदरगाह जैसी समुद्री संरचनाओं और इससे जुड़ी सेवा आवश्यकताओं जैसे वातानुकूलन, कोल्ड स्टोरेज, बिजली और पानी की आपूर्ति, सीवेज उपचार संबंधी विविध निर्माण गतिविधियाँ कराता है।

अतिरिक्त 10% प्लिंथ एरिया दरों और न्यूनतम तीन सितारा रेटिंग के साथ ग्रीन बिल्डिंग मानदंडों का कार्यान्वयन स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए 150 मेगावाट सौर ऊर्जा शक्ति परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए, सभी नई परियोजनाओं में एलईडी लाइटिंग और जीआरआईएचए मानदंड जैसे उपायों को शामिल किया जा रहा है। एमईएस, मित्र सरकारों/देशों के लिए विदेशों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करके सैन्य राजनयिक पहलों का भी समर्थन करता रहा है।

सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड (एसएससीबी)

एसएससीबी तीनों रक्षा सेवाओं और जिसमें की इंटर-सर्विस चैंपियनशिप चार टीमें (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडिया नेवी और एयर फोर्स) के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों का संचालन और समन्वय करता है।

वर्ष 2019 के दौरान, एसएससीबी ने युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त खेल परिसंघों/ संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चौंपियनशिप में सीनियर पुरुष टीमों को मैदान में उतारा। सेना की टीम ने कई इवेंट्स में राष्ट्रीय चौंपियनशिप जीती।

18-27 अक्टूबर, 2019 तक वुहान, चीन में आयोजित 7 वें सीआईएसएम सैन्य विश्व खेलों में भारतीय सशस्त्र बलों की टीम और उसके प्रदर्शन का विवरण नीचे दिया गया है:

भारतीय सशस्त्र बलों की टीम का प्रदर्शन

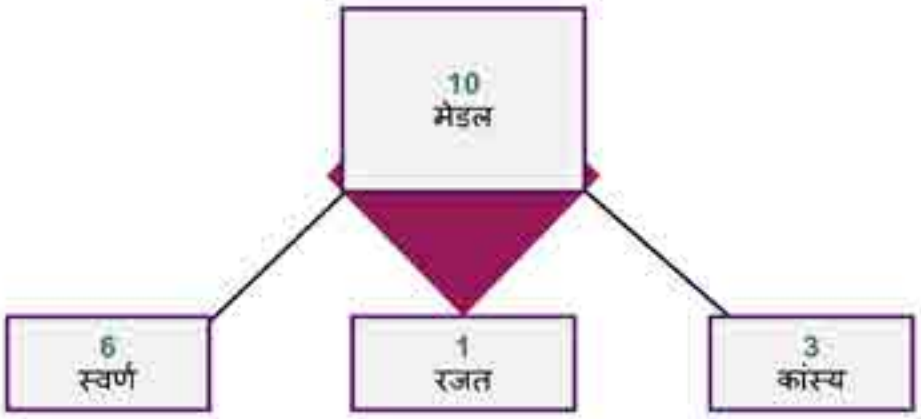

भारतीय टीम द्वारा जीते गए पदक

वर्ष के दौरान सेना के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी)

एनडीसी रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्धनीतिक अध्ययन से संबंधित मामलों पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अपना नाम स्थापित किया है। भारतीय और विदेशी सशस्त्र बलों से ब्रिगेडियर / समकक्ष रैंक के चयनित सशस्त्र बल अधिकारी और सिविल सेवाओं से समकक्ष स्थिति के अधिकारियों को कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जाता है। 59 वें एनडीएस पाठ्यक्रम का विवरण नीचे दिया गया है।

58 वें एनडीसी पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को रक्षा और युद्धनीतिक अध्ययन में एम फिल डिग्री प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह 2 मार्च, 2019 को आयोजित किया गया था। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री समारोह के मुख्य अतिथि थे।

59वें एनडीसी पाठ्यक्रम के प्रतिनभागियों ने 29 नवंबर, 2019 को स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अगला 60वां एनडीसी पाठ्यक्रम 7 जनवरी, 2020 से शुरू होगा।

स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस (एसएफएल)

एसएफएल मुख्यालय आईडीएस, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण के तहत एक प्रतिष्ठित विदेशी भाषा संस्थान है। यह 1948 से भारत में विदेशी भाषा शिक्षण में अग्रणी रहा है।

स्कूल भारतीय सशस्त्र बलों की तीन सेवाओं और सीएपीएफ के कर्मियों को निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है:

विदेशी भाषाएँ जिनमें प्रशिक्षण दिया जाता है

विदेश मंत्रालय के विशेष अनुरोध पर, एसएफएल ने अटल भाषांतर योजना (एबीवाई) के तहत सभी संयुक्त राष्ट्र और जापानी भाषाओं में विदेशी भाषा के उम्मीदवारों की लिखित और मौखिक परीक्षा आयोजित की। ये परीक्षाएं दिसंबर, 2019 में विदेश मंत्रालय को दुभाषियों के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने में सहायता करने के लिए ली गई थी।

रक्षा प्रबंधन कॉलेज (सीडीएम)

सीडीएम एक त्रि-सेना संस्थान है जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ नेतृत्व, अर्धसैनिक बलों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को समकालीन प्रबंधन का कौशल प्रदान करता है। उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम (एचडीएमसी) एक फ्लैगशिप पाठ्यक्रम है, जो 44 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाता है। एचडीएमसी-15 का विवरण नीचे दिया गया है:

15 एचडीएमसी-कोर्स हाइलाइट्स

2019-20 में सीडीएम में दी जाने वाली शिक्षा का एक वृहद अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है जिसमें एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत द्वीप समूह के सैन्य अधिकारी (कर्नल और समकक्ष) शामिल हैं।

रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी)

स्टाफ कॉलेज, मध्य स्तर के सैन्य नेतृत्व के पालने के रूप में सेवा करने वाला एक उत्साहजनक वातावरण प्रदान करता है, उत्कृष्ट कर्मचारी अधिकारियों और तारकीय नेताओं को सशस्त्र बलों के अत्याधुनिक स्तरों के साथ व्यावसायिकता के उच्च स्तर और दृढ़ता से 'कर्तव्य, सम्मान और वीरता' के गुणों को बनाए रखने के लिए तैयार करता है।

पाठ्यक्रम में एक बड़ा संशोधन किया गया और इसे 75 वें स्टाफ पाठ्यक्रम (प्लैटिनम जयंती पाठ्यक्रम) के लिए शामिल किया गया। परिणामी प्रभाव को नीचे हाइलाइट किया गया है:

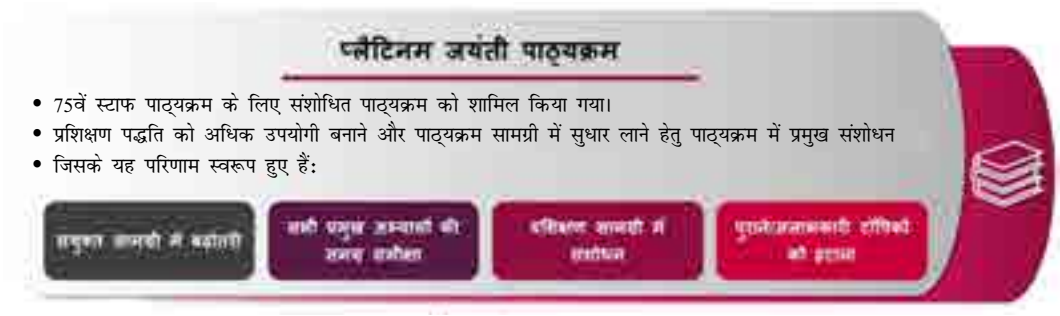

पाठ्यक्रम का संशोधन और प्रभाव

त्रि-सेवा अभ्यास सभी स्टाफ पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य समग्र राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भूमि, नौसेना और वायु संचालन पर जोर देने के साथ संक्रियात्मक और रणनीतिक स्तरों पर संयुक्त योजना और युद्ध के निष्पादन में छात्र अधिकारियों का प्रयोग करना है। पूरे पाठ्यक्रम के लिए एक अभ्यास के बजाय, 73वें स्टाफ पाठ्यक्रम से पूरी टीम को दो समूहों में विभाजित किया गया है और छात्रों को अधिक अनुभव देने के लिए दो ईएक्स कुरुक्षेत्र एक साथ आयोजित किए जाते हैं।

सशस्त्र सेना अधिकरण (एएफटी)

सरकार ने तीन सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) के सदस्यों के कोर्ट मार्शल के फैसले से उत्पन्न सेवा मामलों और अपीलों के संबंध में शिकायतों और विवादों के न्याय निर्णयन एवं सशस्त्र बलों के सदस्यों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए सशस्त्र सेना अधिकरण (एएफटी) की स्थापना की है।

वर्तमान में सशस्त्र सेना अधिकरण दिल्ली (प्रमुख न्यायपीठ) और चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, कोच्चि, गुवाहाटी, मुंबई, जबलपुर और श्रीनगर (जम्मू में कार्यरत) में क्षेत्रीय न्यायपीठों में कार्य कर रहे हैं।

राजभाषा प्रभाग

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन सेवा मुख्यालयों और अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के मुख्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और ढांचागत आवश्यकताएं प्रदान करता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ), निदेशक (सुरक्षा) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के कार्यों का भी निर्वहन करता है।

जनसंपर्क निदेशालय (डीपीआर)

निदेशालय, सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और आम जनता के लिए 13 भाषाओं में एक पाक्षिक पत्रिका 'सैनिक समाचार' प्रकाशित करता है। निदेशालय का प्रसारण अनुभाग 40 मिनट का कार्यक्रम 'सेना दर्शन' तैयार करता है जो सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए नियमित रूप से आकाशवाणी पर प्रसारित होता है। डीपीआर का फोटो डिवीजन एमओडी और सशस्त्र बलों से संबंधित

सभी घटनाओं को फोटो कवरेज प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, डीपीआर ने विभिन्न घटनाओं पर मीडिया कवरेज प्रदान किया, जिनमें निम्न शामिल हैं:

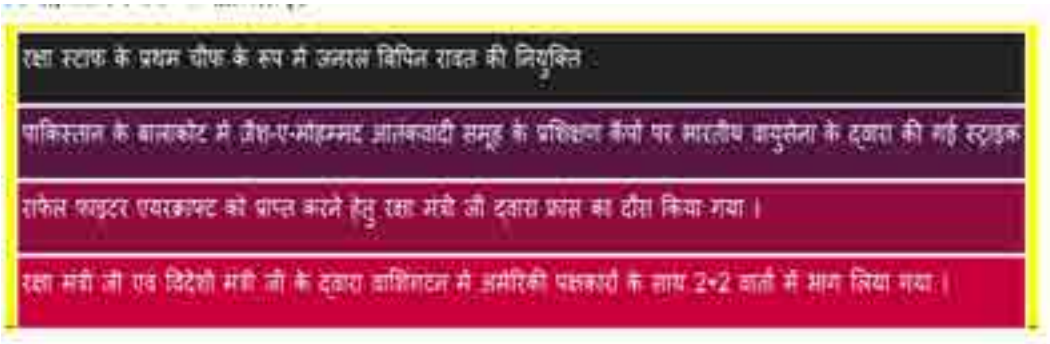

***

विदेशों के साथ रक्षा सहयोग

मित्र देशों (एफएफसी) के साथ रक्षा सहयोग सहलग्नता को वर्ष के दौरान और बल प्राप्त हुआ जब मंत्रालय स्तर पर और सेनाओं के बीच वार्ताओं के साथ-साथ कई गतिविधियां आयोजित की गयीं, जिनमें संरचित वार्ताओं के साथ-साथ संयुक्त अभ्यास शामिल थे। वर्ष के दौरान पांच रक्षा मंत्री स्तरीय दौरे हुए और हमारे रक्षा मंत्री ने भी दस देशों का दौरा किया।

इस अवधि के दौरान भारत और अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग की प्रमुख आकर्षण इस प्रकार है:

अर्जेंटीना और चिली

दोनों देशों के बीच एक औपचारिक संस्थागत व्यवस्था बनाने के लिए 18 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में अर्जेंटीना के साथ रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। लैटिन अमेरिकी देशों के साथ रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, संयुक्त सचिव (योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 11-13 मार्च, 2019 को अर्जेंटीना और 13-15 मार्च, 2019 तक चिली का आधिकारिक दौरा किया।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंध नवंबर 2014 में प्रधान मंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद जारी ''सुरक्षा सहयोग के लिए रूपरेखा'' द्वारा निर्देशित हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायु सेना के प्रमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 4-7 फरवरी, 2019 तक भारत का दौरा किया। एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन अपर सचिव के नेतृत्व में 13-15 मार्च, 2019 के दौरान भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता (डीपीटी) की 6 वीं बैठक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।

ऑस्ट्रेलिया में 9-20 सितंबर, 2019 के दौरान ऑस्ट्राहिंद नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। नौसेनाध्यक्ष के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2-3 सितंबर, 2019 के दौरान ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 वीं एयर-टू-एयर स्टाफ वार्ता 11-13 सितंबर, 2019 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई।

दोनों देशों की सेनाओं के बीच 7 वीं वार्ता 16-18 अक्टूबर, 2019 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच 13 वीं स्टाफ वार्ता 6-8 नवंबर, 2019 के दौरान आयोजित की गई।

9 दिसम्बर, 2019

- **भारत-आस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा सचिवों की तीसरी 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।**

बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश ने नियमित उच्च-स्तरीय दौरों , प्रशिक्षण विनिमय और सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की चिकित्सा सहायता के माध्यम अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत किया। वायु सेना प्रमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 14 फरवरी, 2019 तक सद्भावना यात्रा पर बांग्लादेश का दौरा किया।

10.11 अप्रैल, 2019

वार्षिक रक्षा वार्ता (एडीडी) की द्वितीय बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में 12 प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश का दौरा किया।

इस दौरे के दौरान भारत से रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति करने के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की डालर लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए गए।

दोनों देशों के मध्य सीआरपीएटी पर एक मानकीकृत संचालन प्रक्रिया पर भी हस्ताक्षर किए गए।

एयर-स्टाफ ने 11-14 फरवरी, 2019 के दौरान सद्भावना दौरा किया।

दोनों देशों की नौसेना और वायु सेना के बीच वार्षिक स्टाफ वार्ता क्रमशः 12 अगस्त, 2019 और 5-7 नवंबर, 2019 को आयोजित की गई थी। नौसेनाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 22-25 सितंबर, 2019 तक बांग्लादेश का दौरा किया।

5 अक्टूबर, 2019

- अक्टूबर, 2019 के प्रारंभ में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया।
- बांग्लादेश को तटीय निगरानी प्रणाली की आपूर्ति करने के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्ष किए गए।

भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना ने 10-15 अक्टूबर, 2019 तक वार्षिक सीओआरपीएटी अभ्यास आयोजित किया, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा, भारत में 10-15 अक्टूबर, 2019 तक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास और भारत में 10-19 अक्टूबर, 2019 तक वार्षिक विशेष सैन्य बल अभ्यास आयोजित किया गया। नौसेनाध्यक्ष, बांग्लादेश नौसेना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 8-12 दिसंबर, 2019 तक भारत का दौरा किया।

ब्राजील

भारत-ब्राजील संयुक्त रक्षा समिति (जीडीसी) की बैठक में भाग लेने और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों, प्रशिक्षण केंद्रों और सैन्य सुविधाओं के बीच रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपर सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 11-15 फरवरी, 2019 तक ब्राजील का दौरा किया। ब्राजील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, रक्षा सचिव और ब्राजील के रक्षा उत्पाद सचिव (एसईपीआरओडी) के बीच 24 जनवरी, 2020 को एक बैठक हुई।

चीन

टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) के लिए अंतिम योजना सम्मेलन (एफपीसी) और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-सहित एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेरेरिज्म के लिए फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (एफटीएक्स) में भाग लेने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 से- 29 जून 2020 तक गुइलिन, चीन का दौरा किया।

संयुक्त सचिव (आईसी) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 13-14 अगस्त, 2019 तक भारत-चीन संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 5 वीं बैठक में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया। भारतीय सेना और पीएलए, चीन के बीच संयुक्त सेना अभ्यास ष्हाथ में हाथष का आयोजन 7-20 दिसंबर, 2019 को उमरोई कैंट, मेघालय, भारत में किया गया था। उत्तरी सेना के कमांडर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चीन के साथ रक्षा सहयोग कार्यों के तहत 7-10 जनवरी, 2020 तक चीन का दौरा किया।

कोमोरोस

भारत और कोमोरोस द्विपक्षीय रक्षा सहयोग शुरू करने के करीब आ गए हैं। 11 अक्टूबर, 2019 को रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और कोमोरोस संघ की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मिस्त्र

भारत, मिस्त्र के साथ अपने मैत्रीपूर्ण रक्षा संबंध बनाए रखता है। दोनों पक्षों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। अपर सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 9 वीं संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की बैठक में भाग लेने के लिए 5-7 नवंबर, 2019 तक मिस्र का दौरा किया। वायु सेना प्रमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 24-27 दिसंबर, 2019 तक सद्भावना यात्रा पर मिस्र का दौरा किया।

फ्रांस

हाल के वर्षों में फ्रांस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। नौसेनाध्यक्ष, फ्रांसीसी नौसेना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 6-7 जनवरी, 2019 तक भारत का दौरा किया।

हमारे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए रक्षा मंत्री स्तर पर वार्षिक रक्षा संवाद स्थापित किया गया है।

रक्षा मंत्री और फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री के मध्य फ्रांस में 8-9 अक्टूबर, 2019 तक एक बहुत ही रचनात्मक और उपयोगी वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की।

अक्टूबर, 2019 में रक्षा मंत्री जी के फ्रांस दौरे के दौरान राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की इंडक्शन सेरेमनी भी आयोजित की गई ।

जर्मनी

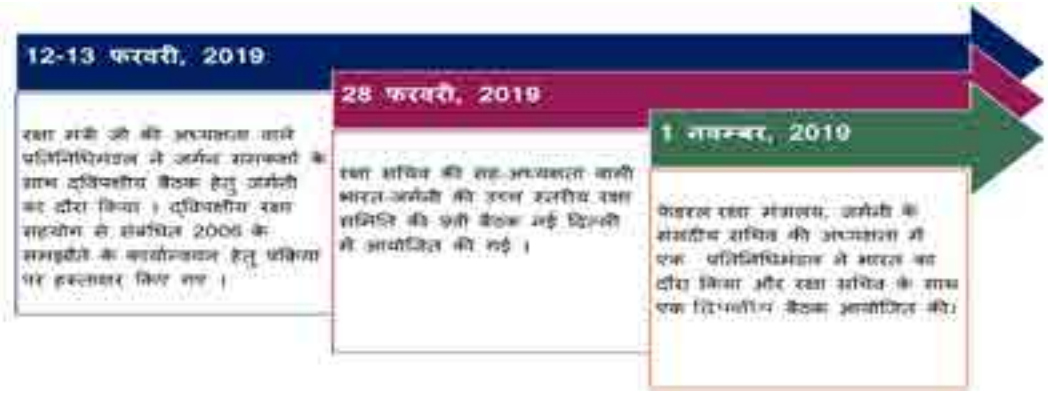

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया के साथ भारत के रक्षा संबंध मधुर बने हुए हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास, भारत में 7–18 मार्च, 2019 तक आयोजित किया गया था।

10 वीं नौसेना–से–नौसेना स्टाफ वार्ता 6–8 अगस्त, 2019 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित की गई। भारत और इंडोनेशिया के बीच 8 वीं आर्मी–टू–आर्मी स्टाफ वार्ता 28–30 अगस्त, 2019 को भारत में आयोजित की गई। भारत और इंडोनेशिया के बीच तीसरी एयर–टू–एयर स्टाफ वार्ता 22–24 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

इजराइल

इजरायल के साथ रक्षा संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक लाभ पर आधारित रहे हैं। कमांडर इजराइल वायु सेना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16–19 अगस्त, 2019 तक भारत का दौरा किया। भारत और इजराइल के बीच 11 वीं आर्मी–टू–आर्मी स्टाफ वार्ता 11–13 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

जापान

भारत और जापान के बीच रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहे हैं। भारत और जापान के बीच तीसरी एयर–टू–एयर स्टाफ वार्ता 27–29 मई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और जापान के बीच 8 वीं नेवी–टू–नेवी स्टाफ वार्ता 9–11 जुलाई, 2019 को टोक्यो में आयोजित की गई।

2-3 सितम्बर, 2019

- जापान के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने जापान का दौरा किया।

भारत में 19 अक्टूबर - 1 नवंबर, 2019 के दौरान एक्स धर्म गार्डियन नामक एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था।

30 नवम्बर, 2019

जापान के रक्षामंत्री और विदेशमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत जापान 2+2 विदेशी व रक्षा मंत्रालयी प्रथम वार्ता में उपस्थिति हेतु भारत का दौरा किया।

2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रालयी वार्ता से पूर्व, जापान के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के मध्य उसी दिन द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया।

सेना प्रमुख ने 3-6 दिसंबर, 2019 तक जापान का दौरा किया।

जॉर्डन

5-6 जनवरी, 2019 से रक्षा सहयोग पर पहली द्विपक्षीय परामर्शदात्री बैठक में भाग लेने के लिए संयुक्त सचिव (योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जॉर्डन दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की शुरुआत हुई है।

कजाखिस्तान

कजाखिस्तान के साथ रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। यूएनआईएफआईएल में हमारे शांति मिशन के साथ कजाख सैनिकों की सह-तैनाती का तीसरा रोटेशन नवंबर, 2019 में शुरू हुआ।

केन्या

भारत और केन्या ने अपने रक्षा संबंधों को लगातार बढ़ाया है। संयुक्त सचिव (योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) की सह-अध्यक्षता में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की पहली बैठक में भाग लेने के लिए केन्या रक्षा बलों के सहायक प्रमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 18 फरवरी, 2019 को भारत का दौरा किया। केन्याई प्रतिनिधिमंडल ने वैरेंगटे में काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल का भी दौरा किया। केन्या सेना के कमांडर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 19-22 नवंबर, 2019 तक भारत का दौरा किया।

किर्गिज़स्तान

28-29 अप्रैल, 2019

- एससीओ सदस्य देशों के रक्षामंत्रियों की बैठक और एससीओ सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभागों के प्रमुखों की बैठक में भागीदारी करने हेतु रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने बिस्केक, किर्गीज़स्तान गणराज्य का दौरा किया।
- रक्षामंत्री ने 29 अप्रैल, 2019 को अपने कीर्गीज समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

मलेशिया

दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, खासकर रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद। भारत और मलेशिया के बीच 8 वीं आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ वार्ता 18-20 सितंबर, 2019 को मलेशिया में आयोजित की गई थी।

मालदीव

भारत और मालदीव समुद्री सुरक्षा चिंताए एक समान है। दोनों पक्ष व्यापक रक्षा सहयोग करते हैं। भारत ने सैन्य प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रशिक्षण और सैन्य कर्मियों को चिकित्सा सहायता के माध्यम से क्षमता निर्माण में मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की सहायता की है।

23-30 जनवरी, 2019

- मालदीव गणराज्य के रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया और रक्षा मंत्री व सभी सेना प्रमुखों से मुलाकात की।
- 24 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में भारत और मालदीव के मध्य दूसरी रक्षा सहयोग वार्ता (डीसीडी) का आयोजन किया गया।

भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों (एमएनडीएफ) के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास 'एकुवेरिन' 24 अप्रैल - 5 मई, 2019 तक भारत में आयोजित किया गया था।

जून, 2019

- तटीय निगरानी रडार प्रणाली (सीएसआरएस) का उद्घाटन संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के मालदीव दौर के दौरान किया गया।

चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स (सीडीएफ), मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 3-8 जुलाई, 2019 तक भारत का दौरा किया। भारत और मालदीव के बीच चौथी संयुक्त स्टाफ वार्ता 4-6 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाइड्रोग्राफी पर संयुक्त आयोग की पहली बैठक 25-27 सितंबर, 2019 को मुख्य हाइड्रोग्राफर, भारतीय नौसेना के दौरे के दौरान माले में आयोजित की गई थी।

सेना प्रमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2019 तक मालदीव का दौरा किया। 4 दिसंबर, 2019 को मालदीव को एक फास्ट इंटरसेप्टर बोट (एफआईबी) सौंपी गई। भारतीय नौसेना और एमएनडीएफ के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास 'एकथा' को मालदीव में 7-20 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित किया गया।

मंगोलिया

भारत के मंगोलिया के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रक्षा संबंध हैं। संयुक्त सचिव (योजना) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 6 से 8 मई, 2019 तक भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 9$^{वीं}$ बैठक में भाग लेने के लिए मंगोलिया का दौरा किया। नोमैडिक एलिफेंट नामक एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास 5-18 अक्टूबर, 2019 को भारत में आयोजित किया गया था।

मोजाम्बिक

29-30 जुलाई, 2019	• रक्षा मंत्री ने मोजाम्बिक दौरे से भारत और मोजाम्बिक के मध्य रक्षा सहयोग पुनः जीवंत हो गया। • यात्रा के दौरा, मोजाम्बिक को दो तीव्र गति वाली इंटरसेप्टर नौकाएं सौंपी गई और मोजाम्बिक के साथ दो समझौता ज्ञापनों/समझौतों अर्थात् हाइड्रोग्राफी और व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर हस्ताक्षर किये गए।

राष्ट्रीय रक्षा मंत्री, मोजाम्बिक की भारत में जवानी यात्रा 26-30 नवंबर, 2019 तक आयोजित की गई थी। मोजाम्बिक विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संपूरक करार पर 29 नवंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।

म्यांमार

2019 में म्यांमार के साथ भारत के रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत और म्यांमार के बीच चौथी आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ वार्ता 13-15 मार्च, 2019 को म्यांमार में आयोजित की गई।

16-17 मई, 2019	• रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भागीदारी हेतु म्यांमार का दौरा किया।

कमांडर-इन-चीफ (वायु), म्यांमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 4 जुलाई, 2019 को भारत का दौरा किया। म्यांमार के रक्षा बलों के कमांडर-इन-चीफ ने 25 जुलाई - 2 अगस्त, 2019 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, भारत और म्यांमार के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 29 जुलाई, 2019 को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और म्यांमार के बीच चौथी एयर -टू-एयर स्टाफ वार्ता 18-20 सितंबर, 2019 को म्यांमार में आयोजित की गई। भारत और म्यांमार के बीच 8 वीं नौसेना-टू-नौसेना स्टाफ वार्ता 28-30 नवंबर, 2019 को म्यांमार में आयोजित की गई।

नीदरलैंड्स

भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और नीदरलैंड के साम्राज्य के रक्षा मंत्री के बीच रक्षा के क्षेत्र में वर्गीकृत सूचना के पारस्परिक संरक्षण पर 16 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

नाइजीरिया

17-18 जनवरी, 2019

- नाईजीरिया ने स्थायी सचिव, रक्षा मंत्रालय, नाइजीरिया ने रक्षा सचिव और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के लिए भारत का दौरा किया।

तत्कालीन अपर सचिव की सह-अध्यक्षता में भारत-नाइजीरिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की 5 वीं बैठक 17-18 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय नौसेना और नाइजीरियाई नौसेना के बीच पहली नौसेना उप-समूह की बैठक 25-26 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

ओमान

खाड़ी क्षेत्र में ओमान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत द्विपक्षीय अभ्यास करता है और तीनों सेवाओं के स्तर पर स्टाफ वार्ता करता है। दोनों देशों ने अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। 9 वीं भारत-ओमान एयर स्टाफ वार्ता 14-16 अप्रैल, 2019 को ओमान में आयोजित की गई थी। तीसरी नौसेना से नौसेना स्टाफ वार्ता 3-5 सितंबर, 2019 को मस्कट में आयोजित की गई थी। 17-19 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में प्रथम भारत-ओमान, सेना से सेना स्टाफ वार्ता आयोजित की गई थी। तीसरा द्विपक्षीय सेना अभ्यास 'अल नजाह' 12-26 मार्च, 2019 को ओमान में और वायु सेना अभ्यास 'ईस्टर्न ब्रिज' के 5 वें संस्करण का आयोजन 20-24 अक्टूबर, 2019 को ओमान में किया गया था।

फिलीपींस

संयुक्त सचिव (नौसेना) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 1-2 अगस्त, 2019 को साइबर सुरक्षा पर एडीएमएम-प्लस ईडब्ल्यूजी के टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) में भाग लेने के लिए मनीला, फिलीपींस का दौरा किया।

पुर्तगाल

भारत पुर्तगाल के साथ अपने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है। 17 अप्रैल, 2019 को पुर्तगाल राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की।

कतर

स्टाफ मेजर जनरल (सी), कमांडर कतरी एमरी नौसेना (क्यूईएनएफ) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 2-5 अप्रैल, 2019 तक भारत का दौरा किया। क्यूईएनएफ में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों/नाविकों के रोजगार के संबंध में भारत और कतर के बीच 5 अप्रैल, 2019 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नौसेना और क्यूईएनएफ के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 17-22 नवंबर 2019 को कतर में आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 27-28 नवंबर, 2019 को 5वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक में भाग लेने के लिए कतर का दौरा किया।

कोरिया गणराज्य (आरओके)

भारत-कोरिया गणराज्य (आरओके) संबंधों ने हाल के वर्षों में काफी प्रगति की है और हितों, आपसी सद्भावना और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के एक महत्वपूर्ण अभिसरण से वास्तव में बहुआयामी बन गए हैं। 2-3 सितंबर, 2019 को भारत में दूसरी भारत-आरओके आर्मी-टू-आर्मी वार्ता आयोजित की गई।

5-6 सितम्बर, 2019

रक्षा मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कोरिया गणराज्य के साथ 8वीं रक्षा वार्ता के लिए कोरिया गणराज्य की यात्रा की।

नौसेना ऑपरेशन प्रमुख, कोरिया गणराज्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 24-27 नवंबर, 2019 तक भारत का दौरा किया।

रूस

थल सेना कमांडर, रूसी संघ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 12-14 मार्च, 2019 को भारत का दौरा किया और नई दिल्ली में रक्षा सचिव से मुलाकात की।

5-6 सितम्बर, 2019

रक्षा सचिव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 8वीं मास्को कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया और रूसी अधिकारी वर्ग के साथ द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया।

10-14 जून, 2019 से पारस्परिक संभारिकी सहयोग पर समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपर सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया। वायु सेना प्रमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 9-12 जुलाई, 2019 तक सद्भावना यात्रा पर रूस का दौरा किया। रूसी परिसंघ के उप-रक्षा मंत्री ने 4 से 5 अगस्त 2019 के दौरान इंटरनेशनल आर्मी गेम्स-2019 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए जैसलमेर (राजस्थान) का दौरा किया। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 16 से 18 अगस्त, 2019 के दौरान इंटरनेशनल आर्मी गेम्स-2019 के समापन समारोह में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया।

4 सितंबर 2019 को पुर्जों, घटकों, समुच्चय और रूसी/सोवियत मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों से संबंधित अन्य सामग्री के संयुक्त निर्माण में आपसी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीजी (इन्फैंट्री), सेना मुख्यालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 18-20 सिंतबर, 2019 से 'अभ्यास केंद्र- 2019' के मुख्य चरण में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया।

भारत में कलाश्निकोव छोटे हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर 18 सितंबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। सचिव (डीपी) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सैन्य तकनीकी सहयोग पर कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के लिए 3-4 अक्टूबर , 2019 को रूस का दौरा किया। सीआईएससी की सह-अध्यक्षता में सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की पहली बैठक 24-25 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

संयुक्त सचिव स्तर के एक विशेष कार्य अधिकारी (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आईआरआईजीसी एम एंड एमटीसी की बैठक के दौरान भारत और रूसी रक्षा मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले भारत रूस इंटरगवर्नमेंटर कमीशन ऑन मिलिटरी एंड मिलिटरी - टेक्नीकल कॉपरेशन (आईआरआईजीसी एम एंड एमटीसी) मंत्रालयी प्रोटोकॉल पर वार्ता करने के लिए 29 से 30 अक्टूबर, 2019 के दौरान रूस का दौरा किया।

पहली वायु सेना स्टाफ वार्ता 29-30 अक्टूबर, 2019 को रूस में आयोजित की गई। चौथी नौसेना-से-नौसेना स्टाफ वार्ता 30 अक्टूबर- 1 नवंबर, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

5-7 नवम्बर, 2019	रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग (आईआरआईजीसी) एम एंड एमटीसी) बैठक पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग बैठक में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया।

भारत-रूस त्रि-सेवा अभ्यास आईएनडीआरए-2019 भारत में 10-18 दिसंबर, 2019 तक आयोजित किया गया।

सऊदी अरब

सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग लगातार प्रगति कर रहा है। संयुक्त सचिव (योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग)के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 2-3 जनवरी, 2019 को रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति (जेसीडीसी) की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया।

सर्बिया

7 नवंबर, 2019 को भारत गणराज्य की सरकार और सर्बिया गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

सिंगापुर

सिंगापुर के साथ रक्षा सहयोग में विशेष रूप से 2019 में राजनीतिक-रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। भारत में 27 मार्च से 14 अप्रैल, 2019 तक एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच 11वीं एयर-टू-एयर सैन्य वार्ता 17-19 अप्रैल, 2019 को सिंगापुर में आयोजित की गई। भारत और सिंगापुर के बीच 12वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता 18 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। संयुक्त सचिव)योजना (की सह-अध्यक्षता में 12वीं भारत-सिंगापुर रक्षा कार्य समूह (डीडब्ल्यूजी) की बैठक 2 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।

30 सितम्बर-01 अक्टूबर, 2019

रक्षा-सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमडल ने 13वीं भारत-सिंगापुर रक्षा नीति में भाग लेने के लिए सिंगापुर का दौरा किया।

5-6 सितम्बर, 2019

रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्री की चौथी वार्ता (डीएमडी) में भाग लेने के लिए सिंगापुर का दौरा किया।

श्रीलंका

भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ रक्षा संबंध हैं। प्रशिक्षण, कैडेटों का आदान-प्रदान, खेलों का आदान-प्रदान, प्रशिक्षकों का आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुख्य पहलू हैं। श्रीलंका की नौसेना के कमांडर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 मार्च से 2 अप्रैल, 2019 तक भारत का दौरा किया।

8-9 अप्रैल, 2019

छठीं वार्षिक रक्षा वार्ता (एडीडी) में शामिल होने के लिए रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका का दौरा किया। कई मामलों पर बातचीत हुई और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढाने के लिए दोनों देश सहमत हुए।

दोनों देशों की सेना और वायु सेना के बीच वार्षिक स्टाफ वार्ता क्रमशः 11 से 13 जून, 2019 और 3-5 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गई। भारतीय वायुसेना के विमान में पति-पत्नी सहित श्रीलंका के सशस्त्र सेना के 160 कार्मिकों द्वारा बोध गया की एक परिचय यात्रा जून 2019 के महीने में आयोजित की गई थी। 7-12 सितंबर, 2019 तक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 'स्लिनेक्स' और 7-19 सितंबर, 2019 तक विशेष सेना अभ्यास भारतीय नौसेना और श्रीलंका के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था।

भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना ने 3 से 25 सितंबर, 2019 तक श्रीलंका में ''कार्मोरंट स्ट्राइक'' 1-14 दिसंबर, 2019 तक भारत में मित्र अभ्यास किया। नौसेनाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 19-22 दिसंबर, 2019 तक श्रीलंका का दौरा किया।

स्वीडन

रक्षामंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 13-14 फरवरी, 2019, तक स्वीडन का दौरा किया और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। 13 फरवरी, 2019, को रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

वायु सेना प्रमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 3-6 जून, 2019, तक सद्भावना यात्रा पर स्वीडन का दौरा किया।

थाईलैंड

थाईलैंड के साथ रक्षा सहयोग में काफी वृद्धि हो रही है। 21 जनवरी-21 फरवरी, 2019 के दौरान थाईलैंड में एक्स कोबरा गोल्ड नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया था। संयुक्त सचिव (पीजी/समन्वय) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आसियान रक्षा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक प्लस में भाग लेने के लिए 28 फरवरी से 2 मार्च, 2019 तक थाईलैंड का दौरा किया। अपर सचिव की सह-अध्यक्षता में आयोजित भारत-थाईलैंड वार्ता की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा उप स्थायी सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 7 मार्च, 2019 को थाईलैंड की यात्रा की। भारत और थाईलैंड के मध्य 11वीं नौसेना से नौसेना सैन्य वार्ता और 15वीं संयुक्त कार्य समूह ईओएस बैठक 12-14 मार्च, 2019 को थाईलैंड में हुई।

अपर सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने थाईलैंड का दौरा किया और एडीएमएम प्लस वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक प्लस (एडीएसओएम प्लस) में भाग लिया।

नौसेनाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 17-19 अप्रैल, 2019 को थाईलैंड का दौरा किया।

भारत और थाईलैंड के बीच10 वीं एयर टू एयर सैन्य वार्ता 23-25 जुलाई 2019 को थाईलैंड में आयोजित की गई। भारत और थाईलैंड के बीच तीसरी सेना-से-सेना सैन्य वार्ता 23-25 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। चौथा भारतीय नौसेना - रॉयल थाईलैंड नौसेना खुफिया सम्मेलन 3-7 सितंबर 2019 से भारत में आयोजित किया गया।

एक्स मैत्री नामक एक संयुक्त अभ्यास 16-29 सितंबर, 2019 के दौरान भारत में आयोजित किया गया। पहला भारत-सिंगापुर-थाईलैंड नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास भी 16-20 सितंबर, 2019 को विजाग, भारत में आयोजित किया गया।

17-18 नवम्बर, 2019

6वीं एडीएमएम प्लस बैठ में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने थाईलैंड का दौरा किया।

भारतीय सेना के दो अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 18-21 दिसंबर 2019 को थाईलैंड में आयोजित काउंटर टेररिज्म एंड हैंडओवर समारोह पर 10 वें एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त सचिव)नौसेना (के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16-17 दिसंबर, 2019 को आबू धाबी में भारत-यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की 10वीं बैठक में भाग लिया।

यूनाइटेड किंगडम

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच रक्षा संबंध उत्कृष्ट रहे हैं और रक्षा सहयोग द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

7-9 मार्च, 2019

रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 20वीं भारत-यूके रक्षा सलाहकार समूह (डीसीजी) बैठक में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया ।

यूके रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 29 नवंबर, 2019 को 21वें रक्षा सलाहकार समूह (डीसीजी) की बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

अमरीका

भारत और अमरीका रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तरीय 2+2 संवाद की शुरूआत ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में नया अध्याय जोड़ा है। सेनाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 2-5 अप्रैल, 2019 के दौरान तक सद्भावना यात्रा पर यूएसए का दौरा किया।

नौसेना ऑपरेशन प्रमुख, अमेरिकी नौसेना (सीएनएस के समकक्ष) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 से 14 मई 2019 तक भारत का दौरा किया। महानिदेशक (अर्जन) ने 31 जुलाई से 1 अगस्त, 2019 तक भारत-अमेरिका रक्षा अधिप्राप्ति और नीति समूह (डीपीपीजी) बैठक आयोजित करने के लिए वाशिंगटन डीसी में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

1-2 अगस्त, 2019
रक्षा सचिव और उनके समकक्ष के साथ रक्षा नीति समूह बैठक वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी।

भारत-अमेरिका समुद्रवर्ती सुरक्षा संवाद 23 अगस्त 2019 को मोंटेरे, कैलिफोर्निया, यूएसए में आयोजित किया गया था

16-18 दिसम्बर, 2019
द्वितीय भारत-यूएस मंत्रालयी 2+2 वार्ता में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन डीसी का दौरा किया।

उज़्बेकिस्तान

उज़्बेकिस्तान के साथ रक्षा संबंध अच्छी प्रगति कर रहे हैं। संयुक्त सचिव (योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) की सह-अध्यक्षता में रक्षा सहयोग पर पहली भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 27 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

25-29 मार्च, 2019
रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

1-2 नवम्बर, 2019
रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शासनाध्यक्षों की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए उज़्बेकिस्तान (धाराकोट) का दौरा किया।

निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

वियतनाम

वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग में अच्छी प्रगति हो रही है। भारत और वियतनाम के बीच दूसरी एयर-टू-एयर सैन्य वार्ता 23-25 अप्रैल 2019 के दौरान को वियतनाम में आयोजित की गई।

3-4 अक्टूबर, 2019
रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वियतनाम के साथ 12वीं वार्षिक सुरक्षा वार्ता में भाग लेने के लिए वियतनाम का दौरा किया।

वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के प्रमुख और उप रक्षा मंत्री ने 24-27 नवंबर 2019 के दौरान भारत का दौरा किया। वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 6-9 दिसंबर, 2019 के दौरान भारत का दौरा किया। भारत और वियतनाम के बीच नौसेना से नौसेना सैन्य वार्ता 16-18 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

जाम्बिया

जाम्बिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 21 अगस्त 2019 को भारत और जाम्बिया के बीच 'रक्षा के क्षेत्र में सहयोग' पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) - प्लस

टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) विशेषज्ञों के काउंटर टेररिज्म पर कार्य समूह के फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (एटीएक्स) के लिए प्रारंभिक योजना सम्मेलन (आईपीसी) में भाग लेने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 22-24 जनवरी, 2019 के दौरान गुइलिन, चीन का दौरा किया।

समुद्री सुरक्षा फील्ड् प्रशिक्षण अभ्यास और अंतिम योजना सम्मेलन पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस विशेषज्ञों के कार्य समूह (एडीएमएम-प्लस ईडब्ल्यूजी) की बैठक में भाग लेने के लिए संयुक्त सचिव (वर्क्स) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 21-22 फरवरी, 2019 तक बुसान कोरिया गणराज्य का दौरा किया।

2017-2019 चक्र के लिए, भारत और म्यांमार सैन्य चिकित्सा संबंधी ईडब्ल्यूजी के सह-अध्यक्ष थे।सैन्य चिकित्सा पर एडीएमएम प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप (2017-19) के तीसरे चक्र के दौरान भारत और म्यांमार की सह-अध्यक्षता में सैन्य चिकित्सा संबंधी एक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (मेडेक्स-2019) जो कि अब तक का पहला स्टैंडअलोन अभ्यास भी है, एडीएमएम प्लस छतरी के नीचे, सैन्य चिकित्सा 11-16 मार्च, 2019 के दौरान लखनऊ (भारत) में आयोजित की गई।

जिसमें 17 देशों (आसियान और आसियान प्लस देशों) के दल ने भाग लिया। मिलिट्री मेडिसिन पर एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी की सह-अध्यक्षता के दौरान, पैरामेडिक्स के लिए मिलिट्री मेडिसिन पर एक हैंडबुक भी लिखी गई थी।

संयुक्त सचिव (वायु) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 14वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक और मानवीय सहायता और आपदा संबंधी विशेषज्ञ कार्यसमूह (14वीं एडीएमएम -प्लस एचएडीआर ईडब्ल्यूजी) अंतिम आयोजना सम्मेलन में भाग लेने के लिए हवाई, अमरीका का दौरा किया।

रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस मानवीय सहायता और आपदा राहत संबंधी विशेषज्ञ कार्य समूह (एचएडीआर पर एडीएमएम-प्लस ईडब्ल्यूजी) अंतिम आयोजना सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-11 अप्रैल, 2019 के दौरान कुआलालंपुर का दौरा किया।

28-29 मई, 2019 को साइबर सुरक्षा टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक - प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह (एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी) के अंतिम संबंधी आयोजना सम्मेलन (एफपीसी) में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मनीला, फिलीपींस का दौरा किया।

एचएडीआर अभ्यास संबंधी एडीएमएम-प्लस ईडब्ल्यूजी में भाग लेने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 30 जुलाई से 1 अगस्त 2019 तक कुआलालंपुर की यात्रा की।

संयुक्त सचिव (नौसेना) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 1-2 अगस्त, 2019 के दौरान साइबर सुरक्षा संबंधी एडीएमएम-प्लस ईडब्ल्यूजी के टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) में भाग लेने के लिए मनीला फिलीपींस का दौरा किया।

एडीएमएम प्लस की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। एडीएमएम-प्लस की छठी बैठक 17-18 नवंबर 2019 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई और इसमें रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। एडीएमएम-प्लस बैठक के मौके पर रक्षा मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक के दौरान पैरामेडिक्स के लिए सैन्य चिकित्सा पर हैंडबुक भी जारी की गई।

भारतीय सेना के दो अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 18-21 दिसंबर 2019 को थाईलैंड में आयोजित काउंटर टेररिज्म और हैंडओवर समारोह संबंधी 10वें एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

मानवीय माइन एक्शन संबंधी एडीएमएम प्लस ईडब्लयूजी और शांति स्थापना अभियान संबंधी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक –प्लस विशेषज्ञों के कार्य समूह एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी की प्रारंभिक स्थल सर्वेक्षण और अंतिम आयोजना सम्मेलन में भाग लेने के लिए 26-29 मार्च, 2020 के दौरान एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया का दौरा किया।

***

सरलीकरण, विकेंद्रीकरण और व्यवसाय करने में आसानी (ईओडीबी) को बढ़ाने की दिशा में पहल

सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपस्करों से लैस करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने के सरलीकरण, युक्तिकरण और विकेंद्रीकरण और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कई अग्रणी पहल की गई, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार करने में आसानी हुई और 'रेड कार्पेट' के स्थान पर 'रेड टेप' का प्रतिस्थापन किया। यह अध्याय ऐसे उपायों का अवलोकन प्रदान करता है।

ईओडीबी को बढ़ाने की पहल

पूंजीगत अधिग्रहण का सरलीकरण, कारगर बनाना और युक्तिकरण

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना: जून 2017 में, नीति आयोग ने 'पूंजीगत अधिग्रहण में बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर)' का प्रस्ताव दिया था, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रसंस्करण मामलों की समयसीमा को कम करना था। नतीजतन, रक्षा मंत्रालय ने शबिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंगश के माध्यम से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) में सुधारों को लागू किया। जहां पहले चरण से चौथे चरण के संशोधनों को वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 में शामिल किया गया था, वहीं चरण i और चरण ii के संशोधनों को वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

चरण-5 संशोधन	तकनीकी क्षमता मूल्यांकन मानक और वित्तीय मूल्यांकन मानक को शामिल करते हुए भारतीय जहाज निर्माण इकाई के लिए क्षमता मूल्यांकन मार्गदर्शन को शामिल करना।
चरण-6 संशोधन	• परिणाम विधीक्षा के लिए प्रक्रिया में संशोधन • फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में लागत समिति द्वारा बैंचमार्किंग में संशोधन • लेटर ऑफ क्रेडिट में सुरक्षा/संरक्षण शर्तें शामिल करने के लिए संशोधन • सामान्य स्टाफ (जीएस) मूल्यांकन और आएफसी के प्रत्याकर्षण के अनुमोदन को शामिल करना। मेक-I और मेक-II प्रक्रिया में संशोधन

चरणवार संशोधन

रक्षा में व्यवसाय करना एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना: रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा में व्यापार करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उनके द्वारा अग्रेषित सिफारिशों को समझने और जांच करने के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों/संघों के साथ विचार-विमर्श किया। इन सिफारिशों में से कई को प्रक्रियाओं के परिशोधन के साथ-साथ डीपीपी और डीपीएम की चल रही समीक्षा में भी शामिल किया गया था।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया और रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन: रक्षा मंत्री के अनुमोदन के आधार पर डीपीपी-2016 के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए डीजी (अधिग्रहण) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ताकि परिसंपत्ति अधिग्रहण से जीवन चक्र सहायता तक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। सभी प्रचलित प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण करने और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बेहतर प्रक्रिया तैयार करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कुल 13 उप समितियों का गठन किया गया है।

विकेन्द्रीकरण

वित्तीय शक्तियों के मौजूदा प्रतिनिधिमंडल में वृद्धि: पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी के लिए रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री की वित्तीय शक्तियों के संशोधित प्रतिनिधिमंडल और वित्तीय शक्तियों के मौजूदा प्रतिनिधिमंडल की वृद्धि, सीसीएस द्वारा अनुमोदित रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा 19 फरवरी, 2019 से प्रख्यापित किया गया था। संशोधित प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

क्र.सं.	वित्तीय शक्तियां	सीएफए
(1)	300 करोड़ रुपये तक	सेवा मुख्यालय / उप प्रमुख
(2)	300 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक	रक्षा सचिव
(3)	500 करोड़ रुपये से अधिक और 2000 करोड़ रुपये तक	रक्षा मंत्री (आरएम)
(4)	2000 करोड़ रुपये से अधिक और 3000 करोड़ रुपये तक	वित्त मंत्री (एफएम)
(5)	3000 करोड़ रुपये से अधिक	सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस)

वित्तीय शक्तियों का संशोधित प्रतिनिधिमंडल

आग्नेयास्त्रों के पुर्जों के निर्यात के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन: गृह मंत्रालय ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 10 के तहत डीडीपी को आग्नेयास्त्रों के निम्नलिखित भागों के निर्यात के लिए अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन किया है:

सरलीकरण

किए गए सरलीकरण उपाय

1. **रक्षा ऑफसेट दिशानिर्दशों का संशोधन:** रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों के पुन: चरणबद्ध खंडों को 8 अगस्त, 2019 को रक्षा मंत्रालय द्वारा संशोधित और प्रख्यापित किया गया है। इसके अलावा, ऑफसेट के उद्देश्यों के शीघ्र फलन को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों में संशोधन किया जा रहा है।

2. **तीसरी पार्टी निरीक्षण एजेंसियों को गुणवत्ता आश्वासन कार्यों की आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देश:** रक्षा मंत्रालय ने 30 मई, 2019 के आदेश के तहत, निजी उद्योग द्वारा निर्मित रक्षा भंडारों के गुणवत्ता आश्वासन कार्यों की आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देशों को तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को अनुमोदित किया है।

3. **विक्रेता योग्यता मानदंड के लिए दिशानिर्देश:** रक्षा मंत्रालय ने 18 सितंबर, 2019 को रक्षा मंत्रालय आईडी के माध्यम से खरीदो (भारतीय-आईडीडीएम) खरीदों (भारतीय) और खरीद और निर्माण (भारतीय) मामलों में विक्रेता चयन/पूर्व योग्यता के लिए मानदंड तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

4. **रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 (डीपीपी-16) में संशोधन:** चरण V और चरण VI संशोधन 1 नवंबर, 2019 तक जारी किए गए हैं। डीपीपी-16 में चरण V संशोधन के भाग के रूप में भारतीय शिपयार्ड के लिए संशोधित क्षमता मूल्यांकन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। चरण VI संशोधन इस प्रकार हैं:

(क) शक्तियों के प्रत्यायोजन मामलों में संबंधित पीआईएफए/आईएफए (कैपिटल) द्वारा और एसओसी के आधार पर गैर-प्रत्यायोजित मामलों के लिए रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा मात्रा पुनरीक्षण किया जाना है।

(ख) मुख्यालय आईडीएस स्टीयरड मामलों में सीआईएससी द्वारा जीएस मूल्यांकन का अनुमोदन और आरएफपी को वापस लेना।

(ग) भारतीय खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए एलसी दिशानिर्देशों में सुरक्षा रक्षा/संरक्षण खंडों को शामिल करने के लिए संशोधन।

(घ) बेंचमार्किंग/लागत समिति पैरा से एफटीपी मामलों में जीएस मूल्यांकन और एफईटी के संदर्भों को हटाना।

व्यापार करने में आसानी

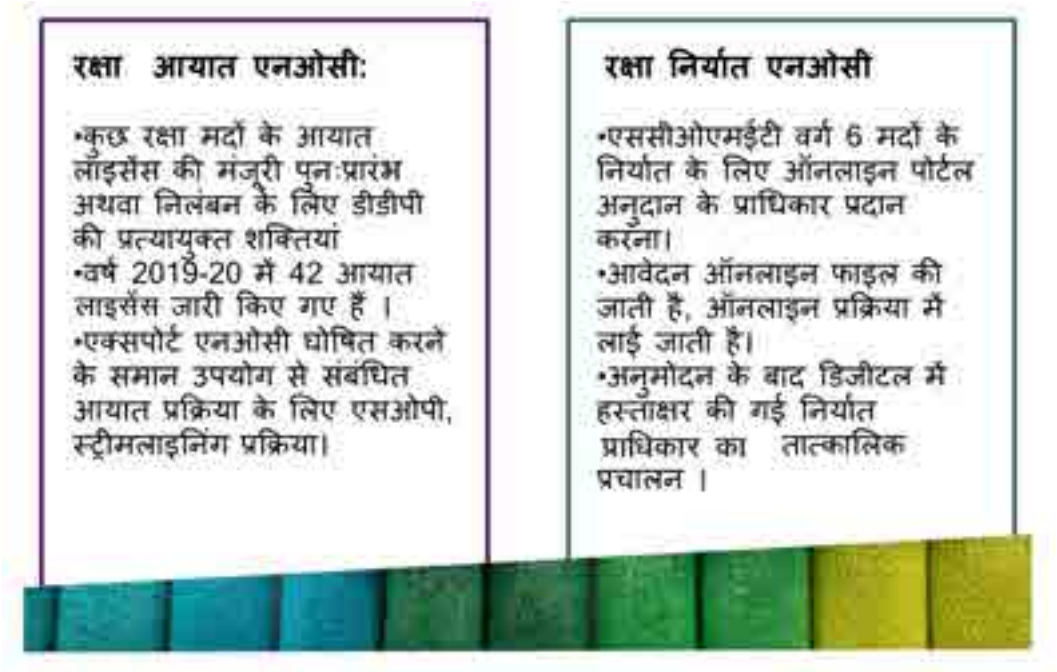

ईओडीबी उपाय

युद्ध सामग्री सूची मदों के निर्यात के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जनवरी 2020 में संशोधित किया गया था। संशोधित एसओपी डीडीपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किए गए संशोधन/संशोधन निम्नानुसार हैं:

(क) भागों और घटकों के लिए निर्यात प्राधिकरण जारी करने से पहले हार्ड कॉपी में मूल ईयूसी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(ख) डब्ल्यूए देशों को इंजीनियरिंग निर्यात (युद्ध सामग्री सूची मदों से संबंधित टीओटी) के मामलों में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित ईयूसी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(ग) निविदा/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए और परीक्षण और मूल्यांकन के लिए परिशिष्ट-द्वितीय मदों का निर्यात सरकार द्वारा हस्ताक्षरित ईयूसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना अनुमति है (वस्तुओं की वापसी के लिए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने और किसी भी जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के अधीन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए नेतृत्व)।

रक्षा उत्पादन विभाग दो ओजीईएल (ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस) लाया है एक चुनिंदा पुर्जों और घटकों के लिए और दूसरा प्रौद्योगिकी के अंतर-कंपनी हस्तांतरण के लिए।

ओजीईएल एक बार का निर्यात लाइसेंस है जो उद्योग को ओजीईएल की वैधता के दौरान निर्यात प्राधिकरण की मांग किए बिना ओजीईएल में निर्दिष्ट निर्दिष्ट वस्तुओं को निर्दिष्ट गंतव्यों में निर्यात करने की अनुमति देता है। ये अधिसूचना hhtps:èkèkwww-defencexin.gov.in पर डाले गए हैं।

रक्षा निर्यात

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल निर्यात (करोड़ रुपए में)	1521.91	4682.36	10745.77	9,115.55 करोड़ *
जारी किए गए प्राधिकरणों की संख्या	254	288	668	829

• उल्लिखित मूल्य में डीपीएसयू द्वारा वास्तविक निर्यात और डीडीपी (ईपीसी) द्वारा निजी फर्मों और स्कोमेट (कैट.6 को छोड़कर) को जारी किए गए प्राधिकरणों के अनुसार मूल्य शामिल है।

व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना

देश में रक्षा और एयरोस्पेस में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के अपने प्रयास के तहत, रक्षा उत्पादन विभाग ने रक्षा प्रतिष्ठान के साथ व्यापार करने में अधिक आसानी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ:

01

रक्षा निवेश प्रकोष्ठ

- ऑनलाइन पोर्टल
- वर्ष 2019-20 में ''भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो-2019'' और ''रक्षा कनेक्ट'' जैसे विभिन्न औद्योगिक इवेंट में भागीदारी
- अपनी स्थापना के समय डीआईसी के षरा 703 पूछताछ/मामले प्राप्त और निपटाये गये हैं।

रक्षा उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई को सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) द्वारा जनवरी 2018 में रक्षा निवेशक सेल (डीआईसी) शुरू किया गया था। ऑनलाइन पोर्टल https:èkèkdefenceinvestorcell.gov.in के माध्यम से भौतिक इंटरफेस के बिना डीआईसी तक पहुंच उपलब्ध है।

प्रत्युत्तर में लागू औसत समय 2 दिनों से कम था जबकि प्रक्रिया पूरी करने में लगा औसत समय 7 दिन से कम था।

मुक्त सामान्य निर्यात लाइसेंस

02

ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस

- मैसर्स इंडो-रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स आईआरआरपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी, भारतीय पक्ष से ओएफबी और रूस की तरफ से जेएससी आरओई और सीके साझेदारों के तौर पर, 25 फरवरी, 2019 को सम्मिलित किए गए थे और 3 मार्च, 2019 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर, 2019 में, भागों और घटकों के निर्यात के लिए और इंट्रा कंपनी टीओटी के लिए 2 ओजीईएल की घोषणा की है। संयुक्त उद्यम कंपनी सेवा और गृह मंत्रालय आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 75,000 की दर से कम से कम 7,50,000 असॉल्ट राइफल का निर्माण करेगी।

नाइट विजन डिवाइस:

03

नाइट विजन डिवाईस

- भारतीय सशस्त्र बलों की रात की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीक का सैटअप मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड (बीईएल) द्वारा किया गया।

बीईएल ने इमेज इंटेन्सिफायर ट्यूबों के स्वदेशी निर्माण के लिए फ्रांस से रणनीतिक प्रौद्योगिकी का निवेश और खरीद की थी। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के अलावा भारत ऐसी क्षमता वाला दुनिया का 5 वां देश बन गया है। बीईएलओपी, पुणे द्वारा निर्मित इमेज इंटेन्सिफायर ट्यूब को सभी इमेज इंटेन्सिफायर आधारित निष्क्रिय नाइट विजन उपकरणों में उपयोग के लिए क्रेता नामित उपकरण के रूप में नामित किया गया है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी)

04

आयुध फैक्टरी बोर्ड

- अधिप्राप्ति के लिए लगने वाले समय को कम करने के लिए वरिष्ठ महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों को बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां।
- वेंडर पंजीकरण के लिए सरलीकृत एसओपी
- स्व-पुर्ननवीनीकरण के साथ पंजीकरण जीवनपर्यन्त वैध है।

विक्रेताओं की प्रत्याशित क्षमता सत्यापन (सीवी) केवल 84 मदों तक ही सीमित है, जहां महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी शामिल है। पंजीकरण विक्रेताओं के स्व-घोषित दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। पंजीकरण स्वत: नवीनीकरण प्रक्रिया के साथ जीवन भर के लिए मान्य है।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)

05

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

- डीम्स रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पहले डीपीएसयू सम्बद्ध किया जाएगा।
- एमएसई हेतु प्रोत्साहन की घोषणा।
- टीआरईडीएस के माध्यम से भुगतान।

i. **डीम्ड पंजीकरण की शुरूआत :** विक्रेता आधार को व्यापक बनाने के लिए, जीएसएल ने डीम्ड पंजीकरण की शुरुआत की है। निविदाओं में अन्य डीपीएसयू, आईएचक्यू, और सीजीएचक्यू और डीक्यूएन (ए) के साथ पंजीकृत विक्रेताओं की स्वत: भागीदारी, जिसने बदले में काफी मूल्य लाभ प्रदान किया है।

ii. सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) से अधिप्राप्ति: एमएसई से अधिप्राप्ति बढ़ाने के लिए 'एनएसआईसी कंसोर्टिया-टेंडर मार्केटिंग स्कीम' के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ जुड़ने वाला जीएसएल पहला डीपीएसयू है।

(क) जीएसएल ने एमएसई के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों का अनावरण किया है:

- ईएमडी की छूट
- टेंडर शुल्क में छूट
- एनएसआईसी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं को सुरक्षा जमा से छूट दी गई है।
- 20% ऑर्डर मूल्य तक 15% की खरीद वरीयता।

(ख) एमएसई विक्रेताओं के माध्यम से अनिवार्य खरीद के लिए एमएसएमई के लिए आरक्षित 358 मदों के अतिरिक्त 18 परियोजना विशिष्ट वस्तुओं की सक्रिय रूप से पहचान की गई।

(ग) प्रकार अनुमोदन शुल्क पर 10% छूट: जीएसएल पहला डीपीएसयू है जिसने एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए ''टाइप अनुमोदन'' प्रमाणन के लिए 10% छूट की पेशकश करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस) के साथ समन्वय किया है।

(घ) जीएसएल ने टर्नकी परियोजनाओं में एमएसई और घरेलू विक्रेताओं को तरलता प्रदान करने के लिए उदारीकृत भुगतान शर्तें स्थापित की हैं। इसके अलावा, इसने एमएसएमई को बैंक गारंटी के बदले 15% तक अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया है।

(ड.) स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, जीएसएल ने पूर्व अनुभव और पूर्व टर्नओवर के संबंध में मानदंडों में ढील देकर 'स्टार्ट-अप पॉलिसी' का अनावरण किया है।

(च) टीआरईडीएस के माध्यम से भुगतान: जीएसएल ने भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के अनुरूप एमएसईएस का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए टीआरईडीएस भुगतान प्रणाली को अपनाया है, जो एमएसई विक्रेता को छूट प्रणाली पर बिल की स्वीकृति के तुरंत बाद भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। जीएसएल ने आरबीआई द्वारा अनुमोदित रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) इकाई के साथ करार किया है।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी)

06

मिधानी

- 25 लाख रूपए से कम के सभी टेंडरों हेतु अर्नेस्ट मनी की छूट।
- केन्द्र सरकार पीएसयू को अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपाजिट से छूट।
- अधिप्राप्ति हेतु कम समय।

i. भागीदारी बढ़ाने और आदेशों को समय पर अंतिम रूप देने के लिए सभी कच्चे माल की पेशकश की वैधता की आवश्यकता को 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

ii. वार्षिक आवश्यकता (एक बार) के लिए निविदा की अवधारणा को लागू किया और एल्युमिनियम पेलेट्स/बार्स के लिए जब भी आवश्यक हो मूल्य की खोज को 60 दिनों से 20 दिनों तक खरीद के चक्र के समय को कम कर दिया।

iii. लगभग उच्च मूल्य बहु उपयोगकर्ता मद (इलेक्ट्रोड/इनगॉट मोल्ड्स, बैंड सॉ ब्लेड्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्राइंडिंग व्हील्स, टुंडिश रिफ्रेक्टरी, रेमिंग मास) की पहचान। वार्षिक खरीद मूल्य रु. 36.68 करोड़ ने खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है।

iv. ऑनलाइन एमपीआर/सीपीएआर प्रणाली को प्रोक्योरमेंट लीड टाइम में कमी की दिशा में एक कदम के रूप में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

v. 10 लाख रुपए से अधिक सभी ई-अधिप्राप्ति के लिए रिवर्स ऑक्शन (आरए) लागू किया गया था जिससे लगभग 6 करोड़ रुपयों की भारी लाभ प्राप्त हुई।

vi. सभी सिविल कार्य निविदाओं में, जहां ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के विपरीत काम करता है ऐसे मामलों को संभालने के लिए 'जुर्माना' पर एक नई शर्त शामिल की गई है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)

07

बीईएल

• एमएसएमई आउटरीच के लिए, बीईएल व्यापार प्राप्त करने वाली इलेक्ट्रानिक डिस्काउंट प्रणाली (टीआरईडीएस) पटल और एमएसएमई समाधान और जीईएम के साथ पंजीकृत है।

i. बीईएल ने सफलतापूर्वक दो मॉड्यूल अर्थात ग्राहक बिलिंग प्रबंधन और बिल ट्रैकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय लीड प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। एसएपी आधारित ऑनलाइन सिस्टम का उद्देश्य क्रमशः ग्राहक सेवा और निर्यात व्यापार नेतृत्व प्रबंधन की प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

ii. बीईएल अब संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठन के रूप में 'सीईआरटी-इन' के रूप में सूचीबद्ध है। यह सूचीकरण बीईएल को भारत के विभिन्न सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के आईटी अवसंरचना के भेद्यता आकलन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) सहित संबंधित सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाता है।

आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण

मेक इन इंडिया पहल

आधुनिकीकरण एवं क्षमता निर्माण प्रयास

अधिग्रहण

सेना वायु रक्षा (एएडी)

• कई स्वदेशी रडार को शामिल किया गया है।

पैदल सेना

• विभिन्न शस्त्रों/उपस्करों की अधिप्राप्ति के साथ पैदल सेना की संचालनात्मक क्षमता पर एक विशेष रूप से जोर दिया गया है।

तोपखाना

• भारतीय तोपखाने की आयुधशाला में स्वदेशी शस्त्र का लोकटिंग रडार और अपगन शेयरिंग धनुष, अल्ट्रा लाइट होवित्जर को शामिल करना।

मैकेनाइज्ड फोर्स

• टैंकों और बीएमपी की रात में कार्य करने की क्षमता, रात में युद्ध करने की क्षमता और समर्थता बढ़ाना है।

आर्मी एविएशन

• 6 अपाचे एएच 64 की अधिप्राप्ति के लिए भी एनओएन को मंजूरी दी गई है।

• मौजूदा वित्तीय वर्ष में एएलएच (डब्ल्यूएसआई) और एयरक्राफ्ट रिप्यूलर 4 केएल और एएलएच (डब्ल्यूएसआई) के लिए 20 एमएम टरेट गन गोलाबारूद और अपव्यय मिटाने के लिए 3 संविदा जैसे उन्नत हेलिकॉप्टर (एएलएच)।

सुरक्षात्मक कपड़ों/गियर का सुधार

बुलेट प्रूफ जैकेट (बीपीजे) और बेलेस्टिक हेलमेट की अधिप्राप्ति	• 236138 बीपीजे और 3282214 बेलेस्टिक हेलमेट अधिप्राप्ति के तहत है।
विशेष पहाड़ी वस्त्र उपस्कर मद का स्वदेशीकरण	• कुछ मदों का स्वदेशीकरण किया गया है, जिससे 30 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष बचत हुई है।
सीमा पर अवसंचरना विकास	• संक्रियाओं का संचालन करने और क्षेत्र की संपूर्ण विकास में सहयोग करने के लिए भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए निधियों का आवंटन किया गया।

अन्य उपाय

क्षमता मूल्याकंन मार्गदर्शन

• आगामी पोत निर्माण परियोजनाओं की प्रगति के लिए विभिन्न भारतीय एन्टिटी के लिए क्षमता मूल्यांकन दिशा निर्देश प्रख्यपित किए गए है।

'के' प्रक्रिया पर संशोधित अध्याय

• दो उपवर्ग जैसे मेक-1 (प्रोटोटाइप तैनाती की लागत के 90% तक सरकारी निधि के लिए प्रावधान के साथ) और मेक-।। (प्रोटोटाइप पूर्व तैनाती के लिए सरकार द्वारा कोई निधि नहीं दी जा रही है।)

डब्ल्यूटीजी के लिए एनओसी

• राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में डब्ल्यूटीजी के स्थ्ज्ञापना के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मानचित्र पर 'गो' और 'नो गो' निर्धारित किया गया क्षेत्र।

• आईएएफ द्वारा गठित 53 आईएएफ एयर फील्ड के लिए कलर कोडेड जोनिंग मैप (सीसीजेडएम)

एसएसीएसए

• वायु मुख्यालय और फील्ड यूनिट के बीच ऑनलाइन निकासी और डिजीटल अंतरण सुनिश्चित करके निकासी /निराकरण समय के लिए आईएएफ ने एक नया एसएसीएसए वेब पोर्टल का विमोचन किया है।

इलेक्ट्रानिक नेवीगेशन चार्ट (ईएनसी) की ऑनलाइन हस्तांतरण और अपडेट

• आईसीजी के अंदर ईएनसी की सुरक्षित ऑनलाइन हस्तांतरण के लिए एनएचओ, देहरादून के साथ समन्वय में प्रक्रिया तैयार की गई है और सफल परीक्षणों के माध्यम से इसे वैध किया गया है।

ओपी एक्टिविटी रिटर्न के सार का ई-रिटर्न

• सीजीएचक्यू द्वारा विकसित ओपी एक्टिविटी रिटर्न के सार का ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रोग्राम।

आरओसी /आरओएस द्वारा सम्पर्क विश्लेषण

• भारतीय समुद्री क्षेत्र अथवा ईईजेड में चलने वाले मर्चेंट पोत अथवा मछली पकड़ने वाले पोतों का ऑनलाइन रखरखाव और विश्लेषण किया जा रहा है। अवलोकन किया गया/ विश्लेषण किए गए डाटा का रखरखाव सीएसएन के डाटा बेस में की जाती है।

मरम्मत/रखरखाव/सर्विसिंग विकास

(क) मरम्मत/सर्विसिंग और आपूर्ति प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए आईएएफ के अनुरूप मैसर्स एचएएल डिवीजनों को भुगतान की निश्चित मूल्य कोट (एफपीक्यू) प्रणाली को आईसीजी के लिए लागू किया गया है।

(ख) मैसर्स ईसीआईएल हैदराबाद आईसीजी डोर्नियर बेड़े पर स्थापित सीवीआर सिस्टम के लिए ओईएम है, इसलिए सीवीआर सिस्टम के पुर्जों की मरम्मत/सर्विसिंग और आपूर्ति मेसर्स ईसीआईएल के माध्यम से की जा रही है। मरम्मत/सर्विसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिएमैसर्स ईसीआईएल के साथ मरम्मत दर अनुबंध (आरआरसी) संपन्न किए गए हैं।

(ग) आईसीजी विमानन बेड़े के ओईएम होने के नाते मैसर्स एचएएल के माध्यम से विमान प्रणालियों और पुर्जों के स्वदेशीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। हालांकि विमानन क्यूए/प्रमाणन एजेंसियों द्वारा निरीक्षण/मंजूरी की सुविधा के लिए, अपेक्षित परीक्षण एकीकरण उड़ान परीक्षण आदि करने के लिए संबंधित मैसर्स एचएएल डिवीजनों को आईसीजी विमान आवंटित किए जा रहे हैं।

***

रक्षा उत्पादन विभाग

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE

रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी)

रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) की स्थापना नवंबर, 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों/प्रणालियों/ प्लेटफार्मों/उपस्करों का उत्पादन करने के लिए एक व्यापक अवसंरचना के विकास के उद्देश्य से की गई। पिछले वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपस्करों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और निजी रक्षा उद्योग को भी सहायता प्रदान की है।

डीपीएसयू द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उत्पाद

विभाग यह मानता है कि सही अर्थों में आत्मनिर्भरता केवल तभी संभव है जब देश के पास प्रौद्योगिकी भी हो। इसलिए यह विभाग देश के रक्षा उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और बौद्धिक संपदा सृजन को प्रोत्साहित करता रहा है।

रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने हेतु किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश ने रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में व्यापक रेंज की क्षमता हासिल की हैं। जहां तक भू-प्रणालियों का संबंध है, इनमें आर्टिलरी गन्स, टैंक, विभिन्न प्रकार के भारी वाहन, सुरंग संरक्षित वाहन, विभिन्न प्रकार के लघु शस्त्र, बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट सहित बख्तरबंद सामग्री, गोलाबारूद, प्रॉपलैंट एवं विस्फोटक इत्यादि शामिल हैं। जहां तक एयरो-प्रणालियों का संबंध है, चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, 3-5.5 टन श्रेणी के हेलिकॉप्टर, ट्रेनर विमान, विभिन्न प्रकार की मिसाइलें शामिल हैं और नौसैन्य प्रणालियों में अपतटीय गश्ती जलयान, कार्वेट, फ्रिगेट, विध्वंशक, विमान वाहक, पनडुब्बियां इत्यादि सहित सभी प्रकार के नौसैन्य जलयानों का व्यावहारिक रूप से विनिर्माण करने की क्षमता देश में ही सृजित की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा उत्पादन मूल्य में वृद्धि

रक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और भारत को रक्षा विनिर्माण में एक वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से रक्षा उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है और उत्पादन रेंज को व्यापक बनाया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए उत्पादित किए जा रहे कई उत्पादों एवं उपस्करों के अलावा अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलों के जरिए कई प्रमुख उत्पादों का विकास किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के उत्पादन मूल्य (वीओपी) में वृद्धि को निम्नलिखित आंकड़ों में दर्शाया गया है :

भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात आयात प्रोफाइल

विभिन्न देशों से प्राप्त होने वाले प्रश्नों सहित निर्यात संबंधी कार्रवाई करने के बारे में समन्वय एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने और रक्षा निर्यात संवर्धन के लिए निजी एवं सार्वजनिक एवं दोनों ही क्षेत्रों की कंपनियों की सहायता करने के लिए जुलाई, 2017 में निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।

फरवरी, 2019

एक ऑन-लाइन पोर्टल की शुरूआत की गई जिसके द्वारा विभिन्न पणधारियों से प्राप्त होने वाली निर्यात लीडस को ऐसे भारतीय रक्षा निर्यातकों के पास प्रत्यक्ष रूप से प्रेषित किया जा रहा है जिनका पंजीकरण इस पोर्टल पर है

भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात-आयात प्रोफाइल में सुधार हेतु किए गए उपाय

रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 (31 दिसंबर, 2019 तक) के दौरान निजी रक्षा उद्योगों को 36 आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं।

रक्षा औद्योगिक गलियारे

बजट घोषणा (2018-19) के अनुसरण में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे, उत्तर प्रदेश में एक और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । उसके बाद उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे में 6 नोडों बिन्दुओं अर्थात आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर एवं लखनऊ की पहचान की गई है। इसी प्रकार तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए 5 नोडों अर्थात चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सेलम एवं तिरूचिरापल्ली की पहचान की गई है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी)/सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) और निजी उद्योगों द्व ारा उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे एवं तमिलनाडु रक्षा गलियारे के लिए क्रमशः लगभग 3700 करोड़ रुपए एवं 3100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। दिसंबर, 2019 तक विभिन्न संगठनों द्वारा 1000 करोड़ रु. से अधिक का कुल निवेश पहले ही किया जा चुका है।

अब तक उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के विभिन्न नोडों पर पणधारियों की छः-छः परामर्श बैठकों का

आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा, इन दो रक्षा गलियारों के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

रक्षा और अंतरिक्ष के लिए एक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना

रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार (आईडेक्स) एक योजना है जिसका निर्माण स्टार्टअप्स द्वारा नवाचार करने, प्रौद्योगिकी का विकास करने एवं रक्षा और अंतिरक्ष क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के सहयोग से किया गया है।

प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2018 में आईडेक्स, जो देश में इस प्रकार की पहली पहल है, का शुभारंभ किया गया था। आईडेक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, निजी नवाचारकों, आरएंडडी संस्थानों एवं अकादमियों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा एवं अंतरिक्ष में नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य करने के लिए उनको अनुदान/वित्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान करना है। यह उम्मीद है कि भारत रक्षा एवं अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अपने जीवंत स्टार्ट अप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठा सकता है।

58 विजेता

डीआईएससी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 58 विजेताओं की पहचान की गई है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित क्षमताओं का विकास करना

रक्षा उत्पादन विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के सामरिक महत्व का अध्ययन करने तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए फरवरी, 2018 में श्री एन. चन्द्रशेखरन, अध्यक्ष, टाटा सन्स की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया था।

इस कार्यबल ने जून, 2018 में रक्षा मंत्रालय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। कार्यबल की सिफारिशों और विभिन्न संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों/फीडबैक के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने फरवरी, 2019 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

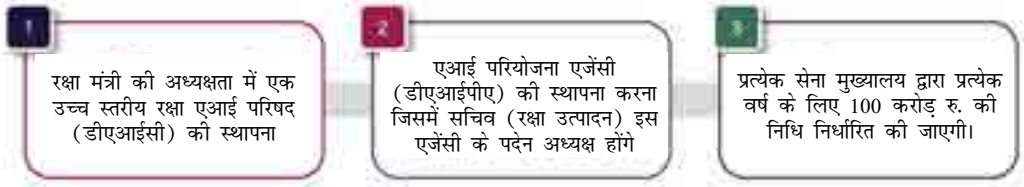

i. रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय रक्षा एआई परिषद(डीएआईसी) की स्थापना करना, जिसमें तीनों सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, सचिव(रक्षा उत्पादन), सचिव (डीआरडीओ), वित्तीय सलाहकार (डीएस), राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयकर्ता, सीआईएससी, उद्योग एवं अकादमियों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। डीएआईसी को रक्षा में एआई के क्रियान्वयन के लिए प्रचालन फ्रेमवर्क, नीति स्तर के बदलाव एवं संरचनात्मक सहायता को समर्थ बनाने और विकास या निर्माण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है।

ii. रक्षा एआई परियोजना एजेंसी(डीएआईपीए) की स्थापना करना जिसमें सचिव(रक्षा उत्पादन) इस एजेंसी के पदेन अध्यक्ष होंगे और तीनों सेनाओं, आईडीएस, डीआरडीओ, डीपीएसयू, अकादमियों और उद्योग से सदस्य लिए जाएंगे। डीएआईपीए का रक्षा एआई परिषद (डीएआईसी) के लिए एक सचिवालय के रूप में कार्य करने के अलावा, सभी सेनाओं और अन्य रक्षा संगठनों में एआई आधारित प्रणालियों में और एआई आधारित प्रक्रियाओं के डिजाइन, विकास एवं उत्पादन को सक्षम बनाने का प्रमुख दायित्व होगा। तदनुसार, डीएआईपीए का मार्च, 2019

में गठन किया गया था।

iii. प्रत्येक सेना मुख्यालय द्वारा अपने वार्षिक बजटीय आबंटनों से पांच (05) वर्षों के लिए एआई विशिष्ट अनुप्रयोग विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रु. की निधि निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, एआई परियोजनाएं, एआई अवसंरचना स्थापित करने, एआई से संबंधित आंकड़ों का समाशोधन करने एवं इन्हें तैयार करने, रक्षा मंत्रालय के संगठनों में क्षमता निर्माण करने इत्यादि सहित एआई कार्यबल द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए रक्षा मंत्रालय द्व ारा प्रत्येक वर्ष पांच (05) वर्षों के लिए 100 करोड़ रु. का बजटीय आवंटन किया जाएगा।

इसके अलावा, एआई आधारित उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का उनके प्लेटफार्मों के अनुसार सृजन करने और इसके लिए उपयुक्त निधियां निर्धारित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और ओएफबी के लिए एक त्रि-वर्षीय (2019-2022) रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। एआई रोड मैप के अंतर्गत कुल 25 एआई समर्थित परियोजनाओं की पहचान की गई है। 6 उत्पादों के लिए प्रोटोटाइप का विकास किया गया है और इनके परीक्षण चल रहे हैं।

रक्षा डीपीएसयू एवं ओएफबी द्वारा विकास के अधीन कुछ एआई आधारित उत्पाद/प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं

डीपीएसयू/ओएफबी	एआई आधारित उत्पाद/प्रौद्योगिकियां
बीईएल	1. आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली घटनाओं (टीआईआई), आतंकवादियों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं (टीसीए) के संबंध में आतंकवादी गतिविधि विश्लेषण और सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण के भाग के रूप में अपराध विश्लेषण। 2. मानव चेहरा पहचान की अवधारणा का प्रमाण।
एमडीएल	1. मैनुअल रेडियोग्राफी के स्थान पर एडवांस्ड फेज्ड अर्रे तकनीक का उपयोग करके रोबोटिक वेल्ड निरीक्षण। 2. रिमोट द्वारा चालित वाहन(आरओवी) का डिजाइन एवं प्रोटोइपिंग।
जीआरएसई	1. मानवरहित सतह जलयान(यूएसवी)।
बीईएमएल	1. डम्प ट्रकों पर स्लीप/फटीग्ड ऑपरेटर अलर्ट प्रणाली। 2. बर्फ हटाने के कार्य के लिए आटोनोमस डोजर।

जीएसएल	1. शिपबोर्ड इक्विपमेंट कंडीशन मॉनीटरिंग सिस्टम।
एचएसएल	1. मानवरहित अंडरवाटर वाहन।
बीडीएल	1. स्मार्ट काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम(सीएमडीएस) 2. उत्पाद सहायता के लिए स्मार्ट असिस्टेंट (एआई समर्थित 24◦7 चौट बोट)।
मिधानी	1. ऑन-लाइन प्रोसेस नियंत्रण के साथ मिश्र धातुओं का विकास एवं सेंसर आधारित यंत्र प्रणाली के जरिए निर्णय।
ओएफबी	1. ड्रोन समर्थित सुरंग संरक्षी वाहन।

अन्य प्रमुख पहलें

अन्य प्रमुख पहलें

रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं। कुछ प्रमुख पहलों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

क) संशोधित मेक-।। प्रक्रिया :

सरकार ने पूंजीगत मदों की रक्षा आपूर्ति में उद्योग की अधिक भागीदारी समर्थ बनाने के लिए फरवरी, 2018 में एक संशोधित मेक-।। प्रक्रिया को अनुमोदन प्रदान किया। नई मेक-।। प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

नई मेक-II प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं

31 दिसंबर, 2019 तक हुई प्रगति

स्व-प्रेरणा प्रस्ताव :

संशोधित मेक-II के अंतर्गत एक नई विशेषता शुरू की गई है जो उद्योग को सेनाओं के प्रयोगार्थ स्वप्रेरणा प्रस्ताव देने में समर्थ बनाता है। पूंजीगत अर्जन के अंतर्गत 'स्व-प्रेरणा' प्रस्तावों पर विचार

करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जून, 2018 में जारी की गई है। सेनाएं प्रस्ताव की जांच करती हैं और यदि वे इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पाती हैं तो वे मेक-।। प्रक्रिया के अंतर्गत इसका विकास कर सकती हैं।

यह स्व-प्रेरणा प्रस्ताव नई तरह का है और पहली बार उद्योग को सेनाओं के प्रयोगार्थ प्रस्तावों की पहल करने में समर्थ बनाता है। इस स्व-प्रेरणा का स्टार्ट-अप्स/उद्योगों द्वारा विकसित की जा रही कच्ची सामग्रियों सहित नई प्रौद्योगिकियों/नए उत्पादों के लिए विशेष महत्व है।

तीनों सेनाओं ने स्व-प्रेरणा प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। इन स्व-प्रेरणा प्रस्तावों को वेबसाइट makeinindiadefence-gov-in के जरिए ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। 31 दिसंबर, 2019 तक कुल 44 परियोजनाओं में से ऐसे 13 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ख)ओएफबी/डीपीएसयू स्तर पर मेक-।। का क्रियान्वयनः

रक्षा मंत्रालय द्वारा ओएफबी/डीपीएसयू में मेक-।। प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए फ्रेम वर्क फरवरी, 2019 में जारी किया गया था। इस फ्रेम वर्क के उद्देश्य में अन्य बातों के साथ-साथ मेक-।। (डीपीपी 2016 का अध्याय-।।।-ए क) की पात्रता मानदंड में छूट, उद्योग द्वारा स्व-प्रेरणा के तहत सुझाए गए प्रस्तावों, ओएफबी एवं डीपीएसयू की अधिप्राप्ति नियमावलियों में न्यूनतम दस्तावेजों पर विचार करने जैसी विशेषताओं को शामिल करना है ताकि मदों विशेषकर नियमित रूप से आयात की जा रही मदों के स्वदेशीकरण के लिए परियोजनाएं संचालित करने हेतु उन्हें सशक्त बनाया जा सके।

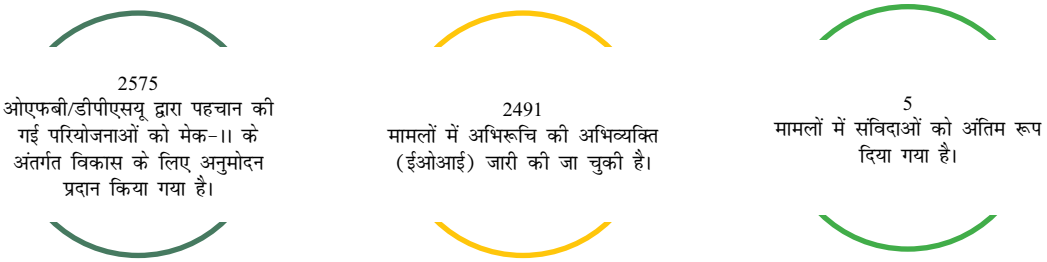

मेक -।। के अंतर्गत प्रगति

च. औद्योगिक लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित बनानाः रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की गई पहल के आधार पर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाया गया है:-

i. गृह मंत्रालय ने दिनांक 01 नवंबर, 2018 की अधिसूचना के तहत शस्त्र नियम 2016 (तीसरा संशोधन) अधिसूचित किया था जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि अग्नेयास्त्र (12.7 मिमी तक कैलीबर के लघु शस्त्र एवं गोलाबारूद और संबद्ध मदें) और उनके केवल निम्नलिखित भाग शस्त्र अधिनियम, 1959/शस्त्र नियम 2016 के अंतर्गत लाइसेंस योग्य हैं।

क. बैरल	ख. सिलेंडर
ग. बोल्ट	घ. ब्रीच ब्लॉक
ङ. स्लाइड	च. फायरिंग पिन
छ. फ्रेम या रिसिवर	ज. एक्सट्रैक्टर
झ. हैमर/स्ट्राइकर	

ii. इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अपनी दिनांक 19 मई, 2017 की पूर्व की अधिसूचना एसओ 1636 (ई) के अधिक्रमण में दिनांक 14 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना के तहत शस्त्र अधिनियम/शस्त्र नियम के अंतर्गत सचिव (डीपीआईआईटी) को प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस वाली मदों की अनुसूची को संशोधित किया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार, ''टैंक एवं अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन'' एवं ''शस्त्र एवं गोलाबारूद और रक्षा उपस्करों की संबंधित मदें; 12.7 मिमी एवं इससे अधिक कैलिबर के अन्य लघु शस्त्र के अलावा'' शस्त्र अधिनियम, 1959/शस्त्र नियम, 2016 के अंतर्गत अन्य शस्त्र लाइसेंस योग्य हैं।

iii. डीआईपीपी ने दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रेस नोट 1(2019 श्रृंखला) के तहत अन्य रक्षा मदों अर्थात ''रक्षा विमानों'' एवं ''सभी प्रकार के युद्ध पोतों'' को आई(डीएंडआर) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अन्य लाइसेंस योग्य रक्षा मदों के साथ-साथ उक्त नियमों के अंतर्गत उनके शामिल नहीं होने के कारण शस्त्र नियम, 2016 से हटा दिया है।

iv. इसके अलावा, डीपीआईआईटी ने प्रेस नोट 2(2019 श्रृंखला) के तहत दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रेस नोट 1(2019 श्रृंखला) के संदर्भ में अधिसूचित किया है कि रक्षा क्षेत्र में किसी कलपुर्जे अथवा उपसाधनों के विनिर्माण के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस की उस समय तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि वे दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रेस नोट 1(2019 श्रृंखला) के किसी अनुबंध में विशेष रूप से सूचीबद्ध न हों।

v. इस प्रकार रक्षा उत्पाद सूची युक्तिसंगत हो गई है और इस उदारीकरण के कारण छोटी हो गई है।

इन उपायों के परिणास्वरूप, रक्षा विनिर्माण के लिए जारी औद्योगिक लाइसेंसों (आईएल) की संख्या में अनवरत रूप से वृद्धि हुई है। सरकार ने दिसंबर, 2019 तक निजी कंपनियों को रक्षा मदों की व्यापक रेंज का विनिर्माण करने के लिए 460 औद्योगिक लाइसेन्स जारी किए हैं। यह मार्च, 2014 में मौजूद लाइसेंसों की संख्या से दोगुना है। गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस को दर्शाने वाला बार चार्ट इस प्रकार है:-

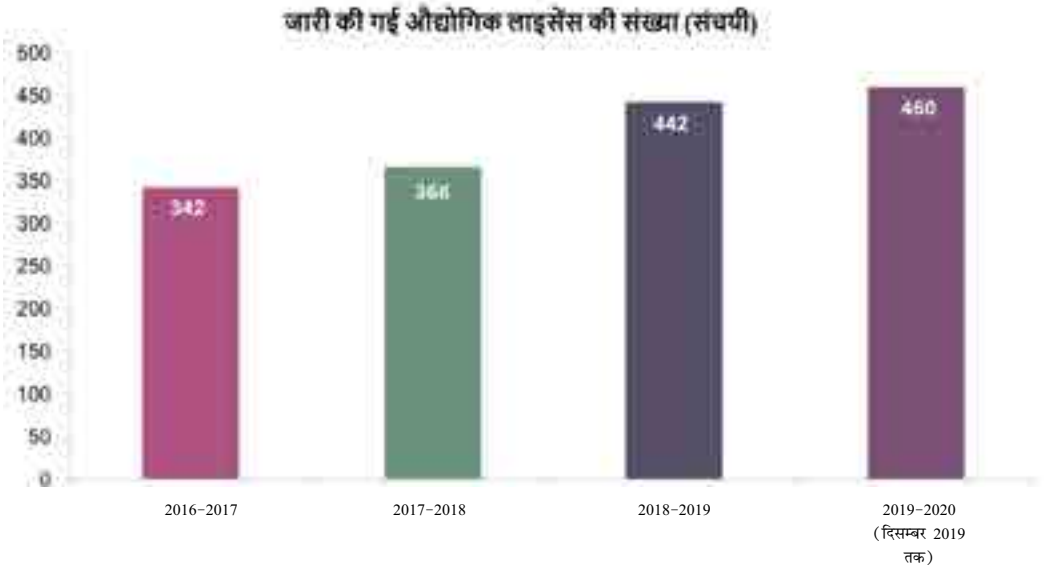

छ. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र की 79 कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक (अर्थात दिसंबर, 2019 तक) 3155 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2014 के बाद रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में 1834 करोड़ रु. से अधिक के एफडीआई प्राप्त होने की सूचना दी गई है।

ज. रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ (डीआईसी): सभी रक्षा उद्यमियों के लिए एक मित्र के रूप में काम करने के लिए डीआईसी की शुरूआत जनवरी, 2018 में की गई थी। डीआईसी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के अवसरों से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए एकल बिन्दु संपर्क के रूप में काम करता है। रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ रक्षा मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही नीतियों एवं परियोजनाओं से संबंधित संभावित निवेश और प्रश्नों के संबंध में इच्छुक निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करता है। डीआईसी ने रक्षा आवश्यकताओं और उनसे संबंधित प्रश्नों से निपटना उद्योगों के लिए सरल बना दिया है। डीआईसी

से https:èkèkdefenceinvestorcell.gov.in पर ऑनलाइन संपर्क किया जा सकता है। डीआईसी को उद्योग से एक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले एमएसएमई के लिए यह विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है क्योंकि यह डीपीएसयू/ओएफबी/एसएचक्यू से संबंधित उनकी शिकायतों का समाधान करता है।

उद्योग अधिकांशत: एमएसएमई से कुल 703 प्रश्न/मामले प्राप्त हुए हैं और डीआईसी द्वारा इनको विधिवत् रूप से निपटाया गया है।

डीआईसी अपने प्रश्नों/मामलों के लिए 2 दिन से कम प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित कर रहा है रहा है और प्रश्न/मामले का सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए औसत समय 7 दिनों से कम है।

झ. रक्षा उत्पादन सूचना प्रौद्योगिकी (डीपीआईटी) प्रभाग:- ओएफबी एवं डीपीएसयू सहित डीडीपी में आईटी से संबंधित पहलों का क्रियान्वयन करने के लिए डीपीआईटी प्रभाग का सृजन किया गया है। डीपीआईटी प्रभाग ने अन्य चालू आईटी परियोजनाओं के अलावा, रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग (डीओएमडब्ल्यू) पोर्टल, डीडीपी एवं रक्षा विभाग डैशबोर्ड के विकास में प्रमुख भूमिका निभायी है।

- डीओएमडब्ल्यू पोर्टल:- विदेशी ओईएम द्वारा ऑफसेट दावे प्रस्तुत करने और डीओएमडब्ल्यू और सीजीडीए द्वारा तदनुरूपी प्रोसेसिंग/लेखापरीक्षा/सत्यापन करने के लिए डीओएमडब्ल्यू पोर्टल को 01 मई, 2019 से संचालित किया गया है। वर्ष के दौरान ओईएम द्वारा शत-प्रतिशत ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण एवं ऑफसेट दावों का सत्यापन प्राप्त किया गया है।

इसके अलावा, ओईएम द्वारा प्रस्तुति प्रक्रिया एवं डीओएमडब्ल्यू द्वारा स्वीकृति को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों एवं एक डैशबोर्ड का विकास भी किया गया है।

भारतीय ऑफसेट भागीदारों (आईओपी) के सत्यापन और ऑफसेट बैंकिंग प्रस्तावों की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से इस परियोजना के द्वितीय चरण पर इस समय काम चल रहा है।

ख. डीडीपी डैशबोर्ड

रक्षा मंत्री जी द्वारा डीडीपी डैशबोर्ड का 26 जुलाई, 2019 को शुभारंभ किया गया था। इस विभाग की विभिन्न पहलों एवं योजनाओं की प्रभावी निगनानी में सहायता करने के लिए इस डैशबोर्ड को डिजाइन किया गया है।

डैशबोर्ड में रक्षा निर्यात, रक्षा ऑफसेट, रक्षा उत्पादन, फाइल किए गए आईपीआर (मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति), रक्षा परियोजनाओं में मेक इन इंडिया, रक्षा में कार्यरत स्टार्ट अप्स, रक्षा गलियारों में निवेश और रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजनाओं सहित विभाग की प्रमुख पहलों के बारे में प्रगति का विवरण है। जनता के लिए यह डैशबोर्ड ''ddpdashboard.gov.in'' पर उपलब्ध है।

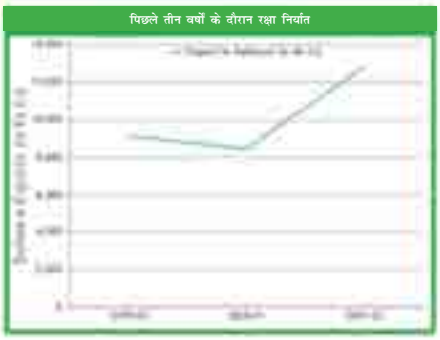

ग. **डेफएक्सपो 2020 वेबसाइट:** रक्षा मंत्री जी द्वारा डेफएक्सपो 2020 वेबसाइट का शुभारंभ 30 सितंबर, 2019 को किया गया था। इस वेबसाइट पर प्रदर्शनी में भाग लेने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और पहले आओ पहले पाओ आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शनी स्थल बुक कराने की सुविधा प्रदान की गई थी।

इस वेबसाइट पर दूतावास के अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, मीडिया, प्रतिनिधिमंडलों एवं व्यापार आगंतुकों के लिए भी सेवा प्रदान की गई थी। प्रदर्शनी स्थल की बुकिंग, भुगतान, सम्मेलन एवं बी2बी बैठक, सम्मेलन हॉलों की बुकिंग, व्यापार आगंतुकों के लिए टिकट, बैज एवं प्रिंटिंग के लिए डाटा इनपुट सहित सभी लेन देन ऑनलाइन किए गए थे।

इस वेबसाइट पर टेलीफोन एवं ई-मेल सहायता के जरिए ग्राहक सहायता सुविधा प्रदान की गई थी। रक्षा मंत्री जी द्वारा 27 दिसंबर, 2019 को वर्तमान अनुसूची के ब्यौरे, प्रदर्शनी में भाग लेने वाले और उत्पादों के ब्यौरे, स्थल मानचित्र, प्रकाशन, टिकट, मौसम एवं प्रायोजक की सूचना देने वाले एक मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया था। सामान्य फीड बैक, स्थल की स्वच्छता के बारे में फीडबैक और संपर्क अधिकारियों को शामिल करने के लिए एक व्यापक फीडबैक माड्यूल भी शामिल किया गया था।

ञ. मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति (एमआरजीएस) :

क. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग ने एक मिशन शमिशन रक्षा ज्ञान शक्तिश की अप्रैल 2018 माह में शुरूआत की है जिसका प्राथमिक उद्देश्य आईपीआर पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार डीपीएसयू एवं आयुध निर्माणियों में 'आईपी संस्कृति को बढ़ावा देना' और बौद्धिक संपदा के सृजन को बढ़ावा देना है।

ख. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग ने अप्रैल 2018 में एक बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा (आईपीएफ) प्रकोष्ठ के रूप में 'पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता' का सृजन करके इस मिशन के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी है।

ग. पहले साल में ही रोड मैप में यथा निर्धारित प्रगति बहुत महत्वपूर्ण एवं उत्साहवर्धक है।

17938 कर्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया	• सभी डीपीएसयू/ओएफबी/डीजीक्यूए से कुल 17938 कर्मिकों को चयनित 'मास्टर प्रशिक्षकों' के एक दल द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिन्हें इस प्रयोजनार्थ राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्था (आईजीएनआईआईपीएम) में परीक्षण दिया गया था।
1,082 आईपीआर आवेदन	• आज की तारीख तक डीपीएसयू/ओएफबी द्वारा आवेदन किए गए हैं।
कार्य योजना	• एक व्यापक कार्य योजना 2019-20 तैयार की गई है और सेना-नौसेना-वायुसेना सहित सभी पणधारियों के लिए प्रख्यापित की गई है।
समझौता ज्ञापन	• अनुमोदित एमआरजीएस कार्य योजना 2019-20 के अनुसार आईपीएफ प्रकोष्ठ की क्षमता का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 9 जुलाई, 2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
आईपीआर पर नीति	• ''सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों और आयुध निर्माणियों द्वारा बौद्धिक सम्पदा (आईपी) के सृजन एवं प्रबंधन'' के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक नीति तैयार की गई है और सभी पणधारियों के लिए 27 दिसम्बर, 2019 को प्रख्यापित की गई है।

'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की उपलब्धि' (अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2019 की अवधि)

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के अधीन आयुध निर्माणियां

भारतीय आयुध निर्माणियां 41 उत्पादन इकाइयों और अनेक प्रशिक्षण और अनुसंधान इकाइयों के साथ सबसे पुराना और विशाल औद्योगिक स्थापना हैं जो आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के अधीन कार्य कर रही है और जिसका प्राथमिक लक्ष्य सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक युद्धक्षेत्र उपस्करों से सुसज्जित करने में आत्मनिर्भता प्राप्त करना है।

आयुध निर्माणियों के मुख्य कौशल

शस्त्र	छोटे मध्यम और बड़े कैलिबर के शस्त्र एवं मोर्टार उपस्कर
गोलाबारूद, विस्फोटक एवं प्रणोदक	छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोलाबारूद, मोर्टार नग, सिग्नलिंग और संबंधित स्टोर्स, राकेट एवं एरियल बम, फ्यूज, विस्फोटक, रसायन एवं प्रणोदक
सैन्य वाहन	ट्रक, सुरंग रोधक और विशेष सुरक्षा वाहन
बख्तरबंद वाहन	टैंक और इसके वैरिएंट, ब्रिज लेइंग टैंक (बीएलटी), बख्तरबंद कार्मिक वाहन (एपीवी) एवं इंजिन
यंत्र एवं आप्टिकल उपकरण	नाइट एंड डे विजन साइट एवं उपस्कर
पैराशूट	ब्रेक पैराशूट, मैन ड्रापिंग एवं सप्लाई ड्रापिंग पैराशूट
ट्रूप कंम्फर्ट एवं सामान्य स्टोर्स	टेंटेज, वस्त्र, निजी उपस्कर, ब्रिज, बोट, केबल आदि।

समग्र स्वदेशी मात्राः स्वदेशी विक्रेताओं और शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयुध निर्माणियों ने अनुसंधान और विकास में निरंतर प्रयासों के माध्यम से अपनी उत्पाद श्रृंखला में स्वदेशीकरण के अत्यंत उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में, कुल स्वदेशी मात्रा 91 प्रतिशत है और इसे और अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आंतरिक अनुसंधान एवं विकास: पिछले दशक में आंतरिक आरएंडडी पर निरंतर बल देने से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और वर्तमान में ओएफबी के कुल उत्पादन का लगभग 23 प्रतिशत आरएंडडी परियोजनाओं से प्राप्त हो रहा है।

- दिनांक 16 अगस्त 2019 को ओएफबी और सीएसआईआर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे ओएफबी को नई आरएंडडी परियोजनाओं को शुरू करने में आसानी होगी।

- ओएफबी की 155 एमएमएक्स 45 कैलिबर धनुष गन ने भारतीय थलसेना द्वारा संचालित दीर्घकालीन फायरिंग परीक्षण को पूरा कर लिया है।
- 06 गन दिनांक 8 अप्रैल 2019 को थलसेना को सौंप दी गई है।

बीएमपी।। अपग्रेड का प्रयोक्ता से सहायता तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एयरोस्पेस आयुध संस्था (एएसओई) द्वारा मिशन "चंद्रयान-2" में ओएफबी के योगदान की प्रशंसा की गई थी।

आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन: ओएफबी ने संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए 2019-20 में (15 नवंबर, 2019 तक) 588 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

निर्यात: वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमआईएल/नाटो मानकों के अनुरूप ओएफबी उत्पादों के विनिर्माण द्वारा आयुध निर्माणियों में विभिन्न रुपांतरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान गोलाबारूद और सहायक मदों की आपूर्ति के लिए ओएफबी ने 45.75 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 315 करोड़ रुपए) का एक सबसे बड़ा निर्यात आर्डर प्राप्त किया है और पहली खेप सुपुर्द की जा चुकी है।

हरित ऊर्जा: ओएफबी हरित ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और विभिन्न आयुध निर्माणियों में 80.67 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

मुख्य उपलब्धियां

ओएफवी द्वारा विकसित नई पीढ़ी की आर्टिलरी गन प्रणाली	''धनुष'' गन के 6 नग की प्रथम खेप दिनांक 8 अप्रैल 2019 को गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर द्वारा भारतीय थलसेना को सौंप दी गई थी।
भारत का प्रथम लूनर लैंडर	''चन्द्रयान-2'' को दिनांक 22 जुलाई, 2019 को जीएसएलवी एमके-।।। -एम-। द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ओएफबी ने आयुध निर्माणी, भंडारा द्वारा आपूर्ति किए गए इसके उत्पादों के माध्यम से अभियान में योगदान दिया।
उच्च विस्फोटक निर्माणी, खड़की	गोल्डन पीकॉक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पुरस्कार 2019 का विजेता घोषित किया गया है।
बीएमपी ।। अपग्रेड का प्रयोक्ता से सहायता प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण	जून 2019 में सफलतापूर्ण हो गया था। इसमें स्वचालित लक्ष्य निगरानी और कमांडर के लिए कंप्यूटरीकृत अग्नि नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित पैनोरेमिक साइट के साथ रात्रि में मिसाइल फायर करने की क्षमता है।

इंडो-रशियन राइफल प्रा.लि. (आईआरआरपीएल): भारत में एके-203 समेत एके श्रृंखला की असॉल्ट राइफलों और अन्य छोटे हथियारों के उत्पादन के लिए दिनांक 18 फरवरी 2019 को भारत गणराज्य और रूसी संघ के बीच हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी करार (आईजीए) के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) एवं जेएससी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट (आरओई) और जेएससी कन्सर्न कलशनिकोव(सीके) के साथ एक संयुक्त कंपनी (इंडो-रशियन राइफल्स प्रा. लि.) को संस्थापित किया गया है।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं और गृह मंत्रालय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संयुक्त कंपनी 7,50,000 नग असॉल्ट राइफल में से 75,000 प्रति वर्ष की दर से विनिर्माण करेगी। करार पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 32 माह की समयावधि के भीतर उत्पादन प्रणाली पूर्ण रूप से स्वदेशीकृत हो जाएगी।

उत्पादन का मूल्य

(मूल्य करोड़ रु. में)

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31 दिसंबर, 2019) तक
14825	14127	12764	5437

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए)

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्यरत एक अंतर-सेवा संगठन है। डीजीक्यूए सभी रक्षा स्टोर्स और थलसेना, नौसेना (नौसैनिक अर्मामेंट को छोड़कर) के लिए आयातित और स्वदेशी दोनों उपस्करों तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माणियों से अधिप्राप्त वायुसेना के लिए सामान्य प्रयोक्ता मदों की गुणवत्ता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है।

उपलब्धियां

- **रक्षा निर्यात संवर्धन योजना**

क. रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा निर्यात संवर्धन योजना शुरू की गई थी। यह योजना भावी रक्षा निर्यातकों को वैश्विक रूप से उनके उत्पादों के विपणन में सुधारने के लिए रक्षा उपस्करों/प्रणालियों के संबंध में डीक्यूए/डीजीएक्यूए/डीजीएनएआई और डीडीपी द्वारा अधिसूचित अन्य एजेंसियों से ''सैन्य उपयोग के लिए अनुकूल'' अथवा ''भावी भारतीय रक्षा निर्यातक/विनिर्माता द्वारा प्रदान किए गए क्यूआर के प्रति परीक्षित एवं प्रमाणित'' की सूचना देने वाले प्रमाण पत्र के निवेदन के लिए दो विकल्प प्रदान करती है। 'रक्षा निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत प्रमाणन, परीक्षण और प्रमाणन' के लिए एसओपी दिनांक 6 मार्च 2019 को प्रख्यापित की गई है।

ख. इस योजना के अंतर्गत दिनांक 8 अक्तूबर, 2019 को मैसर्स भारत फोर्ज लि. नई दिल्ली और मैसर्स लार्सन एवं टुब्रो लि., मुम्बई को ''भारतीय थलसेना के लिए अनुकूल'' उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस)

क. भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया' पहल के एक भाग के रूप में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में विनिर्माण अवसंरचना के विकास के लिए उच्च वरीयता प्रदान की है। एमएसएमई, स्टार्ट अप्स और अन्य उद्योगों के लिए 'अत्याधुनिक' परीक्षण अवसंरचना तक पहुंच की कमी घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक है। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (डीटीआईएस) में रक्षा उपस्करों/प्रणालियों के परीक्षण की भावी आवश्यकता को पूरा करने और विद्यमान रक्षा परीक्षण अवसंरचना के संवर्धन के लिए भी 6 से 8 डीटीआई की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

ख) डीटीआईएस के संचालन के लिए समन्वयक के रूप में डीजीक्यूए को नामित किया गया है। डीटीआईएस के निर्बाध कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए डीजीक्यूए के अंतर्गत डीटीआई के संवर्धन की स्थापना से जुड़ी गतिविधियों का समन्वय करने हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

ग) वर्ष 2020-25 के दौरान डीटीआईएस का 400 करोड़ रुपए के कुल सहायता अनुदान से 6 से 8 नई हरित क्षेत्र रक्षा परीक्षण अवसंरचना की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए)

डीजीएक्यूए रक्षा पीएसयू, आयुध निर्माणियों और डीआरडीओ आदि के लिए गुणवत्ता आश्वासन नियामक प्राधिकरण है और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणियों, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, तेल रिफाइनरियों एवं निजी व्यावसायिक फर्मों आदि में डिजाइन, विकास, उत्पादन, मरम्मत, दोष जांच, उन्नयन और सुधार के दौरान सैन्य वायुयानों, संबद्ध अनुषंगियों, एयर आर्मामेंट, मानवरहित वायुयान (यूएवी) मिसाइल आदि को गुणवत्ता आश्वासन कवरेज प्रदान करता है। डीजीएक्यूए सैन्य विमानन स्टोर्स की विदेश से अधिप्राप्ति के दौरान तकनीकी मूल्यांकन, फील्ड ट्रायल, प्रेषण पूर्व जांच (पीडीआई) में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डीजीएक्यूए सैन्य वायुयानों की दुर्घटना जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का एक सदस्य है। डीजीएक्यूए सेनाओं के लिए रक्षा विमानन स्टोर्स के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय फर्मों की क्षमता आकलन और पंजीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत है।

डीजीएक्यूए ने वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अतंर्गत 14 फर्मों को पंजीकृत किया है। वर्ष 2019-20 में दिनांक 31 दिसंबर, 2019 तक 14364 करोड़ रुपए मूल्य के सैन्य विमानन स्टोर्स को गुणवत्ता आश्वासन कवरेज उपलब्ध कराया गया है।

प्रमुख उपलब्धियां/घटनाएं

- सैन्य विमानन क्षेत्रों से हितधारकों के साथ रक्षा विमानन स्टोर्स के लिए गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन पहलुओं के बारे में निजी क्षेत्र, एमएसएमई, आरएंडडी संस्थानों/उद्योगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ ओएक्स-48 के विकल्प के रूप मे कृत्रिम विमानन लूब्रिकेंट (एसएएल) का विकास किया है। सभी परीक्षण सफल रहे हैं और सीईएमआईएलएसी द्वारा अस्थायी मंजूरी जारी कर दी गई है। डीजीएक्यूए ने सभी हितधारकों के साथ विकास के सभी चरणों में क्यूए कवरेज प्रदान किया है।

- तृतीय पक्ष जांच संकल्पना के अंतर्गत ग्राउंड सपोर्ट एवं ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर, टूल टेस्टर्स एवं ग्राउंड इक्विपमेंट (टीटीजीई) और गौण स्टोर्स के संबंध में उप-ठेकेदारों के परिसरों में उत्पादन प्रभागों और आरएंडडी केंद्रों द्वारा जांच करने के लिए छह विक्रेता पंजीकृत किए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 (31 दिसंबर 2019 तक) के दौरान डीजीएक्यूए ने रक्षा विमानन स्टोर्स की आपूर्ति के लिए 14 फर्मों को पंजीकृत किया है और निविदा जांच के लिए 2 फर्मों की क्षमता सत्यापन को प्रमाणित किया है। डीजीएक्यूए के पास अब तक पंजीकृत फर्मों की कुल संख्या 59 है।
- भारतीय रक्षा उद्योगों की सहायता और भारत में परीक्षण सुविधा के उपयोग के लिए जांच प्रयोगशाला की स्वीकृति/नवीकरण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की जाती है।

वित्तीय आंकड़ा/मापदंड: वर्तमान वर्ष और विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीएक्यूए द्वारा क्यूए कवरेज के साथ उपलब्ध कराए गए स्टोर्स का मूल्य नीचे प्रस्तुत है:

वित्तीय वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 तक)
मूल्य (करोड़ रुपए में)	21335	21671	22877	14364 करोड़ (अनंतिम)

रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ)

डीईओ का प्रमुख चार्टर मुख्य रूप से भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित और विनिर्मित रक्षा उन्मुख उत्पादों और सेवाओं की निर्यात संभाव्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वय करना है।

आयोजित की गई प्रदर्शनियां भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक सर्वोत्तम अवसर प्रस्तुत करती है। ये प्रदर्शनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं। यह फोरम वरिष्ठ विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ परस्पर विचार विमर्श को भी सुगम बनाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य डीपीएसयू और भारतीय उद्योग दोनों से रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां: भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित के लिए मंच प्रदान करने हेतु डीईओ भारत में एयरो इंडिया और डेफएक्सपो नामक दो द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों को आयोजन करता है। यद्यपि एयरो इंडिया एयरोस्पेस और विमानन उद्योग के लिए समर्पित है, डेफएक्सपो इंडिया का फोकस भू और नौसैनिक प्रणालियों पर है।

क. एयरो इंडिया-2019: एयरो इंडिया 2019 का 12वां संस्करण ''अपार संभावनाओं की असीमित उड़ान'' थीम के साथ दिनांक 20 से 24 फरवरी 2019 को एयरफोर्स स्टेशन येलहंका, बेंगलुरू में आयोजित किया गया था। सीआईआई एमआईडीएम, एसोचौम, पीएचडी, यूएसआईबीसी, यूएसआईएसपीएफ, भारतशक्ति, सिनर्जिया फाउंडेशन, एयरोस्पेस विमानन क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा व्यावसायिक सेमिनारों का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / डीजीएफटी, केरल सरकार के आईएनएफआरए, रक्षा मंत्रालय / डीडीपी ने भी सेमिनारों का आयोजन किया।

एयरो इंडिया 2019 में वायु सेना पैवेलियन

एयरो इंडिया 2019 के दौरान निम्नलिखित को पहली बार संचालित किया गया:

वैश्विक सीईओ सम्मेलन, जिसमें 22 सीईओ ने भाग लिया (11 वैश्विक सीईओ और 11 भारतीय सीईओ)
ड्रोन ओलम्पिक्स के लिए 121 आवेदन प्राप्त हुए थे और तत्पश्चात 58 को भागीदारी के लिए शार्टलिस्ट किया गया।
नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रीजनल एयर कनेक्टिविटी से संबंधित शैक्षिक सेमिनार।
स्थल की बुकिंग और पंजीकरण के लिए डिजीटल इंटरफेस का उपयोग किया गया।
प्रशांत महासागर क्षेत्र की कोटिंग और कोडीकरण सेमिनार।
डीआरडीओ द्वारा ज्ञान सेमिनार।
फोटोग्राफी एवं इंस्टाग्राम प्रतिस्पर्धा।
कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में स्किल पैवेलियन और एनएसडीसी द्वारा एयरो स्किल पैवेलियन की स्थापना एयरो स्किल पैवेलियन में बीस बूथ थे जिसमें अंतरिक्ष और विमानन क्षेत्र में कंपनियों समेत संबंधित कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र में कंपनियों समेत संबंधित कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की भागीदारी थी।

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफएक्सपो 2020 के 11वें संस्करण को दिनांक 5-9 फरवरी 2020 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। डेफएक्सपो 2020 की थीम ''रक्षा का डिजीटल रुपांतरण'' और टैगलाइन ''भारत: उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र'' थी। यह अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी थी। इस प्रदर्शनी ने रक्षा क्षेत्र में भारत को निवेश के एक उभरते हुए आकर्षक केंद्र के रूप प्रदर्शित किया और रक्षा क्षेत्र में गठजोड़ों एवं संयुक्त उद्यमों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

रक्षा उद्योग संबंधी विषयों पर अनेक परस्पर संवादात्मक संगोष्ठियों के साथ बी२बी बैठकों, प्रदर्शकों की प्रेस कांफ्रेस और उत्पाद लांच का आयोजन प्रतिभागियों को नवीनतम परिवर्तनों के प्रति जागरुक करने के लिए किया गया। इस प्रदर्शनी ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार और सैन्य एजेंसियों के अभूतपूर्व नेटवर्क को भी आकर्षिक किया।

आयोजन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

- डेफएक्सपो 2020 का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 फरवरी 2020 को लखनऊ में किया गया।
- इसकी एक विशेषज्ञता स्वदेश के विनिर्मित एयरो, नौसैनिक और भू-प्रणालियों का संयुक्त जीवंत प्रदर्शनी रही।
- इस प्रदर्शनी में अब तक के सबसे अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया था जिसमें 1000 से अधिक

प्रदर्शकों ने भाग लिया और 11 लाख आंगतुक आए जोकि चेन्नई में डेफएक्पो के पिछले आयोजन के चार गुना थे।

- रक्षा मंत्री की मेजबानी में 04 नवंबर 2019 को राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें 100 से अधिक विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की उत्कृष्ट भागीदारी रही।
- रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने पुर्तगाल कोरिया, मास, बाइलैंड, इंडोनेशिया, किर्गीस्तान और उज्बेकिस्तान में रोड-शो का आयोजन किया।
- रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र विभिन्न रक्षा उपक्रमों ने भी रेफएक्सपो-2020 के लिए हैदराबाद, बेंगलुरू, कोलकाता, जमशेदपुर, गोवा और गाजियाबाद तथा मुम्बई में रोड-शो किए।
- डेएफएक्सपो-2020 ने 70 से अधिक देशों की भागीदारी को देखा। 12 अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों सहित विदेश में 47 मंत्रियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया एक्स-2020 के बीच भारत-अफ्रीका संगोष्ठी भी लखनऊ में आयोजित की गई।
- भुगतान सहित स्थल, शैले, कांफ्रेस हॉल, विजटर पास आदि सभी ऑनलाइन थे।
- रक्षामंत्री द्वारा डेफएक्सपो- 2020 के लिए ''इनफार्म, एन्गेज और फीडबैक'' के अनूठे फीचरयुक्त एक मोबाइल एप को दिनांक 27 दिसंबर 2019 को लांच किया गया।

- 291 एमएसएमई ने भाग लिया जो पिछले संस्करण में दुगुना था। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए स्थल बुकिंग में 50 प्रतिशत छूट दी गई थी।
- डेफएक्सपो 2020 में 1028 प्रदर्शकों ने भाग लिया जिसमें से 856 भारतीय प्रदर्शक और 172 विदेशी प्रदर्शक थे।
- ''भारतीय दीर्घा'' में प्रदर्शनी की थीम रक्षा का डिजीटल रुपांतरण को प्रतिध्वनित किया और भारतीय स्टार्टअप्स की क्षमताओं को प्रदर्शित किया।
- पहली बार समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के एक समर्पित आयोजन 'बंधन' को आयोजित किया गया जिसमें 68 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए यूपीईआईडीए और डीआरडीओ के बीच समझौता ज्ञापन के आदान-प्रदान के अतिरिक्त डीआरडीओ द्वारा उद्योगों को 18 लाइसेंसिंग करार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सौंप दिए गए।
- 'बंधन' के आयोजन के दौरान, 'मेक इन इंडिया' विजन के अंतर्गत ओएफबी, बीडीएल बीईएल, एमडीएल और निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा भी कुछ उत्पाद लांच किए गए ओएफबी ने 155 एमएम आर्टिलरी गन 'सारंग', 100 मी रेंज की 'न्यू अल्फा गन' और 800 मी. रेंज की एलएमजी को लांच किया। बीडीएल ने मानव वहनीय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और पनडुब्बी

रोधक टारपीडो 'वरुणास्त्र' को लांच किया।

- आईजीए के फ्रेमवर्क के अधीन अनेक सैन्य प्लेटफार्मों और शस्त्र प्रणालियों के कलपुर्जों के संयुक्त उत्पादन के लिए रूसी रक्षा प्रमुखों और भारतीय सैन्य फर्मों के बीच 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान डीईओ द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया और इसमें डीपीएसयू, ओएफबी और निजी उद्योगों ने भी भाग लिया था:-

आयोजन का नाम	तारीख	स्थान	प्रतिभागी
आईएफडीईएफ-2019	दिनांक 4-6 जून, 2019	तेल अवीव, इजराइल	बीईएमएल, जीआरएसई, जीएसएल, बीईएल, एमडीएल
पेरिस एयर शो-2019	17-23 जून 2019	फ्रांस	एचएएल
थलसेना -2019	25-30 जून, 2019	मास्को, रूस	ओएफबी, बीडीएल, बीईएमएल, जीएसएल, डीआरडीओ
डीएसईआई-2019	10-13 सितंबर, 2019	लंदन, यूके	जीआरएसई, ओएफबी, डीआरडीओ, बीईएल, एमडीएल, जीएसएल
बाइडेक -2019	28-30 अक्तूबर 2019	बहरीन	मिधानी, ओएफबी, डीआरडीओ
दुबई एयर शो -2019	17-21 नवंबर 2019	दुबई	बीडीएल और डीआरडीओ
डीएसईआई जापान-2019	18-20 नवंबर 2019	माकूहारी मेसे, जापान	एमडीएल, जीआरएसई, बीईएल, बीईएमएल

रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान

राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्देश): राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान, निर्देश की स्थापना युद्धपोत और पनडुब्बी निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के संकल्प के साथ रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग की एक संस्था के रूप में हुई थी। कालीकट में एक अस्थायी मुख्यालय बनाया गया और संस्थान में प्रशिक्षण एवं आरएंडडी गतिविधियां शुरू की गई। शैक्षिक संस्थानों के साथ अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हो गई और पांच आईपीआर को अब प्रोसेस किया जा रहा है जिन्हें आगे समुद्री अनुप्रयोग में तकनीक हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब, निर्देश अपने सदस्य संगठनों के लिए और अधिक प्रगतिशील परिणाम के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया में है।

डीपीएसयू के कार्य परिणाम: रक्षा पीएसयू के उत्पादन मूल्य और करोपांत लाभ को निम्न सारणियों में क्रमिक रूप से दर्शाया गया है।

तालिका सं. 11.1

रक्षा पीएसयू का उत्पादन मूल्य

(करोड़ रुपए में)

डीपीएसयू का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (दिसंबर, 2019 तक)
एचएएल	17103	17553	18538	11916
बीईएल	9244	9706	11921	7924
बीईएमएल	2624	3227	3467	2110
बीडीएल	5011	4641	3235	1657
जीआरएसई	928	1342	1379	971
जीएसएल	1030	1343	848	589
एचएसएल	629	645	595	259
एमडीएल	3523	4399	4649	3870
मिधानी	696	698	815	732
कुल	**40788**	**43354**	**45447**	**30028**

तालिका सं. 11.2

रक्षा पीएसयू का करोपरांत लाभ

(करोड़ रुपए में)

डीपीएसयू का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (दिसंबर, 2019 तक)
एचएएल	2616	2070	2282	1616
बीईएल	1548	1399	1927	759
बीईएमएल	84	129	63	(-)118
बीडीएल	524	528	423	225
जीआरएसई	11	87	110	114
जीएसएल	117	217	132	108
एचएसएल	54	21	36	01
एमडीएल	549	440	519	337
मिधानी	126	131	131	119
कुल	**5629**	**5022**	**5623**	**3161**

***

सैन्य कार्य विभाग

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE

सैन्य कार्य विभाग एवं उसका संगठन

डीएमए का निर्माण व सीडीएस की नियुक्ति

भारत सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2019 को जनरल बिपिन रावत, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, को प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और स्थायी चेयरमेन सीओएससी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें सीडीएस संस्था के साथ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कार्य विभाग (डीएमए) विनिर्मित किया गया जिसमें सीडीएस डीएमए के सचिव के रूप में भी कार्य करता है।

इस सुधार का उद्देश्य काम-काज और निर्णय लेने में बेहतर समन्वय के साथ सेवाओं के बीच तालमेल और संयुक्तता की चल रही प्रक्रिया को गति प्रदान करना है।

मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी (मुख्यालय आईडीएस)

कारगिल समीक्षा समिति (केआरसी) की रिपोर्ट पर मंत्रियों के संगठन (जीओएम) की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 2001 मुख्यालय आईडीएस को स्थापित किया गया था। मुख्यालय को तीनों सेनाओं के मध्य संयुक्तता और तालमेल को बढावा देने के लिए चैयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के आदेश और नियंत्रण के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस मुख्यालय ने संयुक्त और एकीकृत योजना, खुफिया समन्वय, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियान संचालन और खरीद को प्राथमिकता देने / सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

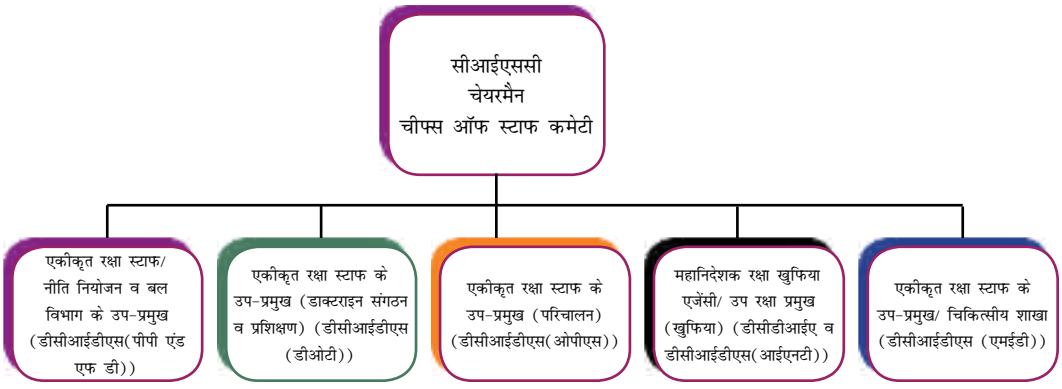

भारतीय सेना

बदलत वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य ने राष्ट्र के सामने कई सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न कर दी है। अनुभूत सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी संक्रियात्मक तत्परता / परिस्थितियों की निरंतर समीक्षा करते समय भारतीय सेना (आईए) युद्ध स्थिति के समूचे परिदृश्य में बाहरी और आंतरिक खतरों से देश की रक्षा करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा आपदा/प्राकृतिक संकटों के समय में भी भारतीय सेना प्रभावित लोगों की सहायता और मदद करके सबसे आगे रहती है।

जम्मू और कश्मीर

वर्ष 2019 जम्मू और कश्मीर के इतिहास में ऐतिहासिक वर्ष था। वर्ष 2018 में सामना की गई बाधाओं से हतोत्साहित होकर आतंकवादियों ने 14 फरवरी, 2019 को सीआरपीएफ रक्षदल पर आत्मघाती हमला किया जिसमें 40 लोगों ने जान गंवाई थी। इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) ने ली थी। आतंकवादियों और सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सामना करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैम्प पर हवाई हमले ने हमारे संकल्प को प्रमाणित कर दिया था। जैश-ए-मोहम्मद को वर्षभर निशाना बनाया गया और सामूहिक नेतृत्व को नष्ट कर दिया गया।

> 05 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति और जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को संघ-राज्य क्षेत्रों के रूप में विभाजन से जम्मू और कश्मीर की अव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती, अलगाववादियों की नजरबंदी, ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी तथा संचार साधनों पर प्रतिबंध लगाकर वहां पर शांति को कायम रखा गया। गतिविधियों के संचालन स्थलों पर आधिपत्य बनाकर आतंकी समूहों को दवाब में रखा गया। हमारे इस आधिपत्य से आतंकवादियों द्वारा संचालित घटनाओं (टीआईआई) तथा स्थानीय नियोजन में समग्र रूप में कमी आई थी।

आंतरिक भू-भाग में स्थिति

सुरक्षा बलों ने अनेक आतंकी समूहों का सफाया करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। प्रमुख आतंकवादियों के मारे जाने से आतंकी समूहों पर व्यापक रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आतंकवादी समूहों पर प्रबल दवाब बनाए रखा गया था। समन्वित आतंकीरोधी आपरेशनों से यह सुनिश्चित हुआ कि आतंकवादी फरवरी, 2019 में पुलवामा घटना के बाद कोई भी आतंकी हमला नहीं कर सके।

सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा 2019, पंचायत, बीडीसी, संसदीय चुनाव के स्वतंत्र आयोजन तथा राज्य पुनर्गठन तथा अनुच्छेद 270 को समाप्त करने में सफल रहे।

सुरक्षा बलों द्वारा की गई समन्वित और पूर्व सक्रिय कार्रवाई के परिणामस्वरूप भर्ती में गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हुई है। दक्षिण कश्मीर में सर्वाधिक भर्ती पुलवामा जिले में हुई थी जिसमें 36 भर्तियों के सर्वाधिक मामले थे। उत्तर कश्मीर में भर्ती न्यूनतम रहा था जबकि उत्तर कश्मीर में बारामुला भर्ती का प्रमुख क्षेत्र था।

वर्ष के प्रथम छह माह में आतंकी-अलगावादी गठजोड़ से भावोत्तेजक मामलों का सहारा लेकर घाटी में हिंसा और अशांति का माहौल जारी रखा गया था।

जेईएल पर प्रतिबंध लगाने, आतंकवाद मानीटरिंग ग्रुप (टीएमजी) का सृजन करके आतंकवाद के लिए वित्तपोषण पर रोक लगाने तथा अलगाववादियों तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने आतंकवादी माहौल को गंभीर रूप से तबाह कर दिया।

अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रभावी सुरक्षा ग्रिड को सुदृढ़ बनाने के कारण आतंकवादियों द्वारा संचालित घटनाओं (टीआईआई) में काफी कमी हुई है। टीआईआई की अधिकांश घटनाएं दक्षिण कश्मीर मुख्य रूप से पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, अनंतनाग तथा बारामुला में हुई। कुल 172 टीआईआई में से इन जिलों में लगभग 86 प्रतिशत घटनाएं हुईं।

नियंत्रण रेखा (एलसी) पर स्थिति

युद्धविराम उल्लंघन (सीएफवी):

वर्ष 2019 में नियंत्रण रेखा पर स्थिति अस्थिर बनी रही। पुलवामा हमले के बाद यह युद्धविराम उल्लंघन की घटनाओं में अल्प वृद्धि हुई थी।

पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तरीय वार्ताओं में स्थिति को सामान्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान को यह अवगत करवाया था कि नियंत्रण रेखा पर शांति पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोकने के लिए विश्वसनीय, प्रमाणनीय तथा अटल उपायों पर निर्भर है।

वर्ष के दौरान 494 केलिबर एस्केलेशनंस के साथ कुल 3017 युद्धविराम उल्लंघन की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

नियंत्रण रेखा पर विरोधी तत्वों द्वारा प्रोबिंग / ट्रांस एलसी आपरेशन संबंधी प्रयास अक्षुण बने रहे। वर्ष 2019 में, छिपकर गोलीबारी करने की नौ घटनाएं हुई थी जिनमें हमारी सैन्य टुकड़ियों के तीन कार्मिकों को मामूली चोटें आई थीं। पाकिस्तानी सेना को सीमा पर सभी दुस्साहसों का माकूल जवाब दिया गया था।

पूर्वोत्तर

वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा संबंधी स्थिति में सुधार देखा गया। इस संबंध में, सेना और असम राइफल्स (एआर) ने शांति का माहौल पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना जारी रखा जो उस क्षेत्र के सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए अनुकूल है।

सूचनाएं यह प्रकट करती हैं कि सुरक्षा बलों (एसएफ) द्वारा निरंतर ऑपरेशनों के कारण विद्रोही समूहों को अत्यंत प्रशासनिक और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और हिसंक गतिविधियों को रोकने के लिए उनकी क्षमताएं बनाए रखने हेतु छत्रक संगठन स्थापित करने पर बल दिया गया है। समानांतर रूप में, अवैध प्रवासियों के मुद्दे से प्रेरित जनजातीय तथा नृजातीय विभाजन को गति मिली है और इसका प्रभाव पूरे पूर्वोत्तर पर होने की संभावना है।

म्यांमार सेना के साथ सकारात्मक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय और म्यांमार सेनाओं द्वारा जनवरी, 2019 से भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी) और म्यांमार के नृजातीय सशस्त्र समूहों (ईएजी) के विरुद्ध भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) पर समंवित आपरेशन संचालित किए गए थे। ये आपरेशन ईएजी शिविरों और आईआईजी के विरूद्ध संचालित किए गए थे।

कुल 140 आतंकवादियों को या तो गिरफ्तार किया गया है अथवा उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है तथा सुरक्षा बलों द्वारा आईएमबी पर 37 हथियार बरामद किए गए हैं।

इन ऑपरेशनों ने म्यांमार में शरण लेने वाले विद्रोही समूहों को विस्थापित कर दिया है और उनकी गतिशील क्षमता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया है।

असमः इस राज्य में सुरक्षा स्थिति काफी सीमा तक शांतिपूर्ण और नियंत्रणाधीन रही। सुरक्षा बलों द्वारा संचालित किए गए आपरेशनों से विद्रोही समूहों के आपरेशनल स्पेस में व्यापक रूप से कमी आई है।

एनडीएफबी (एस) और उल्फा (आई) को प्रतिबंधित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उनके कैडर हतोत्साहित हुए है और उनका मोह भंग हुआ है।

नागालैंडः राज्य में कुछ आंतरिक संघर्ष की घटनाओं और असम राइफल्स (एआर) के विरूद्ध घात लगाने की एक घटना को छोड़कर काफी हद तक शांति रही। फिर भी, एनएससीएन ने अपने एक्टोर्शन रैकेटों और अन्य अवैध गतिविधियां जारी रखी। एनएससीएन (के) के खांगों गुट ने युद्धविराम समझौते पर 15 अप्रैल, 2019 पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए थे और नागा शांति वार्ताओं में नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों (एनएनपीजी) के रूप में शामिल हुआ था। इन गतिविधियों से यह सुनिश्चित कर दिया है कि नागा शांति वार्ताएं विशिष्ट बन गई हैं और ये राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समाधान के रूप में आगे बढ़ रही हैं। शांति प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सरकार और नागा समूहों के बीच वार्ताएं चल रही हैं।

एनएससीएन (के) खांगों गुट ने युद्धविराम समझौते पर 15 अप्रैल, 2019, पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए थे और नागा शांति वार्ताओं में नागा राष्ट्रीय राजनीति समूहों (एनएनपीजी) के रूप में शामिल हुआ था।

दीमापुर में आंतरिक रेखा अनुमति (आईएलपी) प्रणाली लागू करने की मांग ने नागालैंड के घरेलू निवासियों का रजिस्टर (आरआईआईएन) तैयार करने की पहल को बाधित कर दिया।

मणिपुरः आसूचना आधारित पूर्वसक्रिय ऑपरेशनों से यह सुनिश्चित हुआ कि राज्य की स्थिति में सुधार प्रतीत हुआ था। राज्य में दैनिक अशांति पैदा करने के लिए ब्लाकेड्स और बंद होने की घटनाएं जारी रहीं। इम्फाल के विअधिसूचित क्षेत्र में आईईडी और ग्रेनेड ब्लास्ट की घटनाएं अक्सर हुईं। अधिकांश हिंसक घटनाएं घाटी स्थित समूहों द्वारा प्रेरित थीं।

नागा संरचना समझौते की विषयवस्तु पर स्पष्टीकरण मांगने और नागा शांति वार्ताओं के अंतिम रूप

दिए जाने की संभावना के आलोक में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंड़ता को बनाए रखने के लिए चिन्ता व्यक्त करते हुए सिविल सोसाइटी संगठनों की गतिविधि में भी वृद्धि हुई थी।

अरुणाचल प्रदेश: हिंसक घटनाओं में कमी, सिविलियनों के कम हताहत होने तथा आतंकवादियों की गिरफ्तारी की संख्या में वृद्धि होने के संदर्भ में इस राज्य में सुरक्षा स्थिति में निरन्तर सुधार होता रहा है। लांगडिंग, तिराप तथा चांग्लांग जिले विभिन्न नागा विद्रोही समूहों के होने से प्रभावित रहे जो इस क्षेत्र में अपनी हुकूमत स्थापित करने के लिए अपने प्रयास करते रहे।

म्यांमार में उनके बेस से ऊपरी असम में पहुंच बनाने के लिए एनडीएफबी (एस) और उल्फा(आई) द्वारा उस क्षेत्र का प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा आईएमबी सीमा पर समन्वित ऑपरेशनों तथा वर्धित तैनाती से इन विद्रोहियों के ऑपरेशनल स्पेस में कमी आई थी।

4
पुलिस स्टेशन

असम सीमा पर चार पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 30 सितम्बर, 2019 के बाद छह माह के लिए 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित कर दिया गया है।

यह गत आठ पुलिस स्टेशनों से कम है।

मेघालय: यह राज्य गारो राष्ट्रीय मुक्ति सेना (जीएनएलए) के कम होते समर्थन के आधार पर शांतपूर्ण रहा। हिंसा जीएनएलए द्वारा प्रेरित गारो हिल्स तक ही सीमित रही।

मिजोरम: यह राज्य समूहों द्वारा शस्त्र और नार्कोटिक्स की तस्करी करने के प्रयासों में बढ़ोत्तरी की सूचनाओं के साथ शांतिपूर्ण रहा। भारत म्यांमार तथा बांग्लादेश के तीन मिलन स्थानों पर म्यांमार सेना और म्यांमार के ईएजी के बीच चल रहे संघर्ष को ध्यान में रखते हुए।

भारत म्यांमार सीमा पर हमारी ओर से स्थिति को सुधारने के लिए पूर्व सक्रिय कदम उठाए गए थे।

त्रिपुरा: इस राज्य में शांति कायम रही और त्रिपुरा राज्य में हिंसा कानून व्यवस्था के नियंत्रण में रही। इस राज्य का प्रमुख संपर्क बांग्लादेश के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ने वाली परियोजनाओं से है।

नागा शांति समझौते पर वार्ता से पूरे राज्य पर प्रभाव पड़ने और इस क्षेत्र में स्थिति में समग्र सुधार होने की संभावना है।

सभी समूहों को उनके हिंसक रास्ते से रोककर सही रास्ते पर लाने के प्रयास जारी हैं ताकि उस क्षेत्र

में स्थायी शांति और विकास हो सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र आश्वस्त भविष्य की छवि के लिए अपना उग्रवाद क्षेत्र प्रभावित की छवि से उभर रहा है।

यह क्षेत्र प्रमुख परिवर्तनों के शीर्ष पर है और वृहद अवसंरचना और संचार परियोजनाओं 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के भाग के रूप में संदान है।

भारत चीन सीमा पर स्थिति

वर्ष 2019 में एलएसी पर स्थिति यद्यपि चीनी पक्ष द्वारा विवादित / संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक व्यवहार और एकपक्षीय गतिविधियों की कुछ घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण रही। पश्चिमी क्षेत्र (पूर्वी लद्दाख) एलएसी के बारे में अलग-अलग अवधारणा के कारण अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहा है।

मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) सीमित पीएलए कार्रवाईयों के साथ अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है। इसी प्रकार, पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम में काफी हद तक शांति रही जबकि कामेंग और दिवांग घाटी (अरूणाचल प्रदेश) में एलएसी के बारे में उनकी अवधारणा के अनुसार गश्त करने के लिए चीनी दवाब के ये पहलू हैं जिनमें आने वाले समय में प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित होने की सामर्थ्य है।

जहां तक डोकलाम का संबंध है, पीएलए ने सैन्य दलों के लिए सड़क और आवास में सुधार करके टोर्सा नाला के अपने उत्तरी भाग में अतिक्रमण किया है।

भारत की तरफ से क्षेत्र में अपनी समेकित उपस्थिति दर्शायी है और चुनौती/आकस्मिक स्थिति में निपटने की पर्याप्त तैयारी की है।

मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग

रक्षा सहयोग कार्यकलाप हमारे राष्ट्रीय हित और विदेश नीति संबंधी प्रयोजनों के विकासार्थ एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कार्य करते हैं। हाल के वर्षों में भारत की उदीयमान वैश्विक छवि को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना द्वारा क्रियान्वित किए गए रक्षा सहयोग संबंधी कार्यकलापों में काफी वृद्धि हुई है।

भारतीय सेना रक्षा सहयोग क्रियाकलापों के जरिए वर्ष 2019 तक 99 देशों के साथ जुड़ी है।

संरचनाबद्ध समझौते:

उपर्युक्त के अतिरिक्त 20 नवम्बर, 2019 को आयोजित की गई विदेश सेवा अताशे ब्रीफिंग और 24-29 नवम्बर, 2019 को विशाखापट्टनम, तेजपुर, दिनजान तथा अतांग में आयोजित त्रिसेना विदेश सेवा अताशे टूर के जरिए विदेश सेवा अताशे दिल्ली में वर्ष 2019 में सक्रिय रूप में कार्यरत थे।

दौरे: वर्ष 2019 में अनेक उच्च स्तरीय तथा कार्य स्तरीय दौरों का आयोजन किया गया।

विदेशी सेनाध्यक्षों का दौरा

- नेपाल
- रूस
- यूएसए
- जापान
- कीनिया
- वियतनाम

भारत के सेनाध्यक्ष का सैन्य दौरा

- यूएसए
- मालदीव
- जापान

वर्ष 2019 में दौरे

संयुक्त अभ्यास: एफएफसी के साथ संयुक्त अभ्यास हमारे रक्षा सहयोग संबंधी समझौतों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक स्थापित करते हैं। ये समारोह हमारे प्रोफेशनलिज्म को वैश्विक रूप में दर्शाते हैं और हमारी सैन्य टुकड़ियों को मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं।

1	भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यासों के कार्यक्षेत्र और उन्हें सामूहिक रूप से करने पर बल दिया।
2	अफ्रीकी राष्ट्रों और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीडीएम प्लस) देशों के लिए क्षेत्रीय सामूहिकता आधारित दो बहुराष्ट्रीय अभ्यासों की मेजबानी की थी।
3	भारतीय सेना, उज़्बेगिस्तान के साथ प्रारंभिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास में भी शामिल हुई थी।
4	भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने यूएस के साथ प्रथम त्रिसेना अभ्यास टाइगर ट्रियम्फ की मेजबानी की थी।

संयुक्त अभ्यासों के महत्वपूर्ण पहलू निम्नवत हैं :-

एएफआईएनडीईएक्स 2019	एमईडीईएक्स 2019	अभ्यास दुस्तालिक	अभ्यास टाइगर ट्रियम्फ

(क) एफिनडेक्स 2019: एफिनडैक्स 2019, लोकोपकारी बारूदी सुरंग कार्य एवं यूएन शांति सेना ऑपरेशनों के थीम के आधार पर अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए संयुक्त बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसकी पुणे में मार्च, 2019 में मेजबानी की गई थी। 17 अफ्रीकी राष्ट्रों ने इस अभ्यास में भाग लिया। और तीन अफ्रीकी देश पर्यवेक्षक के रूप में इस अभ्यास में शामिल हुए थे।

(ख) मेडैक्स 2019: भारतीय सेना ने मेडैक्स 2019 की मेजबानी की थी जो एडीडीएम की संरचना के तहत सैन्य चिकित्सा प्लस एडीडीएम की तीसरे दौर की सह अध्यक्षता प्लस म्यांमार के साथ सैन्य चिकित्सा विशेषज्ञ कार्यकारी समूह पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। भारत सहित 20 एडीडीएम प्लस देशों ने फ्रेमवर्क के तहत इस अभ्यास में भाग लिया था।

यह उल्लेखनीय है कि मेडेक्स 2019 एडीडीएम + छतरी के अंतर्गत पहला एक मात्र सैन्य चिकित्सा अभ्यास था।

(ग) अभ्यास दुस्तालिकः भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त अभ्यास दस्तलिक के प्रारंभिक एडिशन की मेजबानी उज्बेकिस्तान द्वारा चर्चिक प्रशिक्षण क्षेत्र उज्बेकिस्तान में की गई थी।

दूसरे एडिशन की मेजबानी भारत में वर्ष 2020 में की जाएगी।

(घ) अभ्यास टाइगर ट्रियम्फः भारत यूएस संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रियम्फ के प्रारंभिक एडिशन की मेजबानी भारत द्वारा विशाखापट्टनम में की गई थी। यह यूएसए के साथ पहला अभ्यास था जिसमें सभी तीनों सेनाओं ने यूएस सेनाओं के साथ संयुक्त रूप में भाग लिया और लोकोपकारी सहायता तथा आपदा राहत के बारे में निपुणता का आदान-प्रदान किया।

सामरिक कार्रवाई : संयुक्त अभ्यास

प्रशिक्षण टीमें : मेजबान राष्ट्र से आग्रह प्राप्त होने पर प्रत्येक देश के लिए प्रशिक्षण टीमों की निश्चित रूप से तैनाती करना अधिदेशित होता है। मौटे तौर पर, प्रशिक्षण में अंग्रेजी भाषा है।

सैन्य कुशलता, संभारिकी, आईटी, इंजिनियरिंग और संचार इत्यादि के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करना अधिदेशित रूप से शामिल है। इसके अलावा, कुछ देशों के टीम लीडर्स को भी मेजबान देशों की सैन्य और सुरक्षा सलाहकारों का दायित्व प्रदान किया जाता है।

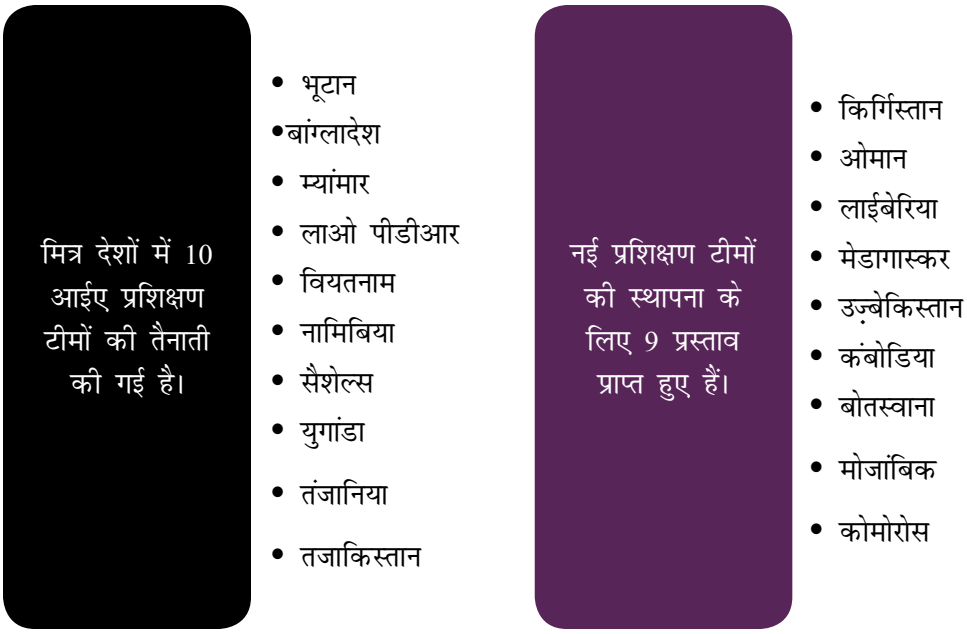

भारतीय सेना की टीमों का ब्यौरा

एफएफसी के साथ प्रशिक्षण : रक्षा सहयोग के लिए सैन्य प्रशिक्षण एक सक्रिय और प्रभावी टूल है। व्यापक सैन्य प्रशिक्षण अवसंरचना के अलावा, हमारी सशस्त्र सेनाएं इकलौती ऐसी सेनाएं है जो सभी प्रकार के भू-भागों अर्थात समतल, जंगलों, रेगिस्तानों, नदियों, पर्वतों और ग्लेशियर भू-भागों में प्रशिक्षण से संपन्न है। इसलिए नियमित और प्रचालित टेलरमेड प्रशिक्षण हेतु एफएफसी से प्रशंसात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।

भारतीय सेना आतंकवाद रोधी, तत्काल विस्फोटक डिवाइस रोधी, विशेष बलों, आसूचना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आपरेशनों, सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए रिक्तियां पेशकश करती है। हाल ही के वर्षों में एफएफसी के सैन्य पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण की स्थिति में आईए प्रशिक्षण संस्थानों में अत्याधिक से वृद्धि हुई है।

2812 रिक्तियां

वर्ष 2019 में एफएफसी के लिए 2821 पाठ्यक्रम रिक्तियां ऑफर की गई हैं।

1202 कार्मिक

भारतीय सेना 1202 कार्मिकों को नियमित टेलरमेड प्रशिक्षण के माध्यम प्रशिक्षित करेगी।

10 आईएमटीटी

यह प्रशिक्षण नियमित प्रशिक्षण हेतु एफएफसी में तैनात भारतीय सैन्य प्रशिक्षण टीमों (आईएमटीटी) द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण के अतिरिक्त है।

एससीओ फ्रेमवर्क के तहत आदान-प्रदान :

भारतीय सेना ने एससीओ फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी सक्रिय कार्रवाईयों में निम्नलिखित सहित भाग लिया:

रक्षा मंत्रियों की बैठक
(अप्रैल, 2019)

वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग विभागों और विशेषज्ञ कार्यकारी समूहों के शीर्षाध्यक्षों की बैठक

संयुक्त अभ्यास सेंटर
(सितम्बर, 2019)

एससीओ फ्रेमवर्क के तहत आदान प्रदान

अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल

प्रत्येक वर्ष रूसी फेडरेशन के तत्वाधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन किया जाता है। भारतीय सेना ने विभिन्न सत्रों में कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अगस्त, 2019 में भारत ने पहली बार सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता की मेजबानी की।

सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता

भारतीय बटालियन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मिशन में कजाख़ सैनिकों की सह-तैनाती : कजाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों में कजाख़ सैनिकों के प्रशिक्षण और तैनाती के लिए भारत से सहायता हेतु अनुरोध किया गया था।

भारतीय सेना द्वारा आयोजित व्यापक प्रशिक्षण और तैयारी अनुसूचि के पश्चात, कजाख़ सेना की एक कंपनी को लेबनान यूएन आंतरिक फोर्स (यूएनआईएफआईएल) में अंतर्गत भारतीय सैन्य टुकड़ी भारतीय बटालियन (आईएनडीबीएटीटी) के भाग के रूप में तैनात किया गया।

नवंबर, 2020 तक यह तैनाती प्रत्येक छः महीने के चार चक्रो तक के लिए की जाएगी। एक मित्रवत सेना की सह-तैनाती, केन्द्रीय प्रशिक्षण गणतांत्रिक के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन प्रयास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सेना विशेषज्ञों को भारत और विदेश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के साथ अन्य एफएफसी हेतु प्रशिक्षण कार्रवाईयों में भी तैनात किया जाता है।

यूएनआईएफआईएल में गश्त लगाती भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना के सैनिक

भारत ने एडीएमएम प्लस के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए सैन्य औषधि पर विशेषज्ञ कार्यकारी समूह के लिए म्यांमार के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की थी।

भारत ने दिसम्बर, 2018 में 10वीं विशेषज्ञ कार्यकारी समूह की बैठक और टेबल टॉप अभ्यास (टीटीएक्स) का भी आयोजित किया था।

फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाईज (एफटीएक्स) मैडेक्स 2019 भारत में आयोजित की

यह नियोजन नवम्बर, 2020 तक छः माह प्रत्येक के चार आवर्तन के लिए जारी रहेगा। मैत्रीपूर्ण सेना का सह-नियोजन मध्य एशियाई देशों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रयासों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आईए अतिरिक्त भारतीय सेना विशेषज्ञ भारत और विदेश के अन्य एफएफसी के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए कार्य करते हैं।

एडीएमएम प्लस एक्सचेंज

चिकित्सीय सहायता

एफएफसी को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना हमारी रक्षा सहयोग पहलों की महत्वपूर्ण आधारशिला को प्रकट करता है। हमारे चिकित्सा स्कूलों में विदेशी चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और अस्पतालों की स्थापना/उपहार स्वरूप दवाईयां प्रदान करके हमने अच्छी ख्याति प्राप्त की है।

भारतीय सेना द्वारा चिकित्सा सहायता

निकटतम पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदानः सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने उनके रक्षा सशस्त्र बलों के साथ 60-80 दौरों का संयोजन किया है।

वर्ष 2019 में सांस्कृतिक आदान-प्रदान किया गया

- श्रीलंका
- म्यांमार
- बांग्लादेश
- भूटान

प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा सांस्कृतिक दौरों, जिसमें सभी रैंकों और सभी तीनों सेनाओं में सफलतापूर्वक, बेहतर सरकारी और प्रोत्साहन मिलन सारिता को स्थापित करना शामिल है। यह भारतीय सशस्त्र सेना की ख्याति को सुस्थापित करती है और यह एक बहुत ही नाजुक भावनात्मक कड़ी के साथ जनता से जुड़ी है।

आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण

मेक इन इंडिया पहल :

मेक इन इंडिया नीति को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने 30 अगस्त, 2019 को सेना डिजाईन ब्यूरो (एडीबी) की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

एडीबी का गठन रक्षा विनिर्माण में प्रौद्योगिकी एवं उपस्कर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिभा एवं उद्यमिता के स्वदेशी / घरेलू विकसित भण्डार का उपयोग करने के लिए उद्योग तथा शिक्षा जगत तक सीधे पहुंचने का प्रयास है।

उत्तरी सीमाओं पर अवसंरचना विकास

भारतीय सेना उत्तरी सीमाओं के साथ पहाड़ी इलाकों में आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी के प्रति जागरूक रही है और बुनियादी ढांचे और ऑपरेशनल सभारिकीय परिसंपत्तियों के समग्र विकास की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करती रही है।

आवश्यक निधियां आवंटित की गई है जो न केवल संचालन करने के लिए भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाएगीं बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान देगी।

सैन्यदलों के लिए उन्नत आवास

बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण: सियाचिन बेस कैंप में 400 फीट बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया था. नुब्रा नदी पर पुराना पुल वर्ष 2002 में बना था और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। स्थानीय अभियंता रेजीमेंट द्वारा नए केबल और प्रमुख असेंबली के साथ पुल की डी-लॉन्चिंग और री-लॉन्चिंग की गई थी।

गोलाबारूद

क. गोला- बारूद का भंडार: भारतीय सेना के गोला-बारूद के भंडारण में सुधार के लिए कई प्रमुख पहल की गई हैं। इस बहु-आयामी रणनीति के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे गोला-बारूद का निर्माण होने जा रहा है।

ख. गोला-बारूद रोल ऑन प्लान : आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) पर पांच साल के रोल-ऑन इंडेंट को रखकर गोला-बारूद का प्रबंधन किया जाता है ताकि वह अपने उत्पादन की योजना बना सके। ओएफबी क्षमता को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक रूप से सहमत लक्ष्यों पर मांगपत्र प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2010 से 2014 के लिए पहला पंचवर्षीय रोल-ऑन इंडेंट फरवरी 2010 में ओएफबी को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा रोल ऑन इंडेंट अक्टूबर 2013 में ओएफबी को वर्ष 2014 से 2019 के लिए पांच साल की संभावित योजना की अनुमानित आवश्यकता

के लिए प्रस्तुत किया गया था। **वर्ष 2019 से 2024 के लिए तीसरा रोल ऑन इंडेंट वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया है।** ओएफबी की उत्पादन रिपोर्टों की मासिक निगरानी की जा रही है और कमियों को उजागर किया जा रहा है।

ग. **गोला-बारूद रोड मैप:** गोला बारूद की पंचवर्षीय रोल-ऑन योजना के मूल्यांकन के दौरान, संकटकालीन जटिलताओं के समाधान के लिए गोला-बारूद रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। गोला बारूद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गोला बारूद रोड मैप को मंजूरी दी गई थी। गोला बारूद रोड मैप के तहत स्वीकृत गोला बारूद खरीद योजना में ओएफबी पर अतिरिक्त आवश्यकताओं को और कुछ गोला बारूद वस्तुओं की पूर्व आयात की खरीद शामिल है।

घ. **गोला-बारूद की आपातकालीन खरीद:** रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2016 में थल सेना उपाध्यक्ष (वीसीओएएस) को आपातकालीन खरीद के अधिकार सौंपे है। इस प्रत्यायोजन के परिणामस्वरूप, भारतीय सेना की बहुत बड़ी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण गोला-बारूद, आयुध, वाहन और पुर्जों के लिए की गई खरीद से किए गए कई अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया। भारतीय सेना के गोला-बारूद की स्थिति में सुधार हुआ है।

ङ. **महत्वपूर्ण गोला-बारूद और कल-पुर्जों के न्यूनतम स्टॉक स्तर को बनाए रखने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन :** यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल हमेशा आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, इसलिए, सशस्त्र बलों को यह सुनिश्चित करने के लिए शक्ति और जिम्मेदारी दी गई है कि गोला-बारूद और कल-पुर्जों के लिए न्यूनतम महत्वपूर्ण स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा।

च. **भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय सेना के लिए गोला-बारूद का निर्माण:** स्वदेशी क्षमता के विकास को सुगम बनाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए :

सरकार ने गोलाबारूद के एक सुदृढ़ विकल्प के रूप में उद्योग के भीतर क्षमता निर्माण के दीर्घकालिक उद्देश्य से भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय सेना के लिए चयनित गोलाबारूद के विनिर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है।

अस्त्र-शस्त्र

नाइट साइट्स हथियार और निगरानी उपकरण

भारतीय सेना के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल (एएफवी) और गैर-एएफवी अनुप्रयोगों के लिए इमेज इंटेन्सिफायर नाइट विजन डिवाइसेस (एनवीडी) की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। वर्तमान खरीद मामलों में पैसिव नाइट विजन गॉगल्स (पीएनवीजी), पैसिव नाइट विजन दूरबीन (पीएनवीबी) और ओएलएफ से एएफवी प्लेटफॉर्म के लिए इमेज इंटेंसिफायर और थर्मल इमेजरी साइट शामिल हैं।

सशस्त्र बलों की परिचालन संबंधी तैयारियों को बनाए रखने की दृष्टि से, सेना मुख्यालय को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के दायरे को और अधिक विस्तृत किया गया है:

एक्स ओएफबी शस्त्रागार	वार्षिक प्रावधान समीक्षा के आधार पर अस्त्र-शस्त्रों के विनिर्माण के लिए ओएफबी पर मांग की जाती है जिसके लिए ओएफबी के पास क्षमता और प्रौद्योगिकी होती है।
एक्स आयात शस्त्रागार	प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होने के कारण कमी को पूरा करने के लिए कतिपय अस्त्र-शस्त्रों का आयात भी किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण अस्त्र-शस्त्रों तथा माइन्स का 100% भण्डार स्तर बनाए रखने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन	कुछ महत्त्वपूर्ण अस्त्र-शस्त्रों और बारूदी सुरंगों के संबंध में 100% अधिप्रमाणन तक खरीद करने के लिए वीसीओएएस को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण खरीद के लिए मार्च, 2019 में सेना उपाध्यक्षों को आपातिक खरीद की शक्तियों का प्रत्यायोजन

- अस्त्र-शस्त्र
- हथियार
- गोलाबारूद
- कलपुर्जे
- मिसाइल

संबंधित सेनाध्यक्षों को प्रधिकार के तहत इसका प्रयोग किया जाना है

राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर)

आरआर, चूंकि इसकी स्थापना ने सुरक्षा के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अमूल्य सहायता प्रदान की है, आरआर ने अपने परिचालन कार्यों के साथ लगातार दबाव डाला है। पूरे बल ने क्षेत्र में शांति और शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जो अन्यथा निरन्तरता की स्थिति में बनी हुई है।

आरआर की परिचालन उपलब्धियां

आरआर ने 165 आतंकवादियों को मार गिराया

- 128 आतंकवादी मारे गए
- 37 आतंकवादी पकड़े गए
- युद्ध सामग्री का बड़ा भंडार जब्त किया गया

श्री अमरनाथ यात्रा (ऑपरेशन शिव) : आरआर यूनिटों और फॉर्मेशन्स ने चरणबद्ध तैनाती, आक्रामक वर्चस्व और उत्कृष्ट खुफिया नेटवर्क द्वारा यात्रा शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रद्धालुओं के आने-जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए चिकित्सा कवर सहित पूरी सहायता प्रदान की गई है।

लोगों के अनुकूल क्रियाकलाप

सेना और सरकार के बारे में लोगों की धारणा को बदलने के लिए बड़ी संख्या में **जनहितैषी** गतिविधियां शुरू की गई। इससे **'आवाम'** और **'जवान'** के बीच आपसी समझ के स्तर को बढ़ाने के अलावा लोगों के सेना को देखने के तरीके में एक स्पष्ट बदलाव आया है।

आरआर द्वारा स्थापित युवा रोजगार एवं दिशानिर्देश नोड (बाईईजीएन) ने राज्य के युवाओं को प्रभावकारी रूप से लक्षित किया।

इससे उन्हें उच्च शिक्षा और रोजगार के रास्ते तलाशने में मदद मिली है, इस प्रकार उन्हें आसान धन के लालच और आतंकवाद के माध्यम से शक्ति की गलत भावना से दूर करने में मदद मिली है। वर्षों से, आरआर ने आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने में राष्ट्र को एक महान रणनीतिक लाभ दिया है।

आरआर का सृजन, दुनिया में एकमात्र विशेष रूप से संरचित सीआई/सीटी उत्प्रेरक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के साथ रणनीतिक निर्णय के बेहतरीन उदाहरणों में से एक रहा है। इससे प्राप्त विशेषज्ञता व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में अनमोल है और इसे हमेशा के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था। प्रादेशिक सेना की अवधारणा लाभकारी रूप से नियोजित नागरिकों को अंशकालिक सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना है जो उन्हें प्रदान किए गए सैन्य प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप सक्षम सैनिक बन जाते हैं।

इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) मद्रास की स्थापना:

30 अप्रैल, 2019 — इंफैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) मद्रास ने मद्रास रेजिमेंटल केन्द्र वेलिंगटन में अपनी स्थापना को सफलतापूर्वक पूरा किया और वर्तमान में इसकी तैनाती अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं।

इन्फैंट्री बटालियन की स्थापना

सीईटीएफ बटालियन (टीए) जीआर की स्थापना

सीईटीएफ जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के लिए 30 अप्रैल, 2019 को एक पारिस्थितिक बटालियन सीईटीएफ बटालियन (टीए) जीआर की स्थापना की गई थी। कंपनी आधारित बटालियन इलाहाबाद में स्थित है और इसकी कंपनियां इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी में तैनात हैं। छह महीने की अल्प अवधि में यह निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम रही है:

ये इकाइयां स्वच्छ गंगा मिशन में जनता को शामिल करने के लिए तीनों शहरों में नियमित रूप से जन जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षिक सेमिनार आयोजित कर रही हैं।

30 अप्रैल, 2019

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के लिए जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक पारिस्थितिकी बटालियन, सीईटीएफ बटालियन (टीए) जीआर की स्थापना की गई।

किए गए कार्यकलाप

- फाइटोरेमेडिएशन और अन्य मैन्युअल प्रयासों की मदद से इलाहाबाद में प्रसिद्ध मैकफर्सन झील की आर्द्रभूमि का कायाकल्प
- बायोफिल्टर स्ट्रिप विधि द्वारा गंगा नदी में अपशिष्टों को जोड़ने वाले नालों की सफाई की गई।
- वायरमेश आदि लगाकर नाले के पानी से ठोस कचरे को अलग करना।
- 6.5 लाख बेटिवर ग्रास स्लिप्स लगाकर नदी तट का स्थिरीकरण करना ।
- जल परीक्षण, सीवेज ट्रीटमेंट संचयों की निगरानी के लिए यूनिट में कार्यात्मक प्रयोगशाला विकसित करना।
- नदीय घाटों पर निरन्तर नावों के द्वारा पैट्रोलिंग करके विधिवता का संरक्षण करना और जलीय प्रजातियों के अवैध शिकार को संभव सीमा तक रोकना।

आजीविका के लिए वृक्षारोपण 'भारतीय सेना का एक विज़न'

सेना प्रमुख (सीओएएस) द्वारा परिकल्पित और अतिरिक्त महानिदेशालय प्रादेशिक सेना (एडीजी टीए) की योजना के अनुसार उत्तराखंड स्थित दो पारिस्थितिकी बटालियन टीए अर्थात् 127 ईटीएफ और 130 ईटीएफ ने दो सीमावर्ती क्षेत्र के दो गांवों अर्थात क्रमशः गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के मलारी और धारचूला में स्थानीय लोगों के लिए अखरोट के एक लाख पौधे लगाए। इसके पीछे का विचार रोजगार के अवसरों की कमी के कारण ऐसे क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए आजीविका के स्थायी साधन प्रदान करना था।

24 अक्टूबर, 2019

थल सेना अध्यक्ष (सीआएएस) ने चमोली गढ़वाल में मलारी में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया जहां 50,000 अखरोट के पौधे लगाए गए।

24 अक्टूबर, 2019

शेष 50,000 अखरोट के पौधे कुमाऊं के धारचूला क्षेत्र में लगाए गए।

ये सभी पौधे स्थानीय लोगों को मुफ्त सौंपे गए हैं और यूनिटों द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाता रहेगा।

201 महिला प्रोवोस्ट यूनिट (प्रादेशिक सेना) की स्थापनाः नियमित सेना/प्रादेशिक सेना की सहायता के लिए सैन्य पुलिस कोर से संबद्ध पहली महिला प्रोवोस्ट यूनिट (प्रादेशिक सेना) की स्थापना के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदित दिया गया है और इस पर वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

पारिस्थितिकीय बटालियनों (टीए) के लिए संशोधित वृक्षारोपण लक्ष्यः 10 पारिस्थितिकी बटालियनों (टीए) के लिए कुल 25 पारिस्थितिकी कार्य बल (ईटीएफ) कंपनियां हैं और लगभग पूरे देश में कार्यरत हैं।

एडीजी टीए द्वारा एक पहल के रूप में, प्रत्येक ईटीएफ कंपनी चालू वर्ष से प्रत्येक वृक्षारोपण वर्ष में पांच लाख पौधे जिसमें (दो लाख पौधे + दो लाख सीड बॉल्स + एक लाख वेटिवर ग्रास स्लिप्स) लगाएगी। प्रत्येक वृक्षारोपण वर्ष में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। .

इसे इस वृक्षारोपण वर्ष के लिए जमीनी स्तर पर लागू किया गया है।

एडीजी टीए की एक पहल

महिला अधिकारियों की नियुक्ति

चयन प्रक्रिया अभी चल रही है और चयनित होने वाली महिला उम्मीदवारों की सही संख्या प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगी।

संयुक्त राष्ट्र मिशन

भारतीय सेना दुनिया भर में 14 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में से आठ में भागीदारी के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में प्रमुख भूमिका निभा रही है। भारतीय सेना की सैन्य टुकड़ियों को अथवा स्टाफ ऑफिसर्स तथा सैन्य पर्यवेक्षक के भाग के रूप मं तैनात छह हजार से भी अधिक कर्मिकों की तैनाती का योगदान ने भारत को संयुक्त राष्ट्र मिशनों के शीर्ष पांच सैन्य दल भागीदार में स्थान दिलाया है। भारतीय सेना की सैन्य टुकड़ियों को कुछ अत्याधिक गंभीर तथा अशांत संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात किया जाता है।

आईए मिशन

भारत की शांति की मध्यस्थताएँ

उत्प्रेरकों में हमारे योगदान के हिस्से के रूप में, भारत ने चार अस्पतालों जो लेवल । से लेवल ।।। तक विभाजित हैं, जिसमें एक इंजीनियरिंग कंपनी, एक पेट्रोलियम प्लाटून और एक फोर्स सिग्नल यूनिट (एफएसयू) को स्थापित किया है। इसके अलावा, भारत ने यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग कैपेबिलिटी रेडीनेस सिस्टम (पीसीआरएस) वेबसाइट में दस स्टाफ ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑब्जर्वर के अलावा एक रैपिडली डिप्लॉयबल इन्फैंट्री बटालियन, एक इंजीनियरिंग कंपनी और एक सिग्नल कंपनी का वादा किया है।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिलाओं की भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है और 2018 में अपेक्षित महिला अधिकारियों को तैनात किया है।

महिला तैनाती दल

- संयुक्त स्तर शीर्ष स्थापना मिशनों में महिला भागीदारी में और सुधार करने के लिए भारत ने डीआर कांगों में जून, 2019 में भारतीय रैपिडली डिप्लाएबल बटालियन के साथ एक महिला कार्रवाई टीम की तैनाती की है।

भारत सदस्य देशों के शांति सैनिकों को प्रशिक्षण देकर संयुक्त राष्ट्र की क्षमता निर्माण की दिशा में भी व्यापक योगदान दे रहा है। भारत के पास दिल्ली में श्सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंगश में एक सुस्थापित प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था, जो यूएन पीसकीपिंग पर भारत और विदेश दोनों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है। भारत ने 96 देशों के 1500 से अधिक विदेशी अधिकारियों और यूएन पीसकीपिंग में 7500 से अधिक भारतीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए सात अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र महिला सैन्य अधिकारी पाठ्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संभारिकी अधिकारी पाठ्यक्रम और अफ्रीकी भागीदारों के लिए संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग पाठ्यक्रम शामिल हैं।

मार्च, 2019 में, भारत पुणे में 17 अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ यूएन पीसकीपिंग एफिनडेक्स 2019 संबंधी एक बहु-राष्ट्रीय संयुक्त फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया।

विविध

स्वच्छ भारत अभियान

इस संबंध में निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(क) **'स्वच्छता ही सेवा' अभियान: नागरिकों की भागीदारी:** रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालयों की इकाइयों और संस्थानों द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान आयोजित किया गया,

(ख) **स्वच्छता पखवाड़ा :** भारत सरकार द्वारा 1-15 दिसंबर, 2019 को स्वच्छता पखवाड़ा घोषित किया गया था,

(ग) **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाएं:** स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए, सभी स्टेशनों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

'स्वच्छता ही सेवा अभियान: नागरिकों की भागीदारी	• दिनांक 02 अक्तूबर, 2019 को रक्षा मंत्रालय (सेना) कैंप लोकेशंस के एकीकृत मुख्यालय में एक केन्द्रीय श्रमदान का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी महिलाए, सैनिक और बच्चों ने स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण में भागीदारी की। वाद-विवाद एवं पेंटिंग प्रतियोगिता हेतु बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए ।
स्वच्छता पखवाड़ा	• स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के लिए रक्षा मंत्रालय (सेना) परिवहन इकाई के एकीकृत मुख्यालय में. स्वच्छता, पेंटिंग कम्पटीशन और साफ-सफाई, प्लास्टिक का प्रयोग न करने एवं वृक्षारोपण अभियान हेतु प्रतिज्ञा सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट परियोजना	• 80 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है और ये वर्ष 2015-16 से कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।

भारतीय सेना और सिविल प्राधिकरणों के बीच सहयोग

सैन्य नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम: ऑपरेशन सद्भावना और ऑपरेशन समरिटान: सेना ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित सैन्य नागरिक कार्रवाई कार्यक्रमों को बड़ी संख्या में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत के ऑपरेशन सद्भावना और ऑपरेशन समारिटन के तहत जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य में आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का भरोसा एवं विश्वास जीतना है।

सेना गुडविल स्कूल

- 44 गुडविल स्कूलों में से नियंत्रण रेखा वाले क्षेत्र में 18 स्कूल स्थित हैं । ये स्कूल 15000 बच्चों को शिक्षा . मुहैया कराने के साथ 1000 स्टॉफ को रोजगार प्रदान करते हैं। सेना पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है. 1388 छात्रों के उच्चतर अध्ययन को प्रायोजित किया गया है ।

चिकित्सा कैंप

- सेना चिकित्सा कोर (एएमसी) जम्मू कश्मीर एवं उत्तरीपूर्व क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों में ऑपरेशन सदभावना के तत्वाधान में बड़ी संख्या में चिकित्सा आउटरीच अभियानों का आयोजन करती है जिसने राष्ट्र और सशस्त्र सेनाओं के लिए गुडविल अर्जित किया है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान

- पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय एकीकरण टूर्स जिसमें छात्र एवं वरिष्ठ शामिल होते हैं, के आयोजन द्वारा भी कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2018-19 में इस प्रकार के कुल 89 टूर्स आयोजित किए गए हैं।

मानवीय पशु चिकित्सा (वेट) सहायता

- वर्ष भर के दौरान विभिन्न पशु चिकित्सा सहायता कैंपों में 37,287 जानवरों का उपचार किया गया। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र मिशन अब्रोड में असैनिकों के जानवरों हेतु भी पशु चिकित्सा सहायता कैंप कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 8253 जानवरों का उपचार किया गया। देश एवं विदेश में भारतीय सेना के इन प्रयासों ने बड़ी छवि अर्जित की है।

विविध

- आपरेशन सद्भावना परियोजना की योजना बनाते समय 'जलापूर्ति कार्यक्रम' विधुतीकरण एवं पशुपालन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को भी विधिवत महत्व प्रदान किया गया है ।

सेना द्वारा की गई पहलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

बाढ़ राहत कार्य

क. असम: असम के छह जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान, पुलों का निर्माण, संपर्क बहाल करने और लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 16 राहत दल और 4 इंजीनियर दल तैनात किए गए।

ख. त्रिपुरा (पश्चिम त्रिपुरा): खैरपुर (पुराना अगरतला) के क्षेत्रों में 14 से 17 जुलाई 2019 तक राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना की एक टुकड़ी को तैनात किया गया।

ग. पंजाब (संगरूर जिला): संगरूर जिले में फुलाद, मूनक ग्रामों के निकट घघर नदी के भारी वर्षा और उच्च जल स्तर के कारण प्रभावित लोगों के बचाव एवं राहत के लिए 18 जुलाई, 2019 से 24 . 2019 को बचाव एवं राहत अभियानों के लिए तीन आर्मी कॉलमों की तैनाती की गई।

घ. अगस्त 2019 (केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब): बचाव और राहत कार्यों के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्यों में विस्तृत रूप से राहत दल उपस्कर सहित तैनात किए गए। लगभग 40,000 लोगों को बचाव किया गया/सुरक्षित बचाया गया, लगभग 5000 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता दी गई और इन बचाव दलों द्वारा वर्ष 2019 के अगस्त माह में इन राज्यों में 24 टन राहत सामग्री राज्यों में वितरित की गई। प्रमुख बचाव और राहत अभियानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य	अवधि		संख्या			टिप्पणियां
	से	तक	राहत टीम	इंजीनियर टीम	मेडिकल टीम	
गुजरात	2 अगस्त, 2019	3अगस्त, 2019	2	4	–	बचाव –1463 खाद्य पैकेट – 825
कर्नाटक	4अगस्त, 2019	16 अगस्त, 2019	26	18	4	बचाव–19104 चिकित्सा सहायता –1652
महाराष्ट्र	4 अगस्त, 2019	13अगस्त, 2019	12	14	6	बचाव – 18133 चिकित्सा सहायता –1900
केरल	8 अगस्त, 2019	17अगस्त, 2019	28	26	3	बचाव – 1990 चिकित्सा सहायता– 1002
तमिलनाडु	9 अगस्त, 2019	12 अगस्त, 2019	6	–	–	बचाव–9
पंजाब	18 अगस्त, 2019	2 सितम्बर, 2019	18	–	–	बचाव – 1309 राहत सामग्री –24 टन

ङ. **सितंबर 2019 (राजस्थान और मध्य प्रदेश):** इस माह के दौरान, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य लगातार बारिश और कोटा बैराज के फ्लड गेट खोलने के कारण उफनती नदियों के कारण बाढ़ आप्लावक से प्रभावित हुए। बचाव और राहत अभियानों के लिए उपस्कर सहित दल तैनात किए गए। इन राहत दलों द्वारा वर्ष 2019 के सितंबर माह में इन राज्यों में लगभग 2642 लोगों को बचाया गया/सुरक्षित बाहर निकाला गया और लगभग 666 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।

बचाव और राहत कार्य

क. सिक्किम: 9 जनवरी, 2019 को भारी बर्फबारी और सड़क बंद होने के कारण विभिन्न स्थानों अर्थात मील 17, मील 13 पर लगभग 400 पर्यटक वाहन और कुल 2946 सिविलियन फंस गए। छग्गू झील 17 मील के बीच फंसे 2656 सिविलियनों को बचाया गया 490 सिविलियनों

को चिकित्सा राहत प्रदान की गई। शेष 290 सिविलियन जो 17 मिले और 13 मील के बीच फंसे थे को भी बचाया गया।

ख. **मेघालयः** खानों से निकलने वाले पानी को हटाने और फंसे खनन श्रमिकों को बचाने के लिए पंपों की स्थापना के लिए दो प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई। इंजीनियरों का एक दल जिसमें 3 अधिकारी और 45 अन्य रैंक (ओआर) थे, को मार्च, 25, 2019 से अप्रैल, 2, 2019 तक सहायता के तैनात किया गया।

ग. **चक्रवात वायु (गुजरात):** गुजरात में चक्रवात वायु प्रभावित जिलों को 11 से 14 जून, 2019 तक सहायता प्रदान की गई। जामनगर, द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, वेरावल और कच्छ (भुज) जिलों में 10 आर्मी कालम तथा 06 इंजीनियर टीमें तैनात की गईं। तटवर्ती / निम्न भू-भागीय क्षेत्रों से लगभग 2200 सिविलियनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चिकित्सा शिविरों/राहत शिविरों के आयोजन में भी सहायता प्रदान की गई।

घ. **बोरवेल से बचावः** देवास (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), फर्रुखाबाद और मथुरा (उत्तर प्रदेश) और जोधपुर (राजस्थान) में बोरवेल से बच्चों को बचाने के लिए सिविल प्राधिकारियों को दी जा रही सहायता के कई मामले हुए हैं।

त्योहारों के दौरान सहायता

क. **कर्नाटकः** 11वें मैसूर कुंभ महोत्सव (17 से 19 फरवरी, 2019 तक) के अवसर पर श्रद्धालुओं की आवाजाही (लगभग 10 लाख) को सुविधा के लिए मैसूर जिले के त्रिवेणी संगम में 7 फरवरी, 2019 को लगभग 780 फुट का एक पुल का निर्माण किया गया।

ख. **उत्तर प्रदेशः** कुंभ मेला 2019 के लिए 2 टीए कंपनियां, डाइविंग डिटेचमेंट और स्पेशल फोर्स टीम, 1 बम डिस्पोजल टीम, इंजीनियर संसाधन (बाउट असॉल्ट यूनिवर्सल टाइप (बीएयूटी) कैम्प की स्थापना के लिए, दो हेलीपैडों का निर्माण, पोंटून ब्रिज सेट का अनुरक्षण) और मेडिकल कवर एम्बुलेंस सहित दो त्वरित कार्रवाई चिकित्सा दल के अतिरिक्त चार एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन उपलब्ध कराए गए (चार एडवांस)।

ग. **उत्तराखंडः** रुड़की और हरिद्वार में कावड़ मेला के दौरान 17 से 30 जुलाई, 2019 तक डूबने से बचने के लिए लोगों के बचाव के लिए एक सैफ्टी टीम की तैनाती द्वारा सहायता प्रदान की गई।

***

भारतीय नौसेना

भारत एक समुद्रवर्ती राष्ट्र है, और यह देश बड़ी संख्या में व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय नौवहन लेन के किनारे स्थित है जो हिंद महासागर को पार करता है। मात्रा के हिसाब से हमारे व्यापार का 95% से अधिक और मूल्य के हिसाब से 68% समुद्री मार्ग से होता है। दुनिया भर में नए बाजारों की तलाश में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए, व्यापार आंकडों में भविष्य में और वृद्धि होगी। भारतीय नौसेना देश की समुद्री संप्रभुता और समुद्री गतिविधियों के असीम उपयोग की प्रमुख प्रवर्तक और गारंटर है।

भारतीय नौसेना में साजों-सामान और संसाधनों का उपयोग करके उच्च स्तर की समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) को बनाए रखा जा रहा है। एक नई मिशन-आधारित तैनाती अवधारणा लागू की गई है।

फ्रंट लाइन फ्लीट जहाजों को निरंतर तैनात किया जाता है।

जलदस्युता रोधी अभियानों के लिए अक्टूबर 2008 से अदन के खाड़ी क्षेत्र में तैनाती

हाल ही में हुए भू राजनैतिक घटनाक्रम के कारण इस क्षेत्र में घटती सुरक्षा स्थिति के दृष्टिगत फारस की खाड़ी में इंडिया फ्लैग मर्चेंट शिप्स की सुरक्षा करना।

आईएन द्वारा फ्रंटलाइन शिप तैनाती

विदेशी तैनाती

पूर्वी बेड़ों की (ईएफ) विदेशी तैनाती

क) भारतीय नौसेना जहाजों कोलकाता और शक्ति ने 3 अप्रैल से 31 मई, 2019 तक पूर्वी बेड़े ओएसडी 01/19 में भाग लिया। विदेशी तैनाती (ओएसडी) के दौरान जहाजों ने कैम राहन बे (वियतनाम), किंगदाओ (चीन), बुसान (दक्षिण कोरिया) और सिंगापुर का दौरा किया।

जहाजों ने कैम राहन बे (वियतनाम) में आईएन-वीपीएन द्विपक्षीय अभ्यास, किंगदाओ (चीन) में पीएलए (एन) आईएफआर, बुसान (दक्षिण कोरिया) और सिंगापुर में एडीएमएम प्लस अभ्यास, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (आईएमडीईएक्स), समुद्रवर्ती सूचना साझा करना अभ्यास (एमएआरआईएसएक्स) और सिंगापुर में एसआईएमबीईएक्स में भाग लिया।

जहाजों ने वियतनाम नौसेना बल के जहाजों के साथ मार्ग अभ्यास, ताइवान जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन और दक्षिण चीन सागर (संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फिलीपींस के जहाजों के साथ) में मल्टी-शिप ट्रांजिट में भी भाग लिया।

ख) भारतीय नौसेना के जहाजों सह्याद्री और किल्टन ने 24 अगस्त से 21 नवंबर, 2019 तक बैंकाक (थाईलैंड), सिहानोकविले (कंबोडिया), कोटा किनाबालु (मलेशिया), ससेबो और योकोसुका (जापान), मनीला (फिलीपींस) और जकार्ता (इण्डोनेशिया) के पूर्वी बेड़े ओएसडी 02/19 में भाग लिया। ओएसडी के दौरान, पोतों ने मलेशिया के साथ समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और यूएसएन और जेएमएसडीएफ के साथ मालाबार-19 में भाग लिया।

पश्चिमी बेड़ा (डब्ल्यूएफ) विदेशी तैनाती (ओएसडी)

भारतीय नौसेना के जहाज तरकश ने 15 जून से 15 अक्टूबर, 2019 तक वेस्टर्न फ्लीट ओएसडी 01/19 में भाग लिया। ओएसडी के दौरान, जहाज ने जिबूती, अलेक्जेंड्रिया (मिस्र), टंगियर्स (मोरक्को), कार्लस्क्रोन (स्वीडन), सेंट पीटर्सबर्ग (रूस), हेलसिंकी (फिनलैंड), बर्गन (नॉर्वे), कैडिज (स्पेन), डकार (सेनेगल), लागोस (नाइजीरिया), वाल्विस बे (नामीबिया), मापुटो (मोजाम्बिक) और रीयूनियन द्वीप समूह (फ्रांस) जैसे 13 देशों में पोर्ट कॉल किया।

जहाज ने यूके के साथ रूसी नौसेना दिवस समारोह, कोंकण-19 में भाग लिया और भारत और नाइजीरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 60 वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लिया।

सागर मैत्री 2:

भारतीय नौसेना जहाज सागरध्वनि ने एनपीओएल वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग मिशन सागरमैत्री 2 के हिस्से के रूप में 31 जुलाई से 27 अगस्त, 2019 तक पोर्ट क्लैंग (मलेशिया) और सिंगापुर के लिए ओएसडी किया।

प्रमुख अभ्यास

भारतीय नौसेना के जहाजों रण, ऐरावत, कोरा और घड़ियाल ने अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह तट पर 14 अक्तूबर से 18 अक्तूबर 2019 तक तटरक्षक बल सहित त्रि-सेना अभ्यास डीएएनएक्स -2019 में भाग लिया।

मई एवं जून 2019 में क्रमशः टंकर्स ऑफ फुजारिहा और ओमान की खाड़ी में हमले के दृष्टिगत भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में पारगमन कर रहे इंडियन फ्लेग्ड मर्चेंट वेसेल (आईएफएमवी) की सुरक्षा एवं रक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन 'संकल्प' को अंजाम दिया।

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास

ऑसिन्डेक्स-19:

भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना (आरएएन) द्विपक्षीय अभ्यास ऑसिन्डेक्स-19 को 2 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2019 से विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित किया गया था।

इन-वीपीएन बिलाट:

भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी (वीपीएन) द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण 14-18 अप्रैल, 2019 तक कैम राहन बे, वियतनाम में आयोजित किया गया था।

आई एफआर (इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू), किंगदाओ (चीन):

70वीं वर्षगांठ समारोह के भाग के रूप में 23 अप्रैल, 2019 को किंगदाओ, चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू (**आई एफआर**) में भारतीय नौसेना के जहाजों कोलकाता और शक्ति ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया।

एडीएमएम प्लस अभ्यास:

भारतीय नौसेना के जहाजों कोलकाता और शक्ति ने 29 अप्रैल से 2 मई, 2019 तक बुसान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के एडीएमएम प्लस देशों के साथ एडीएमएम प्लस अभ्यास में भाग लिया।

एडीएमएम प्लस अभ्यास

वरुण-19: भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण-19 दो चरणों में दिनांक 1 से 10 मई, 2019 तक गोवा में और 20 से 25 मई, 2019 तक जिबूती में आयोजित किया गया था। इन जहाजों विक्रमादित्य, चेन्नई, तरकश, दीपक, मुंबई, पनडुब्बियों शंकुल और कलावरी के साथ-साथ च्ह्प्समुद्री गश्ती विमान ने अभ्यास में भाग लिया, जबकि फ्रांसीसी पक्ष का प्रतिनिधित्व चार्ल्स डी गॉल, फोर्बिन, प्रोवेंस, लाटूचे ट्रेविल, मार्ने के साथ-साथ परमाणु पनडुब्बी एमेथिस्ट द्वारा किया गया था।

वरुण-19

सिम्बेक्स-19: भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (आरएसएन) द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स-19 का आयोजन दिनांक 18 से 24 मई, 2019 तक सिंगापुर में उसके तट पर किया गया था

सिटमेक्स-19

कोंकण-19:

भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास दिनांक 14 से 15 अगस्त, 2019 तक यूके में आयोजित किया गया था।

स्लिनेक्स-19:

भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना (एसएलएन) द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास (सिम्बेक्स-19) दिनांक 7-12 सितंबर, 2019 तक आयोजित किया गया था।

आईएन-आरएमएन बिलैट:

भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियन नेवी (आरएमएन) द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास-एक्स-समुद्र लक्ष्मण का दूसरा भाग दिनांक 12 सितम्बर से 16 सितम्बर, 2019 तक कोटा किनाबालु, मलेशिया के तट पर आयोजित किया गया था।

सिटमेक्स-19:

भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (आरएसएन) और रॉयल थाईलैंड नेवी (आरटीएन), के बीच पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास एसआईटीएमईएक्स-19 दिनांक 16 सितम्बर से 20 सितंबर, 2019 तक पोर्ट ब्लेयर में उसके तट पर आयोजित किया गया था।

सिटमेक्स-19

मालाबार-19: भारतीय नौसेना, जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) और यूएस नौसेना (यूएसएन) के त्रिपक्षीय अभ्यास मालाबार-19 का आयोजन दिनांक 26 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2019 तक जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था।

मालाबार-19

आइ एन-बीएन बिलाट: भारतीय नौसेना - बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास (आइएन-बीएन बिलाट) का पहला भाग दिनांक 12 अक्टूबर से 15 अक्तूबर, 2019 तक विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित किया गया था।

आईएमएनईएक्स-19 भारत-म्यांमार नौसेना अभ्यास (आइमेक्स -19) का दूसरा भाग दिनांक 18 अक्तूबर से 22 अक्तूबर, 2019 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था।

एक्सरसाइज समुद्र शक्ति: आईएन शिप कमोर्टा ने दिनांक 4 नवम्बर से नवम्बर, 2019 तक विशाखापत्तनम के तट पर समुद्र शक्ति (इन-इंडो बिलैट) में भाग लिया।

एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ: विशाखापत्तनम और काकीनाडा में दिनांक 13 नवम्बर से 21 नवम्बर, 2019 तक पहला भारत-अमेरिका संयुक्त त्रि-सेना एचएडीआर अभ्यास आयोजित किया गया था।

जैर-अल-बह्र (समुद्र की दहाड़): भारतीय नौसेना के जहाज त्रिकंद और समुद्री टोही विमान पी 8-। ने दोहा में दिनांक 17 नवम्बर से 21 नवम्बर 2019 तक आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जैर-अल-बह्र (समुद्र की दहाड़) के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

इंद्रा-19: रूसी नौसेना के साथ अभ्यास इंद्रा-19 का नौसेना घटक दिनांक 10 दिसम्बर से 19, 2019 तक गोवा में आयोजित किया गया था।

इन्द्र -19

चित्र 1 टाइगर विजय अभ्यास

हिन्द महासागर क्षेत्र की तटीय नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्ती (कॉर्पेट)

स्थापित समझौता ज्ञापनों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) की तटीय नौसेनाओं के साथ आईएमबीएल के साथ समन्वित गश्त आयोजित की जा रही है।

भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त
इण्डो-थाई कोरपेट का 28 वां चक्र दिनांक 5 सितम्बर से 12 सितम्बर 2019 आयोजित किया गया था।

भारत-म्यांमार समन्वित गश्त
9वीं भारतीय नौसेना और म्यांमार नौसेना कोरपेट (आईएमसीओआर) दिनांक 11 नवम्बर से 19 नवम्बर तक आयोजित किया गया था।

भारत-बांग्लादेश समन्वित गश्त
भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना (बीएन) सीओआरपीएटी का द्वितीय संस्करण दिनांक 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2019 तक आयोजित किया गया था।

तटीय सुरक्षा

नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस (एनसी 3 आई) नेटवर्क इंटर-लिंकिंग आईएन और आईसीजी के 51 स्टेशनों और कई सेंसर को एकीकृत करने का प्रभावी ढंग से डोमेन जागरूकता विकसित करने और अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए उपयोग किया जा रहा है। भारतीय नौसेना मछुआरों और तटीय समुदायों को समुद्रवर्ती सुरक्षा मैट्रिक्स को एकीकृत करने की दिशा में सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से उनके साथ जुड़ा हुआ है।

जीसैट 6 ट्रैकिंग ट्रांसपोंडर: समुद्रवर्ती और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में, भारतीय नौसेना और इसरो ने संयुक्त रूप से गुजरात और तमिलनाडु की 500 उप-20 मीटर मछली पकड़ने वाली नौकाओं (कुल 1000 ट्रांसपोंडर) के लिए जीएसएटी 6 उपग्रह-आधारित ट्रैकिंग ट्रांसपोंडर का प्रारम्भिक कार्यान्वयन गृह मंत्रालय और डीएडीएफ/राज्य मत्स्य विभागों के संयोजन से पूरा कर लिया है।

विदेशी सहयोग

चक्रवात 'इदाई'-मोजाम्बिक: दक्षिणी हिंद महासागर में काम कर रहे भारतीय नौसेना के जहाजों सुजाता और शार्दुल और आईसीजीएस सारथी नाम के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के जहाजों को मोजाम्बिक सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर पोर्ट बीरा, मोजाम्बिक की ओर मोड़ दिया गया ताकि भारतीय नौसेना की यूनिटों और भारतीय कृषि सहकारी विपणन(नेफेड) जैसी भारत सरकार की ईकाईयों और संबद्ध एजेंसियों और अपोलो अस्पताल, मुंबई जैसी नागरिक एजेंसियों से राहत/चिकित्सा सामग्री के साथ 15 मार्च, 2019 को चक्रवात 'इडाई' के कारण हुई तबाही के बाद स्थानीय आबादी को एचएडीआर प्रदान की जा सके।

साइक्लोन 'इडाई'- के पश्चात भारतीय नौसेना द्वारा राहत अभियान-मोजम्बिक

अंटार्कटिका के लिए 38 वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान: भारत के खाड़ी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए जनवरी से मई 2019 तक अंटार्कटिका के लिए 38वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान में एक हाइड्रोग्राफी पाठ्यक्रम क्वालिफाइड अधिकारी और एक हाइड्रो नाविक सहित एक दल ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में भाग लिया।

38वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान - अंटार्कटिका

व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज (डब्ल्यूएसआईई) समझौते: भारतीय नौसेना ने 36 देशों और तीन बहु राष्ट्रीय समूहों के साथ डब्ल्यूएसआईई) समझौतों को आगे बढ़ाया है। पिछले वर्ष में, डब्ल्यूएसआईई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

डब्ल्यू एस आई-ई करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- मालदीव
- मोजाम्बिक
- फिलीपीन्स

नौसेना से नौसेना का विचार-विमर्श

एचएडीआर पर आईडब्ल्यूजी की बैठक: एचएडीआर पर आईओएनएस कार्यकारी समूह की चौथी बैठक 17 दिसंबर से 18 दिसम्बर 2019 तक पश्चिमी नौसेना कमान में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, भारत सहित इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मालदीव, ओमान और थाईलैंड।

आईओएनएस कार्यकारी समूह (आईडब्ल्यूजी) के सदस्य देशों ने भाग लिया। ,

एचएडीआर पर आईडब्ल्यूजी की बैठक

कमीशनिंग और डीकमीशनिंग

आईएनए खंडेरी: प्रोजेक्ट 75 की दूसरी पनडुब्बी, आईएनए खंडेरी को 28 सितंबर, 2019 को रक्षा मंत्री द्वारा मुंबई में शुरू किया गया था।

आईएनएस खंडेरी को शुरू किया जाना

लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एमके IV) : आईएन एलसीयू एल56 29 जुलाई, 2019 को विशाखापत्तनम में शुरू किया गया था।

एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक: एयरक्राफ्ट कैरियर डॉक को 28 सितंबर, 2019 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया था।

आईएनएएस 313: इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 313 को 22 जुलाई, 2019 को चेन्नई, तमिलनाडु के मीनांबक्कम में शुरू किया गया था।

आईएनएएस 314: इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314 को 29 नवंबर, 2019 को नेवल एयर एन्क्लेव, पोरबंदर में शुरू किया गया था।

नौसेना उड्डयन: नौसेना उड्डयन आधुनिकीकरण की दिशा में अपने पथ पर एक महत्वपूर्ण मोड़ के लिए अग्रसर है। इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं:

रुचि की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

समुद्र में रक्षामंत्री दिवसः रक्षामंत्री ने 27-28 सितंबर, 2019 को करवार से दूर आईएनएस विक्रमादित्य में समुद्र में नौसेना के संचालन को देखा।

समुद्र में रक्षा मंत्री दिवस

समुद्र में एमओडी अधिकारी दिवसः 28 मई, 2019 के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए एक समुद्री यात्रा आयोजित की गई।

भारतीय नौसेना और सिविल प्राधिकरणों के बीच सहयोग

भारतीय नौसेना प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विभिन्न बचाव और राहत कार्यों के लिए सिविल प्राधिकरण को निरंतर सहायता प्रदान करती रही है।

इनमें बाढ़ के दौरान स्थानीय आबादी को सहायता, विदेशों से निकासी अभियान, विभिन्न स्थानों पर गोताखोरी सहायता, खोज और बचाव आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान की गई सहायता का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

नौसेना सिविक एक्शन कार्यक्रम

तटीय पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षणः तटीय पुलिस कर्मियों का व्यापक प्रशिक्षण जिसमें समुद्री उड़ानों के बारे में जानकारी प्रदान करना भी शामिल है, आयोजित किया जा रहा है। व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और भारतीय नौसेना ने तटीय पुलिस कर्मियों और नए भर्ती किए गए तटीय वार्डन दोनों को प्रशिक्षित किया है।

पुलिस कर्मियों को तटीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें नौकाओं को संभालना, वीबीएसएस, फायरिंग सी सर्वाइवल और समुद्र में तटीय सुरक्षा स्थितियों से निपटना शामिल है।

वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास: आईए, आईएएफ, आईसीजी, तमिलनाडु सरकार, एनडीएमए और एनडीआरएफ की भागीदारी के साथ मुख्यालयों, पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में भारतीय नौसेना द्वारा 2-4 अगस्त, 2019 तक चेन्नई में वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास -19 आयोजित किया गया था। अभ्यास गंभीर चक्रवात के कारण 'शहरी बाढ़' परिदृश्य पर आधारित था।

अभ्यास में सेमिनार, टेबलटॉप अभ्यास, प्रदर्शनी और कौशल प्रदर्शन शामिल थे। आठ देशों ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और सोमालिया के साथ-साथ आसियान सचिवालय के चौदह विदेशी पर्यवेक्षकों ने एचएडीआर अभ्यास में भाग लिया।

तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियान (सीएसएसी): इस अभियान का उद्देश्य मछली पकड़ने और तटीय समुदाय के बीच देश के तटीय सुरक्षा तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और तटीय सुरक्षा को बढ़ाने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व संबंधी जागरूकता पैदा करना है और किसी भी घटना की रिपोर्टिंग अथवा प्रासंगिक सूचना गश्ती जहाज को तुरंत देने की आवश्यकता संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना है।

(क) केरल के विभिन्न जिलों में मासिक आधार पर अभियान चलाए जाते हैं।

(ख) सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम: भारतीय नौसेना ने समय-समय पर पूर्वी तट के सभी तटीय जिलों में आईसीजी और मत्स्य पालन के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित किए।

(ग) 8 जुलाई से 20 जुलाई, 2019 तक महाराष्ट्र के कई तटीय जिलों (सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, ठाणे और मुंबई) में अभियान चलाया गया।

खोज और बचाव अभियान

पुरी रथ यात्रा: दिनांक 4 जुलाई से 12 जुलाई 2019 तक लाइफ गार्ड और प्राथमिक चिकित्सा पदों की स्थापना के लिए पुरी में पांच गोताखोरों और चार चिकित्सा सहायकों की एक टीम को तैनात किया गया था।

गोताखोरी संचालन/सहायता: जम्मू-कश्मीर इलाके में कई छोटी/बड़ी नदियां और झीलें शामिल हैं। नदियों/ नालों में डूबने की घटनाएं, असैन्य/सैन्य वाहनों, उपकरणों, हथियारों, भंडार आदि सहित अथवा दुर्घटनाओं में डूबने की घटनाएं सामान्य हैं।

मरीन कमांडो (मार्कोज) को विशेष रूप से गर्मी के मौसम में लगभग साप्ताहिक आधार पर डाइविंग सहायता के लिए बुलाया जाता है। इन कार्रवाइयों ने घाटी में सशस्त्र बलों की छवि को मजबूत करने का काम किया है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों के दिलों और दिमाग में मार्कोस के लिए एक विशेष पहचान बनी हुई है।

डाइविंग संचालन / सहायता

चक्रवात 'फैनी': अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान 'फैनी' ने 3 मई, 2019 को दक्षिण ओडिशा तट पर दस्तक दी। चक्रवात 'फैनी' के बाद के प्रभावों से प्रभावी ढंग से निपटने और नुकसान को कम करने के लिए एहतियाती उपाय करने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के नागरिक प्रशासन के समन्वय से भारतीय नौसेना द्वारा व्यापक तैयारी की गई थी।

ओड़िशा के तट पर भारतीय नौसेना के तीन जहाजों को इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों के साथ तैनात किया गया था। नागरिक प्रशासन के परामर्श से एसएआर/एचएडीआर प्रयासों को बढ़ाने के लिए आईएन डाइवर्शिंग/राहत टीमों को नियुक्त किया गया था।

विभिन्न स्थानों पर आईएनएस चिल्का से चिकित्सा और राहत दल तैनात किए गए और स्थानीय लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए पुरी और चिल्का में सामुदायिक रसोई स्थापित की गई।

सामुदायिक रसोइयों में कुल 7850 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया और ओडिशा में प्रभावित लोगों को लगभग 13 टन राहत सामग्री उपलब्ध कराया गया।

बचाव के प्रयास

मुंबई में लगातार बारिश: मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान (एचक्यूडब्ल्यूएनसी) का मुख्यालय जुलाई 2019 की शुरुआत से मुंबई में भारी बारिश के मद्देनजर नागरिक प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार था, जैसी कि आईएमडी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। सिटी प्रशासन के साथ समन्वय के लिए एक कमांड क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीसीएमजी) की स्थापना की गई थी।

भारतीय नौसेना टीमों द्वारा प्रदान की गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:-

क. कुर्ला में बचाव: 2 जुलाई, 2019 को, मानखुर्द और घाटकोपर में नौसेना स्टेशनों से आईएन की दो बचाव टीमें जुटाई गईं, जिन्होंने मीठी नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण फंसे क्रांति नगर, कुर्ला के प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रूप से बचाव केन्द्र तक पहुंचाया गया।

ख. महालक्ष्मी एक्सप्रेस से बचाव: 27 जुलाई, 2019 को भारी बारिश और बाढ़ के कारण मुंबई से 72 किलोमीटर पहले खड़ी महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रियों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना की बचाव टीमों को कोलाबा, मलाड, घाटकोपर, मानखुर्द और करंजा से भेजा गया था।, सभी 700 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस से रेस्क्यू

ग. कल्याण में बचाव : 27 जुलाई, 2019 को, भारतीय नौसेना की 5 बचाव टीमों ने, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की टीमों के साथ मिलकर कल्याण के कम्बा गांव में रिवरविंड्स रिजॉर्ट और एक पेट्रोल पंप से फंसे 300 कर्मियों को बचाया।

ऑपरेशन 'वर्षा राहत' : ऑपरेशन 'वर्षा राहत' के एक भाग के रूप में राहत अभियान चलाने के लिए 6 से 14 अगस्त, 2019 तक कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नौसेना के 44 बचाव दलों और भारतीय नौसेना के दो एएलएच हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। 14,239 लोगों को बचाया गया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 4,290 किलोग्राम भोजन/राहत सामग्री वितरित की गई।

ऑपरेशन 'वर्षा राहत'

जल विलोपित नौका- देवीपट्टनम, आंध्र प्रदेश: गोदावरी नदी में एसएआर आपरेशन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 16-17 सितम्बर, 2019 को विशाखापट्टनम से गोताखोर दल के साथ भारतीय नौसेना के दो हेलीकॉप्टर (यूएच3एच और सीएच) तैनात किए गए थे। 72 पर्यटकों में से 26 जीवित बचे और 25 शवों को निकाला गया।

गोदावरी नदी में एसएआर ऑपरेशन

बाढ़ राहत अभियान- सांगली, महाराष्ट्र : सांगली, कोल्हापुर और निकटवर्ती जिलों में बचाव अभियान में सहायता के लिए 6 अगस्त 2019 को नौसेना गोताखोरों का एक दल तैनात किया गया था। सप्ताह भर चले बचाव अभियान में 1000 से अधिक लोगों को बचाया गया था।

बाढ़ राहत अभियान – सांगली, महाराष्ट्र

नौसेना स्वास्थ्य कैंप

भारतीय नौसेना द्वारा सामाजिक सेवा पहुंच के भाग के रूप में वर्ष के दौरान कई बार चिकित्सा कैंप, रक्तदान कैंप, सामान्य स्वास्थ्य चौकअप और डेंटल कैंप आयोजित किए गए थे। ऐसे कैंपों का सामान्य जन के मध्य विश्वास पैदा करने और सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा।

चिकित्सा कैंप और रक्तदान – अंडमान निकोबार द्वीप समूह:– अंडमान एवं निकोबार कमान पिछले एक वर्ष से कमोरटा, कैंपबेल, बे, दिगलीपुर, कारनीकोबार सहित कई स्थानों पर बहु-विशिष्ट चिकित्सा कैंपों का नियमित रूप से आयोजन करती रही है जिसमें आँख, ईएनटी, मनोचिकित्सक, त्वचारोग विशेषज्ञ और दन्त अधिकारी की तैनाती की गई है। नियमित रूप से आईएनएचएस धनवन्तरी और विभिन्न यूनिटों में रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाते हैं और वार्षिक रूप से जीबी पंत अस्पताप ब्लड बैंक को 500 यूनिट ब्लड दान किया गया है।

चिकित्सा कैंप और रक्तदान

रक्तदान कैंप: नौसेना सप्ताह समारोह 2019 और कुछ यूनिटों की वार्षिकी के दौरान विभिन्न यूनिटों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान कैंपों का आयोजन किया गया। एकत्रित किए गए ब्लड को प्रत्येक स्टेशन की सिविल ब्लड बैंकों के लिए शरू किया जाता है। प्रत्येक रक्तदान कैंपों पर अभूतपूर्व परिणाम देखें गए हैं।

रक्तदान कैंप

चिकित्सा कैंप- वृद्धावस्था गृह : एनडब्ल्यूडब्ल्यूए, गोवा की आरोग्य विंग ने नौसेना हॉस्पीटलशिप जीवंती के साथ मिलकर दिनांक 14 नवम्बर 2019 को बोग्मालो के "हमारा घर" वृद्धावस्था गृह के निवासियों के लिए एक चिकित्सा कैंप आयोजित किया। इस कैंप में डाक्टरों की एक टीम थी जिसमें आईएनएचएस जीवंती से चिकित्सा विशेषज्ञ, आंख विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ और दांत के सर्जन थे एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, गोवा के एक जराचिकित्सक थे जो कैंप में विशेष चिकित्सा प्रदान करने के लिए मौजूद थे। कैंप से पहले आईएनएचएस जीवंती द्वारा वृद्धावस्था गृह के सभी 60 निवासियों के ब्लड् रिपोर्टों की जांच की गयी।

चिकित्सा कैंप- वृद्धावस्था गृह

भारतीय वायु सेना

वायु सेना शक्ति में भू-क्षेत्रों को पार किए बिना रणनीतिक परिणाम बनाने की क्षमता है। यह इसे पसंद किए जाने का प्राथमिक साधन बनाता है। भारतीय वायुसेना का वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध जैसे पारंपरिक युद्दों के दौरान सम्पूर्ण उपयोग, और 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान इसका सीमित उपयोग इस बिंदु को स्पष्ट करता है।

वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के साथ, भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां विविध,जटिल और गतिशील हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारतीय वायु सेना वास्तव में रूपांतरित और घातक सेना बनाने की राह पर अग्रसर है। शामिल की जा रही हथियार प्रणालियां दक्षता और सटीकता के साथ वायु सेना की शक्ति के उपयोग में वृद्धि करेगी।

परिकल्पना

युद्ध के स्पेक्ट्रम के चारों ओर सामरिक पहुँच और क्षमता अर्जित करना जिससे सैन्य कूटनीति के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा, राष्ट्र निर्माण और भारतीय रणनीतिक के प्रभावी क्षेत्र के भीतर बल प्रयोग को परिचालित करना है।

भारतीय वायु सेना का परिकल्पना

इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय वायु सेना पूर्ण स्पेक्ट्रम क्षमता के साथ एक सामरिक एयरोस्पेस शक्ति में बदलने के लिए एक केंद्रित आधुनिकीकरण योजना को अनुसरण कर रही है।

राफेल विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट्स, सरफेस-टू-एयर गाइडेड वेपन्स (एसएजीडब्ल्यू) और एयर डिफेंस राडार के शामिल होने से संक्रियात्मक दक्षता और क्षमता बढ़ेगी।

भारतीय वायु सेना केंद्रित, निरंतर और विकसित स्वदेशी कार्यक्रमों के माध्यम से श्मेक इन इंडियाश को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास कर रही है। भारतीय वायु सेना विदेश निर्मित रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को आगे और कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिग्रहण और उन्नयन

एलसीए: लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) एयोरनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) द्वारा विकसित और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित किया गया है। पहला एलसीए स्क्वाड्रन 1 जुलाई, 2016 को तैयार किया गया था। एलसीए के लिए एफओसी 21 फरवरी, 2019 को प्रदान किया गया था। एचएएल ने एफओसी विमान का उत्पादन शुरू कर दिया है और वर्ष वर्ष 2019-20 तक चार एफओसी लड़ाकू विमानों की सुपुर्दगी की योजना बनी है और 2019 तक चार एफओसी लड़ाकू विमानों और 2020-21 तक 12 एफओसी फाइटर विमान की आपूर्ति की योजना बनाई है। इसके अलावा भारतीय वायु सेना ने 83 एलसीए एमके 1 ए विमान प्राप्त करने की योजना बनाई है, जिसके लिए बातचीत चल रही है।

राफेल विमान: राफेल लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता प्रदान करेगा और हमारे विरोधियों की तुलना में एक मजबूत हथियार और प्रणाली क्षमता बढ़त प्रदान करेगा। राफेल के वेपन के पैकेज में हवा से हवा में मार करने वाली बीवीआर मीटिओर मिसाइल शामिल है जो हमारे विरोधियों की तुलना में क्षमता पर भारतीय वायुसेना को एक अलग बढ़त प्रदान करेगी। जमीनी लक्ष्यों के लिए, राफेल लंबी दूरी की स्काल्प प्रोसीजन सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसके अलावा, भारतीय वायु सेना राफेल में कुछ भारत विशिष्ट संवर्द्धन हैं जो उच्च तुंगता वाले इंजन स्टार्ट के लिए क्षमता सहित बेहतर क्षमता वाले विमान प्रदान करते हैं जो हिमालयी क्षेत्र से संचालन को सक्षम करेगा।

सुखोई एमकेआई विमानः भारतीय वायु सेना ने 272 सुखोई-30 एमकेआई के लिए अनुबंध किया था। वर्तमान में, ब्लॉक IV अनुबंध के तहत सुपुर्दगी जारी है और मार्च 2020 तक इसके पूरे होने की

संभावना है। यह हवा से हवा में मार करने वाली एस्ट्रा मिसाइल है और बहुत लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस हथियार के साथ एकीकृत है।

मिराज-2000 अपग्रेडः मिराज-2000 विमान की लड़ाकू प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए, विमान को थेल्स और दसॉल्ट एविएशन [मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम)] और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के माध्यम से अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड एक नया और अधिक शक्तिशाली रडार, पूर्ण अत्याधुनिक एवियोनिक्स सूट और स्मार्ट वेपन प्रदान करता है, जो भविष्य की सभी युद्ध संक्रियाओं में विमान को संक्रियात्मक रूप से प्रासंगिक बनाए रखेंगे।

मिग-29 अपग्रेडः मिग-29 को 63 मिग-29 विमानों के उन्नयन और कार्य अवधि विस्तार के लिए रसियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन 'मिग', (आरएसी 'मिग'), रूस द्वारा अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड किए गए विमानों को फ्रंटलाइन स्क्वाड्रनों को आवंटित किया गया है और अब सामान्य संक्रियाओं के लिए उपयोग किया जा रहा है

जगुआर डारिन-III अपग्रेड : एचएएल द्वारा डैरिन-I जगुआर विमान का डैरिन-III मानक में उन्नयन निम्नलिखत रूप में शामिल है।

डारिन-I में अपग्रेड

नए मिशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन प्रणालियों के एकीकरण के साथ, कॉकपिट को पूरी तरह कार्यात्मक ग्लास कॉकपिट में बदल दिया गया है।

परिवहन बेड़ा

हरक्यूलिस सी 130 जे-30: सी-130 जे एक मध्यम आकार का सभी मौसम में चलने वाला परिवहन विमान है जो इंटर थिएटर और इंट्रा थिएटर एयरलिफ्ट संक्रियाओं में सक्षम है। यह एयरड्रॉप या एयर-लैंडेड ऑपरेशंस द्वारा योद्धी सैन्य टुकड़ियों/कार्मिकों या कार्गो की सुपुर्दगी कर सकता है। भारतीय वायु सेना ने विमान के लिए एनवीजी की अधिप्राप्ति करके विमान की संक्रियात्मक क्षमता को बढ़ाया है और अब यह विमान अंधेरी रात में भी काम कर सकता है।

लांग-हॉल मिशन के लिए सी-17 ग्लोबमास्टर एयरबोन

भारतीय वायुसेना के रंग में हरक्यूलिस सी-130जे विमान

हेलीकाप्टर बेड़ा

लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच): भारतीय वायुसेना एचएएल से आईएएफ के लिए 10X एलसीएच लिमिटेड सिरीज उत्पादन (एलएसपी) की अधिप्राप्ति कर रहा है। वर्तमान में यह मामला अग्रिम चरण में हैं।

अपाचे हेलीकॉप्टर: हेलीकॉप्टर एक टेंडेम सीटिंग, दिन/रात, सभी मौसम में सक्षम प्लेटफॉर्म है। यह अत्यधिक दक्ष है, युद्ध क्षति की तुलना में सर्वाइवेबल है और युद्धक परिस्थितियों में भी

इसकी आसानी से मरम्मत की जा सकती है। हेलीकॉप्टर उष्णकटिबंधीय और रेगिस्तान क्षेत्रों में लंबे समय तक संचालन करने में सक्षम हैं।

हल्का लड़ाकू हैलिकाप्टर

एयर कॉम्बैट, एडी, सीआई ऑप्स, यूएवी न्यूट्रलाइजेशन, सीएसएआर, अर्बन वारफेयर में तैनाती के लिए सक्षम मल्टी-रोल नेटवर्क केंद्रित प्लेटफॉर्म होने के नाते, विमान भारतीय वायुसेना की सभी आवश्यकताओं के साथ-साथ सेना की स्ट्राइक कोर आवश्यकताओं को पूरा करता है। अत्याधुनिक फायर कंट्रोल रडार (एफसीआर) से लैस, 64-एएच में दिन के उजाले, रात और कम दृश्यता की स्थिति में लक्ष्य का पता लगाने, स्थिति का पता लगाने, पूर्वनिर्दिष्ट करने, ट्रैक करने और लक्ष्य को भेदने की क्षमता है।

हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर (एचएलएच) मार्च 2019 से 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी शुरू हो गई थी और मार्च 2020 में पूरी हो गई है।

हैवी लिफ्ट हेलीकाप्टर

मुकाबला करने वाले विमान

द्वितीय एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एईडब्ल्यूएंडसी): दो एईडब्ल्यूएंडसी विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है।

द्वितीय विमान वाहित प्रारंभिक चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली

यूएवी का उन्नयनः यह उन्नयन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मित्र अथवा शत्रु की पहचान, ट्रैफिक कॉलिसन से बचाव प्रणाली, संचार/रेडियो रिले, वाइड आई मोजेक क्षमता और रिमोट वीडियो टर्मिनल की क्षमता प्रदान करेगा।

यूएवी

हथियार और एसोसिएटेड एवियोनिक्स

लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम): भारतीय वायुसेना ने एस -400 मिसाइल लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) प्रणाली की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। मैसर्स रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, रूस के साथ 5 अक्टूबर, 2018 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रणाली की अधिप्राप्ति और 2020 में इसके शामिल होने से देश की वायु रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

लम्बी दूरी की सतह से मार करने वाली मिसाइल

अतिरिक्त आकाश मिसाइल प्रणालियों की अधिप्राप्तिः बीईएल से आकाश मिसाइल सिस्टम की अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध पर 13 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं और सुपुर्दगी अनुबंध के अनुसार की जाएगी।

आकाश मिसाइल सिस्टम

एमआरएसएएमः भारतीय वायु सेना के लिए एमआरएसएएम कार्यक्रम में डीआरडीओ द्वारा मिसाइलों के साथ फायरिंग यूनिट्स (एफयू) का संयुक्त विकास और सुपुर्दगी शामिल है और पहली एफयू की सुपुर्दगी डीआरडीओ द्वारा अनुमानित समयसीमा के अनुसार जून 2020 की दूसरी तिमाही से शुरू होने की संभावना है।

अस्त्रः डीआरडीओ द्वारा अभिकल्पित और विकसित की जा रही अस्त्र बीवीआर मिसाइल के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और मिसाइल फायरिंग सफल रहा। भारतीय वायु सेना द्वारा लड़ाकू विमानों के लिए इन मिसाइलों को खरीदने की योजना कर रहा है।

सुखोई-30 एमकेआई विमान पर ब्रह्मोस हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइल का एकीकरणः

मिसाइलों की खरीद के साथ-साथ सुखोई-30 एमकेआई विमान पर ब्रह्मोस मिसाइल को एकीकृत करने के लिए ठ।च्स् के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मिसाइल के आकार और भार को देखते हुए, इसे सुखोई-30 एमकेआई पर एकीकृत करना भारतीय वायुसेना और संबंधित हितधारकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सफल हथियार एकीकरण और लॉन्च की एक श्रृंखला के बाद, सिस्टम पूरी तरह परिचालनात्मक है। यह महत्वपूर्ण रूप से विमान की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाता है।

जगुआर विमान के लिए : एनजीसीसीए नई पीढ़ी के क्लोज कॉम्बैट मिसाइल (एनजीसीसीएम), जगुआर ओवर विंग लॉन्चर (जेओडब्ल्यूएल) के साथ-साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम (एचएमडीएस) और जगुआर के लिए संबद्ध उपकरणों के एकीकरण और आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। एकीकरण परीक्षण प्रगति पर हैं। एकीकरण के सफल होने पर, हवाई युद्ध में भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी।

प्रशिक्षक विमान

उन्नत जेट प्रशिक्षक (हॉक एमके-132): वर्तमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलटों की भावी पीढ़ियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना हॉक विमान का संचालन करती है।

हॉक 132 स्काट कलर्स में

हॉक विमान एक ट्रांसोनिक टेंडेम सीट ग्राउंड अटैक और फ्लाइंग/हथियार प्रशिक्षण विमान है। उड़ान प्रशिक्षण भूमिका के लिए उपयोग किए जाने पर, यह बुनियादी और उन्नत लड़ाकू और हथियार प्रशिक्षण प्रदान करता है। संक्रियात्मक भूमिका में इसका उपयोग एक शक्तिशाली ग्राउंड अटैक विमान के रूप में किया जा सकता है जो आधुनिक हथियारों के एक बड़े चयन को ले जाने और इसकी सुपुर्दगी करने में सक्षम है।

एचटीटी-40: एचटीटी-40 को एचएएल द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है और वर्तमान में दो प्रोटोटाइप विमानों पर परीक्षण उड़ानें की जा रही हैं। आईएएफ एचटीटी-40 और संबंधित उपकरणों की खरीद करेगा।

एयरोस्पेस सुरक्षा

पिछले एक दशक में भारतीय वायुसेना और सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एयरोस्पेस सुरक्षा रिकॉर्ड में सुधार हुआ है।

विमान दुर्घटना दर: वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेणी-I दुर्घटनाओं की संख्या के रूप में गणना की गई वार्षिक विमान दुर्घटना दर में श्रेणी-I कई वर्षों से उत्तरोत्तर गिरावट देखी गई है।

उड़ान के प्रयास: एक ओर तो उड़ान प्रयास में निरंतर वृद्धि हुई है और दूसरी ओर दुर्घटना दर में कमी आई है। उड़ान में वृद्धि के साथ संरक्षित परि संपत्तियां सीधे तौर पर परिचालन क्षमता बढ़ाने में योगदान करती हैं। पिछले दस वित्तीय वर्षों के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा वित्तीय वर्ष वार उड़ान प्रयासों को नीचे दर्शाया गया है: -

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उड़ान सुरक्षा उपाय

रक्षा मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2004 में विमान दुर्घटनाओं के मूल कारणों की पहचान करने और नुकसान को कम से कम करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के एक विशेषज्ञ समिति का

गठन किया गया था। समिति ने मई 2005 में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और एक्सकॉम की सिफारिशों को भारतीय वायुसेना द्वारा लागू किया गया।

जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, उनका वर्णन नीचे किया गया है:

महत्वपूर्ण सुधार के क्षेत्र

क) **सिमुलेटर:** वास्तविक उड़ान में शामिल जोखिम को बढ़ाए बिना वास्तविक वातावरण में एयरक्रू को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सिमुलेटर शामिल किए गए हैं। सभी नए विमान शामिल करने के लिए सिमुलेटर अनिवार्य रूप से खरीदे जाते हैं। एचपीएचसी (हाई परफॉरमेंस ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज) और डीआईएसओ (डिसओरिएंटेशन) सिमुलेटर सभी एयरक्रूज के लिए ऑप्टराम (ऑपरेशनल ट्रेनिंग इन एयरोस्पेस मेडिसिन) कोर्स के संचालन के लिए खरीदे गए हैं।

ख) एरर मैनेजमेंट (एएफएसईएम) और अन्य उपायों संबंधी वायु सेना प्रणाली: एएफएसईएम एक ऑनलाइन टूल है जो भारतीय वायु सेना को दुर्घटनाओं का कारण बनने वाली त्रुटियों को पहचानने और समय पर उपचारात्मक उपाय करने में मदद करता है। संचालन में सुरक्षा पहलुओं को एकीकृत करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) और चालक दल संसाधन प्रबंधन (सीआरएम) जैसी अवधारणाओं का पालन किया जा रहा है। दुर्घटना संभावना कारक (एपीएफ) कैलकुलेटर, एक सॉफ्टवेयर-आधारित उपकरण हैं जिसका उपयोग प्रभावी दुर्घटना प्रभावी रोकथाम कार्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से आईएएफ बेसेस पर विमान बेड़े और परिचालन माहौल के लिए विशिष्ट जोखिमों और खतरों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

प्रचालन परिवेश: नए विमानों को शामिल करने के साथ-साथ मौजूदा बेड़े की सुविधाओं के उन्नयन के लिए परिचालन अवसंरचना में सुधार किए गए हैं।

मानव कारक विश्लेषण और वर्गीकरण प्रणाली (एचएफएसीएस): मानव त्रुटि के मूल कारण की पहचान करने और उसी प्रकार दुर्घटना जांच के दौरान एचएफएसीएस की शुरुआत, दुर्घटनाओं की रोकथाम में इसका उपयोग करने के लिए की गई है।

पक्षी जोखिम प्रबंधन उपाय: स्थानीय दशाओं के अनुरूप पक्षी जोखिम प्रबंधन उपायों को नया रूप दिया गया है। पक्षियों के हमले की सभी घटनाओं में, पक्षियों के अवशेषों को प्रजातियों की पहचान करने के लिए फिजियोलॉजी और संबद्ध विज्ञान के रक्षा संस्थान (डीआईपीएएस) को भेजा जाता है और इस प्रकार आगे की घटनाओं से बचने के लिए प्रजातियों के विशिष्ट निवारक उपाय करने में मदद मिलती है। स्थापित किए गए अन्य उपायों में ऑर्निथोलॉजी सेल द्वारा किए गए अध्ययन और पक्षी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करना शामिल है। पक्षियों के जोखिम नियंत्रण उपायों में वृद्धि करने के लिए एवियन रडार (बर्ड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग रडार) की खरीद का मामला उठाया गया है। भारतीय वायु सेना ने पक्षियों के सर्वेक्षण और पक्षियों के जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ाने के लिए 72 नए माइक्रोलाइट विमान शामिल किए हैं।

अंतरिक्ष कार्यक्रम

मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम:

भारतीय वायु सेना और इसरो ने पांच साल की अवधि के लिए एक सफल एचएसपी के संबंध में सहयोग के लिए मई 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एचएसपी मिशन के लिए अंतरिक्ष चालक दल का चयन मौजूदा आईएएफ परीक्षण पायलटों में से किया जाता है है। इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन (आईएएम), आईएएफ बैंगलोर को एयरोस्पेस मेडिसिन में अपने डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग करके इसरो एचएसपी का समर्थन करने वाली प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया गया था।

आईएएम की जिम्मेदारियां

एचएसपी कार्यक्रम एयरोस्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में दक्षता, क्षमताओं और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय वायुसेना और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं को अवसर प्रदान करता है। यह पहला स्वदेशी मिशन है जो भारत और इसरो को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं और शक्ति को स्थापित करने में भी सक्षम करेगा।

भारतीय वायु सेना और सिविल अधिकारियों के बीच सहयोग

सिविल प्राधिकरणों की सहायता: भारतीय वायु सेना देश में किसी भी संकट के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होने पर निश्चित रूप से सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला होता है। देश के भीतर और साथ ही देश के बाहर मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना की विभिन्न परिवहन परिसंपत्तियों द्वारा कई मिशनों को सफल बनाया गया है, जिसमें परिवहन बेड़े ने 4251 यात्रियों और 1630 टन भार को ले कर 980 घंटे में 406 उड़ानें भरीं। कुछ विशिष्ट आपरेशंस का उल्लेख नीचे किया गया है:

(क) **जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए एयरलिफ्ट:** फरवरी 2019 की शुरुआत में भारी हिमपात के कारण जम्मू-कश्मीर में सड़कें बंद हो गई थीं। जम्मू में गेट परीक्षा होने के कारण 500 से अधिक छात्र घाटी में फंस गए थे। दो सी-17, विमानों को 8-13 फरवरी, 2019 के दौरान 546 छात्रों सहित जम्मू-कश्मीर के 1263 नागरिकों को एयरलिफ्ट करने का काम सौंपा गया था।

(ख) **सीआरपीएफ के नश्वर अवशेषों को एयरलिफ्ट करना:** 15 फरवरी, 2019 को श्रीनगर से दिल्ली तक पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ कर्मियों के 40 शवों को एयरलिफ्ट करने का काम एक सी-17 एसी को सौंपा गया था। इन्हें आगे सी-17, सी -130जे, एएन -32 और डीओ-228 वायुयानों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।

(ग) **चक्रवात राहत (ओडिशा और गुजरात) :** दिनांक 4-5 मई, 2019 को, एक सी -17 और तीन सी -130 जे ने चक्रवात फैनी राहत के लिए भारतीय वायु सेना विमान द्वारा दिल्ली से भुवनेश्वर तक 75 टन दवाएँ पहुँचाई। 11-12 जून, 2019 को, 03 ◦ सी-17 विमानों को चक्रवात वायु के मद्देनजर विजयवाड़ा, अराकोनम और पटना से जामनगर और अहमदाबाद तक एनीआरएफ की टीमों को एयरलिफ्ट करने का काम सौंपा गया था।

***

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE

रक्षा अनुसंधान और विकास

पृष्ठभूमि

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) अपनी प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के विस्तृत स्पेक्ट्रम के साथ रक्षा आवश्यकताओं की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है, जो महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के लिए आत्मनिर्भरता के पीछे एक बल है। डीआरडीओ ने अपने अनुसंधान के लिए नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। ये हैं (i) प्लेटफॉर्म (ii) हथियार प्रणालियां (iii) सामरिक प्रणालियां (iv) सेंसर और संचार प्रणालियां (v) अंतरिक्ष (vi) साइबर सुरक्षा (vii) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स (viii) सामग्री और उपकरण और (vx) सैनिक सहायता।

कार्यक्रम और परियोजनाएं

डीआरडीओ परियोजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

डीआरडीओ परियोजनाओं का वर्गीकरण

वर्ष 2019 के दौरान, ₹ 4,672 करोड़ की कुल लागत से 84 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी और ₹ 8,781 करोड़ की कुल लागत से 34 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

डीआरडीओ के पास लगभग ₹ 68,820 करोड़ (डीआरडीओ का हिस्सा: ₹37419 करोड़, 54%) की लागत वाली 399 चालू परियोजनाएं (सामरिक परियोजनाओं को छोड़कर) हैं । 399 चालू परियोजनाओं में से 38 बड़ी परियोजनाओं (लागत ≥ ₹300 करोड़) की लागत ₹55,856 करोड़ है।

सुरक्षा मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) द्वारा ₹41,677 करोड़ (डीआरडीओ का हिस्सा: ₹12,010 करोड़) के 8 प्रमुख कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है।

सीसीएस की विभिन्न परियोजनाएं

डीआरडीओ परियोजनाओं में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि/उपलब्धियां

i. **एंटी-सैटेलाइट मिसाइल (मिशन शक्ति):** डीआरडीओ ने मार्च 2019 में ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी-सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल 'मिशन शक्ति' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस परीक्षण ने विश्व स्तर पर अपनी संपत्ति की रक्षा करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही भारत को ऐसी क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल किया गया है।

ii. **दृष्टि रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र':** आधुनिक दिशानिर्देश और नवाचार तकनीकों के साथ दृष्टि सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल (बीवीआरएएएम) 'अस्त्र' का विकास पूरा हो गया है। सितंबर 2019 के दौरान ओडिशा के चांदीपुर के तट पर सुखोई-30 एमके । प्लेटफॉर्म से अस्त्र का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल का विकास परीक्षण पूरा हो चुका है।

iii. **नौसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम):** एमआरएसएएम भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई), इजराइल का एक संयुक्त विकास कार्यक्रम है। वर्ष के दौरान, भारतीय नौसेना ने एमआरएसएएम की इसकी पहली समन्वय विनियोजन फायरिंग सहित अपनी एंटी-एयर युद्ध क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विनियोजन के इस समन्वय तरीके समन्वय तरीके के सफल साबित होने के साथ-साथ भारतीय नौसेना इस विशिष्ट क्षमता वाली मिसाइलों में एक चुनिंदा समूह का हिस्सा बन गई है।

iv. **सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस':** भारत और रूस द्वारा विकसित, बहुमुखी ब्रह्मोस को तीनों सेनाओं सहित भारतीय सशस्त्र बलों में परिचालित किया गया है। 22 मई, 2019 को, भारतीय वायुसेना ने भूमि लक्ष्य को भेदने के लिए अपने फ्रंटलाइन सुखोई-30 एमके-। लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर वर्जन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 24 मई, 2019 को, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। स्वदेशी बूस्टर प्रणोदन प्रणाली, एयरफ्रेम, बिजली आपूर्ति और अन्य प्रमुख स्वदेशी घटकों

वाली मिसाइल का 30 सितंबर, 2019 को आईटीआर, चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 17 दिसंबर, 2019 को, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित सीकर के साथ ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके अलावा, उसी दिन, वायु सेना की आवश्यकताओं के अनुसार समुद्री लक्ष्य के खिलाफ सुखोई-30 एकके-। विमान से एयर वर्जन ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।

v. **टैंक-रोधी मिसाइल (प्रॉसपीना):** 'नाग', दिन और रात की क्षमताओं के साथ अत्यधिक मोर्चाबंदी वाले दुश्मन के टैंकों को सामना कर सकता है। नाग - नामिका प्रणाली को जीएसक्यूआर के अनुरूप पाया गया है, जिससे भारतीय सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय सेना को 'नाग' मिसाइलों और नामिका के उत्पादन के लिए डीएसी से एलएसपी ऑर्डर (एओएन) दिया गया है।

vi. **तीसरी पीढ़ी के हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल ('हेलिना'/ध्रुवास्त्र):** हेलिना उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) पर एकीकरण के लिए एलओबीएल क्षमता के साथ तीसरी पीढ़ी का हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) है। वर्ष के दौरान, एएलएच से 13 उड़ान परीक्षण किए गए और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित पृथक्करण का प्रदर्शन किया गया। अगस्त 2019 के दौरान भारतीय वायुसेना के एएलएच से टारगेट हिट विद सीकर का प्रदर्शन किया गया था।

vii. **आकाश एमके-। एस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल:** आकाश मार्क-। एस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो उन्नत हवाई लक्ष्यों को बेअसर कर सकती है। यह मिसाइल स्वदेशी सीकर के साथ आकाश मिसाइल का उन्नयन है। आकाश मार्क-। एस मिसाइल स्वदेशी सीकर सहित पहली स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली बन गई है जिसे भारतीय सेना के अगले दो रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा।

viii. **स्मार्ट हवाई-रोधी फील्ड हथियार (एसएएडब्ल्यू):** एसएएडब्ल्यू लंबी दूरी, स्टैंड-ऑफ, सटीक हवा से सतह पर मार करने वाला हथियार है जो जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। वर्ष के दौरान, जगुआर डारिन ।। पर एकल विन्यास में आठ उड़ान परीक्षण पूरे किए गए, जो मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करता है।

ix. **लंबी दूरी के ग्लाइड बम (एलआरजीबी):** डीआरडीओ पारंपरिक वारहेड्स जैसे ब्लास्ट प्री-फ्रैगमेंटेशन (पीएफ) और पेनेट्रेशन कम ब्लास्ट (पीसीबी) के डिजाइन, विकास और परीक्षण में शामिल है। मई 2019 के दौरान, सुखोई-30 एमके-। विमान से नॉन विंग्ड ग्लाइड बम प्रदर्शन परीक्षण कार्यान्वित किए गए थे।

x. **हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) 'तेजस':** एक ऐतिहासिक अवसर पर, 20 फरवरी, 2019 भारतीय वायुसेना के लिए एलसीए 'तेजस' मार्क-। की यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिन है, जब विमान की अंतिम परिचालन मंजूरी (एफओसी) की औपचारिक घोषणा की गई थी।

श्री राजनाथ सिंह, 19 सितंबर, 2019 को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) 'तेजस' को उड़ाने वाले पहले रक्षा मंत्री (आरएम) बने। उन्होंने बेंगलुरु में बहुद्देश्यीय लड़ाकू विमान में 30 मिनट की उड़ान भरी।

- **एलसीए तेजस भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एडवांस्टड प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डिजाईन और विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है।**
- **यह सुपरसोनिक, लाईट वेट, सभी मौसमों के अनुकूल, बहु-युद्ध भूमिकाओं के लिए डिजाईन किया गया मल्टी-रोल फाईटर एयरक्राफ्ट है**

xi. **हल्के भार वाले नौसेना युद्धक विमान:** 2019 में गोवा के तट आधारित परीक्षण सुविधा (एसबीटीएफ) आईएनएस हंसा में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (नौसेना) की पहली अरेस्टेड लैंडिंग सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई। इसके सफल परीक्षण ने भारत को विश्व के नक्शे पर डेक लैंडिंग विमान डिजाइन करने की क्षमता से लैस राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया।

xii. **एयरबोर्न पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (एईडब्ल्यू एवं सी)** प्रणाली: एईडब्ल्यू एवं सी हवाई और जमीन-आधारित परिसंपत्तियों और उनके सटीक स्थान स्थिति का पता लगाने के लिए, ट्रैक-व्हाइल-स्कैन और प्राथमिकता-ट्रैक मोड के माध्यम से हवाई खतरों की 'पहचानने योग्य हवाई निगरानी तस्वीर' देने में सक्षम है।

वर्ष के दौरान, डीआरडीओ ने सेना की नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 11 सितंबर, 2019 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (एईडब्ल्यू एवं सी) प्रणाली में से दूसरा सौंप दिया।

xiii. स्माल टर्बो फैन इंजन (एसटीएफई)**:** डीआरडीओ सबसोनिक अनुप्रयोगों के लिए लक्षित मानव रहित वायु वाहनों (यूएवी) की प्रणोदन आवश्यकताओं के लिए एक लघु टर्बोफैन इंजन (एसटीएफई) विकसित कर रहा है। 'निर्भय' सब-सोनिक क्रूज मिसाइल के साथ एसटीएफई का एकीकरण परीक्षण किया गया है और 3 नंबर के एसटीएफई इंजन को उपयोगकर्ता को सुपुर्द किए जाने हेतु तैयार किया जा चुका है।

गाइडेड पिनाका रॉकेट प्रणाली: गाइडेड, कैनार्ड नियंत्रित सटीक आघात निदेशित आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली सहित निदेशित पिनाका को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस रॉकेट प्रणाली में 20 किमी से 80 किमी की सीमा में लक्ष्य को भेदने की क्षमता मौजूद है। प्रणाली का तकनीकी परीक्षण मार्च 2019 में किया गया था। अगस्त 2019 के दौरान निदेशित पिनाका वारहेड का थर्मो-स्ट्रक्चरल परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था।

xiv. **मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) 'अर्जुन' एमके-ए:** एमबीटी 'अर्जुन' एक बहु-आयामी उच्च प्रौद्योगिकी गहन लड़ाकू वाहन प्रणाली है जो कई पहलुओं में दुनिया के समकालीन टैंकों के साथ तुलनीय है। एमबीटी अर्जुन में उत्कृष्ट गतिशीलता, बेहतर आघात क्षमता और उच्च स्तर की सुरक्षा मौजूद है। भारतीय सेना एमबीटी अर्जुन एमके-।ए के दो रेजिमेंटों के लिए मांगपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

xv. **उन्नत कम भार वाले टॉरपीडो (एएलडब्ल्यूटी):** कुल 10 सक्रिय परीक्षण आयोजित किए गए थे जिसमें स्थिरता और नियंत्रण, गति और गहराई में परिवर्तन और वाहन की पूर्ण क्षमता सत्यापित की गई थी। एसके 42-बी से एएलडब्ल्यूटी के ग्राउंड ड्रॉप परीक्षण भी पूरे कर लिए गए थे।

xvi. **सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो (स्मार्ट):** वर्ष के दौरान, यंत्रीकृत टीएएल डी एवं पी टॉरपीडो की सभी उप-प्रणालियों के साथ इसका संयोजन, एकीकरण और कार्यात्मक परीक्षण पूरा कर लिया गया और स्मार्ट मिसाइल के साथ इसका एकीकरण शुरू हो गया। डिजाइन की गई सभी महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों को विभिन्न भूमि परीक्षणों में सत्यापित किया गया है। छठे रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (आरटीआरएस) परीक्षण को भी फरवरी 2020 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

(आरटीआरएस) परीक्षण को भी फरवरी 2020 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया

xvii. **सहायक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स:** सहायक एक हल्का भार वाला एयर ड्रॉपपेबल कंटेनर है जो पैराशूट प्रणाली से लैस है जिसे मध्य समुद्र में संकटग्रस्त भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग स्टोर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सहायक कंटेनर नौसेना

की परिचालन लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाएंगे। वर्ष के दौरान, 6 सहायक प्रणालियों को भारतीय नौसेना को सुपुर्द करने के लिए तैयार किया गया था। भारतीय नौसेना ने जनवरी और मार्च 2019 में सहायक एयर ड्रॉपपेबल कंटेनरों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस प्रणाली को अगस्त, 2019 के दौरान विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सेनाओं में शामिल करने के लिए सौंप दिया गया है।

xviii. **मिग-29 अपग्रेड विमान (डी-29 प्रणाली) के लिए आंतरिक ईडब्ल्यू प्रणाली:** डी-29 चेतावनी और जैमिंग के लिए एक एकीकृत ईडब्ल्यू प्रणाली है जिसमें रडार चेतावनी रिसीवर (आरडब्ल्यूआर), इलेक्ट्रॉनिक संचार युक्ति (ईसीएम) और इलेक्ट्रॉनिक सहयोग युक्ति (ईएसएम) कार्य शामिल हैं और यह बहु खतरे वाले रडार को चयनित तौर पर जाम करने के लिए अत्याधुनिक सक्रिय चरणबद्ध प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। भारतीय वायुसेना की संतुष्टि के लिए बहु उत्सर्जक परिदृश्य में प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया गया है। उत्पादन के लिए इस प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय नौसेना के लिए 488 करोड़ रुपये की मूल्य वाली विनिर्माण एसडीआर-एनसी के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा संविदा पर हस्ताक्षर कर एसडीआर के स्वदेशी श्रृंखला उत्पादन में प्रमुख उपलब्धि हासिल की गई।

xix. **सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (एसडीआर):** डीआरडीओ ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) और वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग इस्टैबलिशमेंट (डब्ल्यूईएसईई) के साथ विकास भागीदारों के रूप में और बीईएल के साथ उत्पादन भागीदार के रूप में संघीय रूप से 5 रूप-कारकों में सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो विकसित किया हैं (नीचे दिए गए आंकड़े में विस्तृत):

डीएसी ने ₹1100 करोड़ की अनुमानित लागत से भारतीय नौसेना के लिए एसडीआर-टीएसी की खरीद को भी मंजूरी दे दी है, नौसेना डोर्नियर विमान पर एसडीआर-एआर की एक इकाई का अधिष्ठापन फरवरी 2020 में पूर्ण हो गया और स्थापित इकाई का परीक्षण प्रगति पर है।

xx. **सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए ऐरे रडार (एईएसएआर) 'उत्तम':** एईएसएआर 'उत्तम' हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए 'तेजस' के लिए एक वायुवाहित अग्नि नियंत्रण रडार है। रडार मूल्यांकन के लिए लगभग 100 उड़ान परीक्षणें की गई। स्वदेशी सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए ऐरे (एईएसए) रडार एकीकरण और एलसीए 'तेजस' एलएसपी-2 विमान पर ईएमआई/ ईएमसी परीक्षण पूरे हो गए और उड़ान मूल्यांकन हेतु लगभग 10 उड़ानें कार्यान्वित की गई।

xxi. नई संचालन प्रणाली (एएनयूओएस): इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में मौजूदा वाणिज्यिक और ओपन-सोर्स संचालन प्रणाली को सख्त करना और स्वदेशी विश्वसनीय संचालन प्रणाली (ओएस) कर्नेल का डिजाइन और प्रोटोटाइप तैयार करना शामिल है। अनुराग हार्डेन्ड लिनक्स (एएचएल) और अनुराग हार्डेन्ड विंडोज (एएचडब्ल्यू) को विकसित किया गया है एवं सुरक्षा संवेदनशील अनुप्रयोगों में तैनात किया गया है।

xxii. एमएमआईसीएस और जीएएन एचईएमटी प्रौद्योगिकी: अगस्त 2019 के दौरान, निसार उपग्रह के लिए मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट (एमएमआईसीएस) विकसित किए गए और इसरो को सुपुर्द किए गए। एस-बैंड 130 डब्ल्यू गैलियम नाइट्राइड हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर (जीएएन एचईएमटी) उपकरणों को भी विकसित किया गया और उपयोगकर्ताओं को सौंपा गया।

xxiii. वारगेमिंग सॉफ्टवेयर

डीआरडीओ का वारगेमिंग सॉफ्टवेयर

कॉर्पोरेट पहल

युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का निर्माण

प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी, 2020 को पांच डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (डीवाईएसएल) को राष्ट्र को समर्पित किया।

ये डीवाईएसएल हैं:

डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों, शामिल किए गए और किए जाने के लिए स्वीकृत दोनों का उत्पादन मूल्य ₹ 2.8 लाख करोड़ से अधिक है। डीआरडीओ द्वारा लगभग ₹ 8700 करोड़ की लागत से विकसित आठ प्रकार की प्रणालियों/उपकरणों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित की गई प्रमुख प्रणालियां, जिन्हें 2019 के दौरान शामिल करने के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की गई है, वे शामिल हैं:

मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड	मैकेनिकल माइनफील्ड उपकरण एमके-I	मैकनिकल माइन लेयर (एसपी)
एसडीआर (टीएसी)	इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अग्नि नियंत्रण प्रणाली	मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज़ आदि

डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित प्रमुख प्रणालियां

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों को शामिल करने और सशस्त्र बलों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सेनाओं के साथ नियमित बातचीत के लिए तंत्र स्थापित किए हैं, जिसे सचिव डीडी आर एंड डी और वायु सेना, सेना और नौसेना के चीफ/वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के बीच वार्षिक संयुक्त समीक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है; सेना के लाइन निदेशालयों के साथ त्रैमासिक बातचीत बैठकें (क्यूआईएम); वायु सेना के साथ त्रैमासिक प्रगति समीक्षा (क्यूपीआर); नौसेना के साथ वार्षिक सिनर्जी बैठकें (आईएन-डीआरडीओ) और सेना के लिए वीसीओएएस/डीसीओएएस स्तर पर द्विवार्षिक समीक्षाएं आयोजित की गईं। एक नई पहल की गई है और डीआरडीओ वैज्ञानिकों (>200 वैज्ञानिकों) के तीन बैचों ने भारतीय सेना इकाइयों/संरचनाओं के साथ इंटर्नशिप की है।

उद्योग इंटरफेस

रक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी (टीओटी) हस्तांतरण के लिए डीआरडीओ नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में टीओटी के लिए भारतीय उद्योगों और डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की सुविधा के लिए टीओटी शुल्क, रॉयल्टी, हैंडहोल्डिंग समर्थन आदि के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान, 114 नंबर के एलएटीओटी पर हस्ताक्षर किए गए। 71 उद्योगों ने विभिन्न उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए टीओटी लिया।

डीआरडीओ द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों विशेषकर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) लागू की गई है, जो सेना आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों की प्राप्ति के लिए नवाचार, अनुसंधान और विकास करने के लिए शिक्षाविदों या अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से काम कर सकते हैं।

वर्तमान में इस योजना के तहत 74 परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है, जिनमें से 65 को 2019 में जोड़ा गया है। कलाम के विजन 'डेयर टू ड्रीम' योजना के तहत रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचारों के लिए व्यक्तियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की योजना शुरू की गई है।

एक अखिल भारतीय 'डीआरडीओ इनोवेशन कॉन्टेस्ट' शुरू किया गया है और रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय नवप्रवर्तकों को पुरस्कारों का पहला सेट प्रदान किया गया।

कौशल, प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग देने के लिए फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी पहलुओं पर दिशानिर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी:

डीआरडीओ ने 11 राष्ट्रीय और 7 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

कुछ प्रमुख देशों के साथ निर्यात शुरू हो गया है और 2-3 मित्र देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

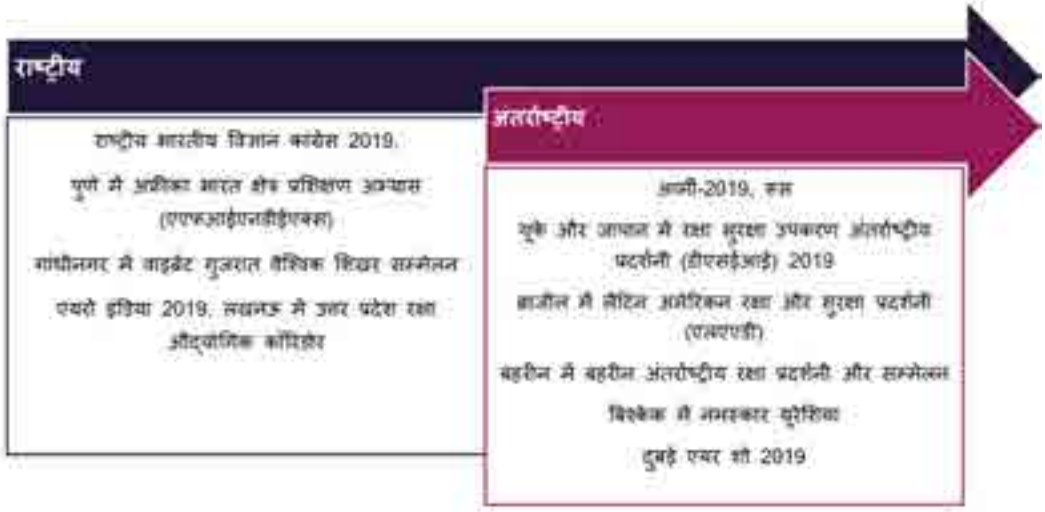

अकादमिक बातचीत

डीआरडीओ भारत भर में बनाए गए उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से रक्षा अनुप्रयोगों से संबंधित पहचाने गए अनुसंधान क्षेत्रों में निर्देशित अनुसंधान करने के लिए शिक्षाविदों को सहायता प्रदान करता है। आज की तारीख में 8 केंद्र संचालित हैं, जिनमें आईआईटी मद्रास में एडवांस सेंटर फॉर रिसर्च इन हाई एनर्जी मैटेरियल्स (एसीआरएचईएम), रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर (आरआईसी), जादवपुर विश्वविद्यालय में जेसी बोस सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी (जेसीबीसीएटी), आईआईटी-बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी (सीओपीटी) का द्वि-नोडल केंद्र, डीआरडीओ-आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (जेएटीसी) और भारतियार विश्वविद्यालय में डीआरडीओ-बीयू सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज शामिल हैं।

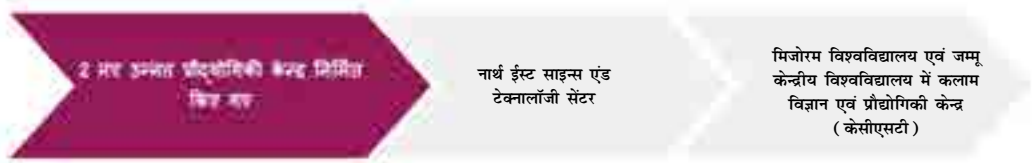

वर्ष में प्रयास

वर्तमान में, इन उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से ₹ 570.01 करोड़ की कुल लागत से 157 परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं। इसके अलावा, डीआरडीओ की एक्स्ट्रा म्यूरल (ईआर) पहल के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को ₹ 18.75 करोड़ की लागत वाली 19 परियोजनाएं मंजूर की गई और डीआरडीओ के तहत काम करने वाले चार अनुसंधान बोर्डों (एयरोनॉटिक्स, नौसेना, आयुध और जैव विज्ञान) के माध्यम से लगभग 81 शैक्षणिक संस्थानों को ₹ 49.34 करोड़ की कुल लागत से 99 परियोजनाएं मंजूर की गई।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के बीच आईपीआर जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास में, विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं में इस अवधि के दौरान एक उन्नत कार्यशाला और छह आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भारतीय उद्योगों द्वारा डीआरडीओ पेटेंट की सहज पहुंच के लिए डीआरडीओ नीति को रक्षा अनुसंधान एवं विकास सचिव द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई नीति के तहत, डीआरडीओ द्वारा आयोजित 460 भारतीय पेटेंट तक सहज पहुंच प्रदान की जाएगी, जिससे उद्योगों की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की संभावना है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण विभाग

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास और कल्याण

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) देश में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है।

कल्याण

1. केएसबी सचिवालय भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो युद्ध-विधवाओं/विकलांग सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

2. **राज्यों को वित्तीय सहायता:** राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों (आरएसबी/जेडएसबी) के स्थापना व्ययों के लिए विभाग द्वारा केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में फंडिंग पैटर्न 75:25 है, और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 60:40 है। केएसबी सचिवालय रक्षा सेवा अनुमान (डीएसई) बजट से सैनिक विश्राम गृहों (एसआरएच) के निर्माण की 50% लागत का साझा करता है। एसआरएच को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/निधियों से बनाए रखने की आवश्यकता होती है। 12 दिसंबर, 2019 तक केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को 22.25 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

3. **सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ):** भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण के लिए योजनाएं चलाने के लिए है। फंड को केएसबी द्वारा प्रशासित किया जाता है और फंड को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत छूट के लिए पात्र है। फंड को तीनों सेवाओं, कॉर्पोरेट, पीएसयू और व्यक्तिगत दानदाताओं से योगदान प्राप्त होता है। इस फंड में आईएनआर 305 करोड़ का कोष है और एएफएफडीएफ के कोष पर अर्जित होने वाली उपयोगी आय का एक हिस्सा रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) नामक योजना के तहत निर्धारित किया गया है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को देश भर में सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने के लिए मनाया जाता है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर, 2019 तक सप्ताह भर चलने वाले अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे टीवी स्पॉट का प्रसारण, मशहूर हस्तियों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संदेश, झंडा दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट/सोशल मीडिया का उपयोग।

7 दिसंबर 2019 को पीएम को एएफएफडी का झंडा लगाते हुए आरएसबी महाराष्ट्र के अधिकारी

4. 2 दिसंबर, 2019 को एक सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई) के सहयोग से किया गया था। 17 दिसंबर, 2019 तक 10.66 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई।

2 दिसम्बर, 2019 को मानेकशा सेंटर दिल्ली कैंट में डीएसआर कान्क्लेव में सशस्त्र सेना झंडा दिवस की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री

2 दिसम्बर, 2019 को मानेकशा सेंटर दिल्ली कैंट में डीएसआर कान्क्लेव में सशस्त्र सेना झंडा दिवस में मुख्य दान कर्ताओं को मदद करते हुए रक्षा मंत्री

5. **रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (आरएमईडब्ल्यूएफ) योजनाएं:** आरएमईडब्ल्यूएफ के तहत वित्तीय सहायता, जो एएफएफडीएफ का एक हिस्सा है, पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों की पहचानी गई व्यक्तिगत जरूरतों जैसे गरीबी अनुदान, बच्चों की शिक्षा और विवाह अनुदान, चिकित्सा अनुदान आदि के लिए प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 (30 नवंबर , 2019 तक) के दौरान आरएमईडब्ल्यूएफ के तहत पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के पक्ष में 19118 लाभर्थियों को आईएनआर 65.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का वितरण किया गया है। इनके अलावा, गंभीर बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1.81 करोड़ रुपये की राशि, विकलांगों के लिए संशोधित स्कूटर की खरीद और किरकी और मोहाली में वॉर मेमोरियल हॉस्टल और पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर को अनुदान भी एएफएफडीएफ के तहत दिया गया है।

6. **प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस):** इस योजना के तहत कुल 5500 छात्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय रक्षा कोष से पूर्व सैनिकों के वार्डों और विधवाओं को प्रदान की जाती हैं, (जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रशासित होती हैं) शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2,000/- प्रति माह से 2,500 रुपए प्रति माह और लड़कियों के लिए 2,250 रुपये प्रति माह से 3,000 रुपये प्रति माह रुपये से बढ़ा दी गई है और उनका सालाना भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 (12.12.2019 तक) के दौरान 9606 लाभर्थियों को 25.13 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

7. **मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सशस्त्र बल कार्मिक (सेवारत/ईएसएम) के बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा नामित (एमबीबीएस और बीडीएस) सीटों का कोटा बढ़ा दिया है। पात्र छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए केएसबी द्वारा कुल 35 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीटें आवंटित और वितरित की गई।

8. सरकारी फ्लैगशिप कार्यक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की भागीदारी

i) **स्वच्छता ही सेवा अभियान (एसएचएस)-2019** इस वर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और एकल उपयोग प्लास्टिक एसयूपी के प्रभावी प्रबंधन की थीम पर केंद्रित है। डीईएसडब्ल्यू ने 6 सितंबर, 2019 को उपरोक्त विषय पर सेंट्रल रेस्ट हाउस, नरैना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। क्षेत्रीय स्तर पर, सभी राज्य आरएसबी और जेडएसबी ने प्लास्टिक कचरा संग्रह श्रमदान और प्लास्टिक अपशिष्ट रीसाइक्लिंग तथा निपटान से संबंधित जागरूकता और सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए। अभियान में कुल 403 गांवों ने भाग लिया। 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस पूरे देश में प्लॉगिंग (जॉगिंग के दौरान कूड़े को उठाना) के लिए एक विशेष दिवस के रूप में मनाया गया।

ii) **जल शक्ति अभियान:** जल शक्ति अभियान की गतिविधियों को संचालित करने की कार्य योजना विभाग और इससे संबद्ध कार्यालयों के संबंध में तैयार की गई थी। प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) ने जल संरक्षण की अवधारणा को प्रचारित करने के लिए एक गांव को गोद लिया। इस विषय पर पोस्टर और अन्य सूचनात्मक सामग्री तैयार की गई थी जिसे व्यापक रूप से साझा किया गया है।

जल शक्ति अभियान: अगस्त 2019 में जेडएसबीओ में ईएसएम द्वारा तालाबों का पुनरोद्धार

iii) **सुगम्य भारत अभियान:** यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना विभाग द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत विभाग द्वारा तैयार की गई है कि संबंधित कार्यालयों, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सैनिक विश्राम गृहों की सभी इमारतों को विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) या दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है। मौजूदा भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग की नियमित निगरानी के साथ-साथ मौजूदा भवनों की पोस्ट रेट्रोफिटिंग सत्यापन ऑडिट की जा रही है।

iv) **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस:** 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2019 को सैनिक रेस्ट हाउस, नरैना , दिल्ली में मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारियों व पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों ने योग सत्र में भाग लिया।

v) 'रन फॉर यूनिटी' में पूर्व सैनिकों की भागीदारी: मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। 31 अक्टूबर, 2019 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को (राष्ट्रीय एकता दिवस) के रूप में मनाने के लिए आयोजन किया गया।

vi) इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस): केएसबी हेल्पलाइन [01126717987] के लिए आईवीआरएस 6 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था ताकि ईएसएम को तकनीकी प्रश्नों में सक्षम किया जा सके, ऑपरेटर तक आसान पहुंच हो, क्योंकि हेल्पलाइन पर अधिकांश प्रश्न आवेदनों की स्थिति के बारे में हैं। आईवीआरएस हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ 20 कॉल अटेंड कर सकता है और ईएसएम की शिकायत निवारण के लिए प्रतीक्षा समय को कम करेगा।

पुनर्वास

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) का मुख्य जोर पूर्व सैनिकों (ईएसएम) के पुनर्वास, पर्यावास और कल्याण पर है। हर साल लगभग 60,000 सशस्त्र बल के कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं या सक्रिय सेवा से मुक्त होते हैं, उनमें से ज्यादातर 35 से 45 वर्ष की उम्र से तुलनात्मक रूप से कम उम्र के होते हैं और उन्हें अपने परिवारों का सहयोग करने के लिए दूसरे करियर की आवश्यकता होती है। ये कर्मी राष्ट्र निर्माण के लिए उपलब्ध एक मूल्यवान, अनुशासित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, समर्पित और प्रतिभाशाली पूल का गठन करते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

अगस्त, 2016 से, डीजीआर केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संस्थानों, नियामक निकायों द्वारा संचालित संस्थानों/नियामक निकायों के साथ संबद्ध संस्थानों में पुनर्वास पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। आयोजित किए गए सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) स्तर -5 या

उससे ऊपर के हैं (सिवाय इसके कि जब व्यक्ति के लिए क्षेत्र में परिवर्तन शामिल हो, जहां यह स्तर -4 होगा)।

अधिकारियों का प्रशिक्षण: सरकारी संस्थानों/स्वायत्त संस्थानों में अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रमों की अवधि 2 सप्ताह से लेकर अधिकतम 24 सप्ताह तक भिन्न होती है। अधिकारियों के पाठ्यक्रम के लिए शुल्क सरकार और व्यक्तिगत अधिकारियों द्वारा 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।

जेसीओ/ओआर और समकक्ष प्रशिक्षण: डीजीआर जेसीओ/ओआर और उनके समकक्ष के लिए एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ये पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित किए जाते हैं और पाठ्यक्रम शुल्क का 100% सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिए गए प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है:

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	कार्मिकों की संख्या का ब्यौरा (15 दिसंबर, 2019 तक)
अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम	12	387
जेसीओ/ओआर के लिए पाठ्यक्रम	114	4385
कुल	**126**	**4772**

रोजगार के अवसर

ईएसएम के लिए केंद्र सरकार में रोजगार के अवसर: केंद्र सरकार ने ईएसएम के लिए उनके पुनर्वास के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया है जो इस प्रकार है:

सभी अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट के स्तर तक के पदों में रिक्तियों का 10%

केन्द्र सरकार के विभागों में समूह 'ग' ग्रुप सीधी भर्ती पदों के पदों का 10% समूह 'घ' सीधी भर्ती पदों में रिक्तियों का 20%

समूह 'ग' पदों में 14.5% रिक्तियों और समूह 'घ' पदों (4.5% दिव्यांग इएसएम/ कार्रवाई में मारे गये सैनिकों के आश्रितों के लिए) 24.5% रिक्तियां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षित है।

समूह 'ग' पदों में 14.5% रिक्तियों और समूह 'घ' पदों 24.5% रिक्तियां (4.5% दिव्यांग इएसएम/ कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए) सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में आरक्षित हैं।

रक्षा सुरक्षा कोर में 100%

रोजगार के लिए पंजीकरण : अवधि के दौरान डीजीआर और आरएसबी/ जेडएसबी के माध्यम से कुल 8793 (जनवरी-नवंबर 2019) और 16688 (जनवरी-जून 2019) कर्मियों को स्थायी/ संविदात्मक नौकरियों (स्वरोजगार योजनाओं को छोड़कर) के लिए प्रायोजित किया गया था।

सुरक्षा एजेंसी योजना: योजना का उद्देश्य ईएसएम द्वारा नौकरी मिलने तक किसी प्रकार की कमाई की सुविधा प्रदान करना है। वर्ष के दौरान कुल 870 सुरक्षा एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके द्वारा योजना के तहत 38398 ईएसएम को रोजगार प्रदान किया गया।

रक्षा मंत्री 21 नवंबर, 2019 को लखनऊ में पुनर्वास/प्लेसमेंट स्टाल का दौरा करते हुए

स्वरोजगार के लिए योजनाएं

डीजीआर के माध्यम से रोजगार के अवसर: डीजीआर अधिकारियों और जेसीओ/ओआर और समकक्ष और विधवाओं के लिए उनके रोजगार और कल्याण के लिए योजनाएं चलाता है। प्रमुख योजनाएं और उनके माध्यम से लाभार्थियों (अधिकारी/जेसीओ/ओआर/विधवा/विकलांग ईएसएम/आश्रित) की संख्या नीचे दी गई है:

योजना	लाभार्थियों की संख्या (1.1.2019 से 30.11.2019 तक)
कोयला परिवहन योजना एवं टिप्पर अटैचमेंट	166
मदर डेयरी दूध बूथ और फल और सब्जी (सफल) की दुकान	354
एनसीआर में ईएसएम (अधिकारी) द्वारा सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन	57
8% आरक्षण कोटा के तहत एलपीजी/रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) के आवंटन के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना	143
कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा संचालित खुदरा दुकानों का प्रबंधन	14

डीजीआर भूतपूर्व सैनिक नौकरी मेले : अगस्त 2014 में डीजीआर और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर, डीजीआर पूर्व सैनिक नौकरी मेले का आयोजन पैन इंडिया में तीनों सेवा मुख्यालयों के सहयोग से किया जा रहा है। 1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक की अवधि के दौरान कुल 7 डीजीआर पूर्व सैनिकों के जॉब फेयर का आयोजन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया है:

स्थान	दिनांक	सहभागिता		नौकरी की रिक्तियां (लगभग)
		निगमित नियोक्ताओं	ईएसएम	
कोलकाता	27 फरवरी, 2019	17	1924	3180
गोवा	15 मार्च, 2019	23	402	368
अहमदाबाद	23 अगस्त, 2019	31	1526	559
चंडीगढ़	11अक्टूबर, 2019	31	1090	2570
पुणे	16 अक्टूबर, 2019	29	856	2779
चेन्नई	22 नवम्बर, 2019	42	1438	2430
कोलकाता	29 नवंबर, 2019	41	1815	1192
	कुल	**214**	**9051**	**13078**

23 अगस्त, 2019 को अहमदाबाद में जॉब फेयर के उद्घाटन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री और सचिव, डीईएसडब्ल्यू

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

डीटीसी में मार्शल के रूप में रोजगार: दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मार्शल के रूप में रोजगार के लिए दिल्ली सरकार को कुल 998 भूतपूर्व सैनिक प्रदान किए गए हैं।

सीआईआई और एफआईसीसीआई के साथ समझौता ज्ञापन: डीजीआर ने 2014 में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और अक्टूबर, 2019 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से स्वीकृति प्राप्त की है ताकि कॉर्पोरेट क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सके।

स्वास्थ्य देखभाल

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस): ईसीएचएस का उद्देश्य ईएसएम और उनके आश्रितों को ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, सेवा चिकित्सा सुविधाओं और देश भर में फैले सिविल पैनलबद्ध/सरकारी अस्पतालों के एक नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों का उपयोग करके जहाँ तक संभव हो कैशलेस उपचार सुनिश्चित करने का प्रयास है। योजना के कुल लाभार्थी लगभग 55 लाख हैं।

ईसीएचएस नेटवर्क : दिल्ली में स्थित केंद्रीय संगठन , ईसीएचएस शीर्ष स्तर पर है। यह डीईएसडब्ल्यू के तहत एक संबद्ध कार्यालय है और इसका नेतृत्व एक सेवारत मेजर जनरल करता है। देश भर

में कुल 30 क्षेत्रीय केंद्र फैले हुए हैं। नेपाल में छह पॉलीक्लिनिक सहित कुल 433 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, ईसीएचएस के पैनल में 1964 सिविल अस्पताल हैं जो ईसीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराते हैं। इसकी पहुंच कश्मीर घाटी तक भी फैली हुई है। आपातकालीन स्थिति में, सदस्यों को भुगतान पर गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति है। उनके चिकित्सा उपचार बिलों की प्रतिपूर्ति अनुमोदित (सीजीएचएस) दरों पर की जाती है।

पिछले एक साल के दौरान उपलब्धियां

ईसीएचएस टोल-फ्री हेल्पलाइन : ईसीएचएस हेल्पलाइन को 23 सितंबर , 2019 से 24◦7 चालू कर दिया गया है। इससे पूर्व सैनिकों को चौबीसों घंटे अपनी समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी और ईसीएचएस के विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दो हेल्पलाइन नंबर 1800114115 और 011-25682870 हैं। ईसीएचएस के बारे में सभी जानकारी, जिसमें सूचीबद्ध सुविधाओं की सूची, सदस्यता के लिए प्रपत्र और नवीनतम नीतियां आदि शामिल हैं, वेबसाइट www-echs-gov-in पर उपलब्ध हैं।

सीओ ईसीएचएस ने ली शपथ - सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम करेंगे

जमीन के अधिग्रहण/खरीद की मंजूरी: वर्ष के दौरान चित्तौड़, एलुरु, (एपी), एलुरु, वीराराजेंद्रपेट, (कर्नाटक) और गीता कॉलोनी, शाहदरा (पूर्वी दिल्ली) के ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। इनके अलावा, वर्ष के दौरान गिद्दलूर गांव, आंध्र प्रदेश में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी भी जारी की गई थी।

क्षेत्रीय केंद्र और केंद्रीय संगठन में ईसीएचएस पदाधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन : क्षेत्रीय केंद्र और केंद्रीय संगठन में ईसीएचएस पदाधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए डीएफपीडीएस-2016 की शक्तियों की सेना अनुसूची (एएसपी)-2016 में एक अलग अनुसूची (अनुसूची-26) बनाई गई है। इसे 25 जुलाई, 2019 को जारी किया गया। ईसीएचएस के पदाधिकारियों को देरी को कम करने और ईसीएचएस के सुचारू कामकाज और अधिक रोगी संतुष्टि के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए 9 जुलाई, 2019 को आदेश जारी किए गए हैं।

आधुनिक दंत उपकरणों का प्राधिकार : 8 अगस्त, 2019 को ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए डीईएसडब्ल्यू द्वारा और अधिक आधुनिक दंत चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिकृत किया गया है।

75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता: सैन्य अस्पतालों के ईसीएचएस ओपीडी में ईसीएचएस सदस्यों एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों को प्राथमिकता देने के निर्देश 12 सितंबर 2019 को सभी कमान मुख्यालयों एवं क्षेत्रीय केंद्रीय संगठन को जारी कर दिए गए हैं.

घरेलू चिकित्सा उपकरण: 18 सितंबर, 2019 को ईसीएचएस लाभार्थियों को घरेलू चिकित्सा उपकरण प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए सैन्य अस्पताल के विशेषज्ञ के अलावा सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञों की सिफारिशों पर ईसीएचएस की अधिकतम दरें उपलब्ध हैं। पहले यह सैन्य अस्पताल के विशेषज्ञ की सलाह पर ही मुहैया कराया जाता था।

अस्पताल प्रक्रिया का पैनल बनाना: अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, बेहतर रोगी देखभाल का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सूचीबद्ध अस्पतालों के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए 10 अक्टूबर, 2019 को एक व्यापक और निष्पक्ष प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

ईसीएचएस में आयुष सुविधाएं: दिल्ली और एनसीआर के 5 पॉलीक्लिनिक में आयुष ओपीडी की शुरुआत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ईसीएचएस लाभार्थियों को आयुष के तहत उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना है - 6 नवंबर, 2019 को लोधी कॉलोनी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में पहली आयुष ओपीडी का संचालन किया गया।

निर्धारित चिकित्सा भत्ता : 19 नवंबर , 2019 को, नेपाल में रहने वाले ईसीएचएस सदस्यों को डीईएसडब्ल्यू द्वारा निर्धारित चिकित्सा भत्ता दिया गया है, जो उन जिलों में रह रहे हैं, जो ईसीएच पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र बल अस्पताल/उन्नत एमआई रूम में शामिल नहीं हैं।

पेंशन सुधार

विशेष पारिवारिक पेंशन (एसएफपी)/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (एलएफपी): 8 जुलाई, 2019 को यह निर्णय लिया गया है कि विशेष पारिवारिक पेंशन (एसएफपी)/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (एलएफपी), यदि कोई हो, रक्षा मंत्रालय के दिनांकित पत्र के अनुसार स्वीकार्य होगी। 31 जनवरी, 2001 पेंशनभोगी की मृत्यु पर, जिसे सैन्य सेवा में फिर से नियोजित किया गया था और यदि उसकी मृत्यु अन्य शर्तों के अधीन पिछली सैन्य / सिविल सेवा के संबंध में साधारण पारिवारिक पेंशन के अलावा सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है।

शिकायत निवारण प्रणाली: ईएसएम/पेंशनभोगियों की शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए विभाग के पास एक समर्पित पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ है, जिसके परिणामस्वरूप शिकायत निवारण प्रणाली बेहतर हुई है। शिकायतों के निपटान का कुल प्रतिशत 97% है और डेटा pgportal.gov.in पर उपलब्ध है। यह गहन अनुवर्ती कार्रवाई, संबंधित कार्यालयों के साथ नियमित बातचीत के साथ-साथ साप्ताहिक समीक्षा के कारण हासिल किया गया है। शिकायतों के समाधान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए 30 दिनों की छोटी समय-सीमा के साथ-साथ उपर्युक्त पहलों के प्रभाव के परिणामस्वरूप औसत निपटान समय 2014 में 87 दिनों से घटकर 2018 में 25 दिन हो गया और इसे और 2019 में घटाकर 21 दिन कर दिया गया। उपरोक्त किए गए प्रयास शिकायतों को कम करने, निपटान के समय को कम करने, हमारे पूर्व सैनिकों के साथ संवाद और बातचीत को बढ़ावा देने के साथ-साथ ईएसएम की शिकायतों को हल करने के लिए आरएसबी/जेडएसबी को संवेदनशील बनाने के हमारे ठोस प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

100 दिन का एजेंडा और विभाग की वार्षिक कार्य योजना: विभाग से संबंधित अगले पांच वर्षों के लिए एक विजन, मिशन, 100 दिवसीय एजेंडा और कार्य योजना दस्तावेज को 19 जुलाई, 2019 को रक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। पुरुषों और महिलाओं के पुनर्वास, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अधिक प्रभावी नीति, सेवाओं और संस्थागत ढांचे का विकास करना, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में सक्रिय सेवा छोड़ने के बाद सेवा की और यह प्रदर्शित करने के लिए कि उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्र सशस्त्र बलों की देखरेख करता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से 100 दिनों के एजेंडे और वार्षिक कार्य योजना की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है। कैबिनेट सचिव अ.शा. पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2019 के अनुसार 100 दिनों के एजेंडे की सभी मदों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

***

महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE

महिलाओं का सशक्तीकरण और कल्याण

राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। महिलाओं को रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किया गया है। उड़ान, संभारगी और विधि जैसे सशस्त्र सेना के विविध ब्रांचों में महिलाओं की नियुक्ति के साथ उनके लिए बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है।

भारतीय सेना

सेना में महिलाओं की नियुक्ति, प्रवेश और रोजगार संबंधी नीति फरवरी, 2019 में घोषित की गई है, जिसमें निम्नलिखित परिकल्पनाएं की गई हैं:-

(क) महिला अफसरों के स्थायी आयोग: जेएजी और एईसी की दो स्ट्रीमों के अलावा आठ शस्त्रों एवं सेनाओं नामत: सिग्नल, इंजीनियर, सेना विमानन, एएडी ईएमई, एएससी, एओसी और अंतरिम कोर में महिला अफसरों के लिए स्थायी आयोग (पीसी) के अनुमोदन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है (मुकदमा-सिविल अपील सं. 9367-9369 से 2011 शीर्षक सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबिता पुनिया एवं संगठन)

(ख) सैन्य पुलिस के कोर में सिपाही के रूप में महिलाएं : रक्षा मंत्री ने 22 जनवरी, 2019 को सैन्य पुलिस में सिपाही के रूप में महिलाओं की भर्ती को अनुमोदन प्रदान किया है। यह परिकल्पना की जाती है कि सैन्य पुलिस कार्मिक में महिला सैन्य पुलिस की प्रतिकार विद्रोह परिस्थिति, समारोह दायित्व और भीड़-भाड़ नियंत्रण एवं महिलाएं और बच्चे शामिल

अपराधों की जांच-पड़ताल जैसे पुलिस दायित्वों में भूमिका होगी। पदोन्नति, वेतन एवं भत्ते जैसी सेवा के सभी शर्तों और निबंधनों पुरूष सैन्य पुलिस कार्मिक के समान होंगे। 17 वर्षों में चरणबद्ध तरीके में कुल 1700 महिला पुलिस कार्मिक अर्थात प्रतिवर्ष 100% की भर्ती की जाएगी 17 वर्ष के अंत में सैन्य पुलिस में महिलाएं संवर्ग के 20% होगी। वर्ष 2019-20 के लिए भर्ती पूरी हो चुकी है और 101 महिलाओं के प्रथम बैच 6, 2020 से प्रशिक्षण ले रहे हैं। बैच मार्च 2021 में प्रशिक्षाण के 62 हफ्तों के बाद पास-आउट होने की संभावना है।

भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना महिलाओं के कल्याण, समग्र हित और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। हर समय उच्च मनोबल और प्रेरणा बनाए रखने के लिए महिला कर्मचारियों और महिला परिवार के सदस्यों को अधिकतम सहायता प्रदान करना भारतीय नौसेना का निरंतर प्रयास है। भारतीय नौसेना ने महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण और संबंधित इकाइयों में गतिविधियों/कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन प्रयास किए हैं। महिला कर्मचारियों के लिए महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं:

महिला कर्मचारियों के लिए महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उपाय

(क) **एसएससी अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग:** कार्यकारी शाखा (कानून संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना वास्तुकला) के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अल्प कालीन सेवा आयोग के अधिकारियों को 2008 से स्थायी आयोग की स्वीकृति की शुरुआत।

(ख) **महिला पायलट:** भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट को 2 दिसंबर, 2019 को 7वें डोर्नियर कन्वर्जन कोर्स के पासिंग आउट के दौरान प्रतिष्ठित एविएटर विंग्स से सम्मानित किया गया।

भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट को 'विंग्स' का पुरस्कार

i) **विशाखा और निर्भया अधिनियम:** ''विशाखा दिशानिर्देश'' और ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013'' मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सभी कमानों और बाहरी इकाइयों में लागू किए गए हैं। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए तीनों कमानों में समितियों का गठन किया गया है।

ii) **नेवल वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (एनडब्ल्यूडब्ल्यूए):** नौसेना की महिलाओं के आत्मविश्वास को विकसित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में गतिविधियाँ और असंख्य कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर आयोजित किए गए हैं।

iii) **नेवल रेजिमेंटल सिस्टम (एनआरएस):** एनआरएस की स्थापना जनवरी 2011 में सपोर्ट सिस्टम को संस्थागत बनाने और मृतक नाविकों की विधवाओं/ निकटवर्ती को सक्रिय और विस्तारित सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

iv) विधवाओं और सेवानिवृत्त समूह तक पहुंचना: उनके कल्याण को प्रभावित करने वाले मुद्दों के शीघ्र समाधान की सुविधा के लिए निम्नलिखित की स्थापना की गई है:

v) **दिल्ली में विधवाओं का छात्रावास:** नौसेना विधवाओं/ वीरनारियों के कल्याण के लिए भारतीय नौसेना द्वारा सहारा हॉस्टल अद्वितीय और अपनी तरह की पहली पहल है और इसका

उद्देश्य महिलाओं और उनके परिवारों को उनके पति के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद की अवधि में सहायता प्रदान करना है। इसमें 34 सुसज्जित आवासीय इकाइयां शामिल हैं। इस सुविधा का उद्घाटन 24 मई, 2019 को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा किया गया था।

सहारा हॉस्टल, नई दिल्ली का उद्घाटन

vi) **माउंट सतोपंथ पर अभियान:** माउंट सतोपंथ पर उत्तराखंड में 7075 मीटर की चोटी पर्वतारोहण अभियान, का आयोजन 22 सितंबर से 16 अक्टूबर, 2019 तक किया गया था। अभियान दल में 13 नौसेना कर्मी शामिल थे, जिनमें आठ अधिकारी (सात महिला अधिकारी और एक पुरुष अधिकारी) और पांच नाविक शामिल थे।। यह भारतीय नौसेना द्वारा किया गया दूसरा बड़ा अभियान था जिसमें अधिकांश पर्वतारोही महिला अधिकारी थीं। टीम प्रतिकूल मौसम के कारण शिखर पर नहीं पहुंच सकी लेकिन इस अभियान के दौरान 6500 मीटर की ऊंचाई हासिल की।

vii) **स्वास्थ्य क्लीनिक-महिलाएं:** एनडब्ल्यूडब्ल्यूए के आरोग्य विंग के तत्वावधान में पूरे वर्ष विभिन्न आईएन इकाइयों में विभिन्न स्वास्थ्य क्लीनिकों का संचालन किया गया। इन आयोजनों का उद्देश्य नौसेना कर्मियों की पत्नियों को सकारात्मक महिलाओं के स्वास्थ्य के गुणों के प्रति संवेदनशील बनाना और इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना था।

सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप

स्वास्थ्य महिला स्क्रीनिंग स्वास्थ्य कैंप

भारतीय वायु सेना

i) **फाइटर स्ट्रीम में महिला पायलटों को शामिल करना:** आईएएफ के ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में महिला पायलटों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। एक स्वाभाविक प्रगति के रूप में, आईएएफ ने महिला पायलटों को मांग वाली फाइटर स्ट्रीम में भी शामिल करने का निर्णय लिया। तदनुसार, तीन महिला प्रशिक्षुओं के पहले बैच को फाइटर स्ट्रीम के लिए शामिल किया गया था। इनमें से छह लड़ाकू स्क्वाड्रन में तैनात हैं और दो हॉक-132 विमान पर कमीशनिंग के बाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक और महिला प्रशिक्षु को फाइटर स्ट्रीम आवंटित की गई है और दिसंबर 2019 में कमीशन दी जाएगी।

ii) **शॉर्ट सर्विस कमीशन टू परमानेंट कमीशनः** 15 अगस्त, 2018 को प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के दिनांक 25 अगस्त, 2018 डायरी सं. 1796/रक्षा (वायुसेना-III)/2018 के माध्यम से सरकार की मंजूरी के बाद, स्थायी आयोग (पीसी) के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों (एसएससीओ) के विचार को सक्षम करने के लिए आवश्यक वायु मुख्यालय मानव संसाधन नीतियां (एचआरपी) आईएएफ तैयार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा है। ये एचआरपी जो महिला व पुरूष दोनों के लिए समान हैं, औपचारिक रूप से फ्लाइंग शाखा के लिए 7 दिसंबर, 2018 को और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए 16 जनवरी, 2019 को घोषित किए गए थे। इसके बाद, सभी सेवारत एसएससी अधिकारियों (जेंडर का ध्यान दिए बिना) को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जा रहा है। फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं की कुल 26 महिला एसएससी अधिकारियों को जून 2018 से जून 2019 तक स्थायी कमीशन दिया गया है।

iii) **राजनयिक कार्य के लिए महिला अधिकारी का नामांकन :** विदेशों में भारतीय मिशन पर राजनयिक पदों पर पारंपरिक रूप से पुरुष अधिकारी कार्यरत होते हैं। विंग कमांडर अंजलि सिंह पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें आईएएफ द्वारा रूस के दूतावास में उप वायु संलग्नक (Dy Air Attaché) के रूप में नामित किया गया है।

iv) **कमांडर के रूप में महिला अधिकारी की नियुक्ति :** विंग कमांडर शालिजा धामी को दिसंबर 2003 में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। उन्हें दिसंबर 2018 में पीसी प्रदान किया गया। वह नवंबर, 2013 में भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला क्यूएफआई बनी। उन्होंने 2000 घंटे से अधिक उड़ान किया है उन्हें हाल ही में आईएएफ की एक कॉम्बैट यूनिट (131 एफएसी फलीट, 26 अगस्त, 2019 से प्रभावी) हिंडन की पहली महिला फ्लाइट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है।

कॉकपिट में आईएएफ महिला पायलट

भारतीय तट रक्षक

महिला अधिकारियों को डोमेन विशेषज्ञता से संबंधित कर्तव्यों को आवंटित करके अपने पेशेवर कौशल को सुधारने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। संभारगी प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों को तटरक्षक स्टोर डिपो के प्रभारी अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया जाता है, जो मुख्य रूप से सूची प्रबंधन और तटरक्षक बल की सभी फ्रंटलाइन इकाइयों और बेसों को संभारगी सहायता प्रदान करते हैं। महिला अधिकारियों को विशिष्ट संभारगी कर्तव्यों के अलावा आईसीजी के लिए विशिष्ट परिचालन भूमिकाओं में भी नियुक्त किया गया है जिसमें पायलट, पर्यवेक्षक, विमानन सहायता सेवाएं और एसीवी ऑपरेटर शामिल हैं।

रक्षा विभाग

महिलाओं के लिए एनसीसी विशेष प्रवेश: एनसीसी विशेष प्रवेश को पहली बार 'सी' प्रमाणपत्र वाली महिला एयर विंग कैडेटों के लिए बढ़ाया गया है। यह उन्हें भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी बनने के लिए बिना किसी स्क्रीनिंग टेस्ट के सीधे एसएसबी में जाने में सक्षम करेगा।

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ)

डीआरडीओ एक नियोक्ता के रूप में महिला कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियम 2013 के अनुसार, डीआरडीओ यह सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारियों को उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने और उनकी क्षमता की पूर्ति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। इसके परिणामस्वरूप कई महिला वैज्ञानिक डीआरडीओ में उच्च पदों पर पहुंची हैं और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (एसएचई बॉक्स) लागू की गई थी और इसके संचालन के लिए सभी प्रयोगशालाओं/ प्रतिष्ठानों ने अपना यूजर-आईडी बनाया है।

डीआरडीओ हर साल राष्ट्रीय स्तर पर ''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' मनाता है। मार्च 2019 में, **''स्टीयर एज मैनेजर, इनोवेटर, लीडर, एंटरप्रेन्योर एंड साइंटिस्ट (एसएमआईएलईएस)''** शीर्षक से एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एआरडीई पुणे में आयोजित की गई थी , जहाँ विभिन्न प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों से 170 से अधिक महिला वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, अधिकारी और कर्मचारी डीआरडीओ ने भाग लिया।

रक्षा उत्पादन विभाग

i) **आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी):** आयुध निर्माणियों में 6123 महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण के लिए कार्यस्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। किसी भी महिला कर्मचारी की यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तंत्र मौजूद है।

ii) **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल):** एचएएल सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं (डब्ल्यूआईपीएस) फोरम की एक कॉर्पोरेट लाईफ सदस्य है और डब्ल्यूआईपीएस फोरम के कार्यक्रमों /गतिविधियों में भाग लेने के अवसर महिला कर्मचारियों को दिए जाते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए सभी वैधानिक कल्याण सुविधाओं का विस्तार किया गया है। एचएएल में 2301 महिला कर्मचारी हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार मंडलों/कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

iii) **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल):** बीईएल लैंगिक विविधता और महिला सशक्तीकरण में विश्वास करती है। भर्ती, कैरियर की प्रगति, लर्निंग और विकास, कल्याणकारी उपायों आदि में उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं ने महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों (1 कार्यात्मक निदेशक, 1 कार्यकारी निदेशक और 5 महाप्रबंधक) को ग्रहण किया है।

iv) **बीईएमएल लिमिटेड:** बीईएमएल एक समान अवसर नियोक्ता है, जिससे पूरे संगठन में महिला कर्मचारियों/कार्यकारियों के लिए कार्य का अनुकूल वातावरण तैयार होता है। महिला कर्मचारियों/अधिकारियों की कुल संख्या 255 है।

v) **भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल):** 1 दिसंबर, 2019 तक बीडीएल में 311 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कुल कार्यबल का 10.57% है। कंपनी ने अपने स्थायी आदेशों, सीडीए नियमों में संशोधन किया और ''कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न का निषेध'' पर एक अध्याय शामिल किया।

vi) **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई):** जीआरएसई में महिला कर्मचारियों की संख्या 101 है जो कंपनी की कुल संख्या का लगभग 5% है।

vii) **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल):** सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त करने के लिए महिला कार्यबल के लिए प्रख्यापित विभिन्न दिशानिर्देशों का जीएसएल ने सख्त अनुपालन किया है। एक महिला प्रकोष्ठ भी बनाया गया है जो जीएसएल की महिला कर्मचारियों के विकास और विकास के पोषण के लिए एक उत्तरदायी मंच के रूप में कार्य करता है। सभी संवर्गों में महिला कर्मचारियों के समग्र विकास के लिए नियमित जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जीएसएल में 153 महिला कर्मचारी हैं।

viii) **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल):** महिला कर्मचारियों के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण, कौशल विकास और कार्य स्थल पर कल्याण सुविधाओं के प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन आदि के लिए पांच महिला अधिकारियों के साथ एक ''जेंडर बजटिंग एंड वीमेन इन पब्लिक सेक्टर सेल'' का गठन किया गया है। और उनके कैरियर प्रबंधन और समग्र व्यक्तित्व विकास में महिला कर्मचारियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भी एचएसएल महिला कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दे रहा है और महिला कर्मचारियों को उनके निर्णय लेने के कौशल और आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने के समान अवसर दिए जाते हैं। एचएसएल में वर्तमान में 36 महिला कर्मचारी हैं।

ix) **मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल):** एमडीएल में 182 महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर अर्थात नेतृत्व, सॉफ्ट स्किल और तकनीकी प्रशिक्षण दोनों आउटबाउंड और इन-हाउस 416 मानव-दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।। महिला कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं के फोरम (डब्ल्यूआईपीएस) की सदस्य हैं। एमडीएल ने 2019-20 के दौरान 65 शिक्षुओं को विभिन्न ट्रेडों में कौशल वृद्धि के लिए अप्रेंटिसशिप भी प्रदान की।

x) मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी): महिला विकास के लिए 15 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 80 महिला कर्मचारी शामिल थीं। विषय थे: वित्तीय योजना, कार्यकारी विकास, महिला अधिकारिता, दृष्टिकोण प्रबंधन, कार्य जीवन और सामान्य जीवन संतुलन, नेतृत्व कौशल, कार्य संस्कृति का परिवर्तन, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक नियंत्रण, संचार कौशल, परिवर्तन प्रबंधन, योग चिकित्सा और ध्यान तकनीक, प्रबंधकीय प्रभावशीलता , महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता, वित्तीय लक्ष्य, नेतृत्व विकास।

xi) **गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए):** महिला सशक्तीकरण और कल्याण के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नीतियों के अनुसार सभी अवसर और लाभ प्रदान किए जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू)

डीईएसडब्ल्यू सशस्त्र बलों के कर्मियों की विधवाओं और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों सहित लगभग 32 लाख पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण से संबंधित है। विभिन्न योजनाओं के तहत बालिकाओं व महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) सचिवालय शिक्षा, ईएसएम की बेटियों की शादी और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ईएसएम की विधवाएं पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के तहत पुनर्वास प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। ईएसएम की विधवाओं की कुछ श्रेणियों को कोयला टिपर योजना, तेल उत्पाद एजेंसियां, सफल बूथ आदि जैसी कई डीजीआर रोजगार योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है।

युद्ध विधवाओं को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत योगदान के भुगतान से छूट दी गई है।

सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में भूतपूर्व महिला सैनिकों की संख्या भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के दायरे और कार्यप्रणाली में एक नया आयाम जोड़ेगी। उनके प्रोफाइल और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्रिय सेवा से चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत/बाहर किए जाने वाले महिलाओं के लिए महिला उन्मुख पुनर्वास/ कल्याण योजनाओं का पता लगाया जा रहा है।

***